20 _B, 2020 (Aàb-_B g`ŠV{H$) ❋ df-29, nîR g»`m 60, AH$-4-5

राजस्थान सुजस

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

Rajiv@75

छाया : सुजस

मुख्यमंत्री ने किया शहादत को नमन

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 5 मई को यहां 61 कैवलरी ग्राउंड जाकर शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा की पार्थिव देह पर पुष्पचक्र अर्पित किया और दो मिनट का मौन रखकर शहीद को श्रद्धांजलि दी। शहीद की पार्थिव देह अंतिम दर्शन के लिए 61 कैवलरी ग्राउंड में रखी गई थी।

श्री गहलोत ने जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में शहीद हुए कर्नल आशुतोष शर्मा की वीरांगना, पुत्री एवं भाई से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने शहीद की मां के पैर छूकर उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने कर्नल आशुतोष की शहादत को नमन करते हुए कहा कि राजस्थान वीरों की धरती है। कर्नल आशुतोष ने आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए शहीद होकर देश को गौरवान्वित किया है। हम सभी को उनकी शहादत पर नाज है।

सैनिक कल्याण मंत्री श्री प्रतापसिंह खाचरियावास एवं कृषि मंत्री श्री लालचंद कटारिया सहित सेना एवं प्रशासन के अधिकारियों ने भी शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की।

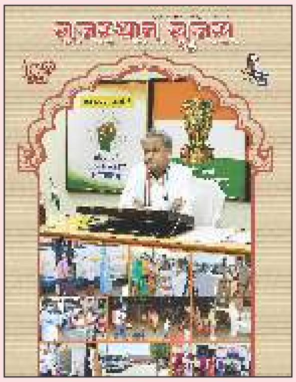

प्रधान सम्पादक
महेन्द्र सोनी, आईएएस
आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क

सम्पादक
डॉ. राजेश कुमार व्यास

उप सम्पादक
आशाराम खटीक

कला
विनोद कुमार शर्मा

आवरण छाया
सुजस

राजस्थान सुजस में प्रकाशित सामग्री में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं एवं आंकड़े परिवर्तनशील हैं। आवश्यक नहीं कि शासन उनसे सहमत हो। सुजस में प्रकाशित सामग्री का विभाग किसी भी रूप में उपयोग कर सकेगा।

ग्राफिक डिजाइनिंग
पॉपुलर प्रिन्टर्स, जयपुर

सम्पर्क
सम्पादक
राजस्थान सुजस (मासिक)
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
सचिवालय परिसर
जयपुर - 302 005

e-mail :
publication.dipr@rajasthan.gov.in
editorsujas@gmail.com

Website :
www.dipr.rajasthan.gov.in

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान का मासिक

वर्ष : 29 अंक : 4-5 20 मई, 2020 (अप्रैल-मई संयुक्तांक)

इस अंक में

कोरोना से जीतेगा राजस्थान

06 ....

कुशल नेतृत्व से ....

20 ....

इंदिरा प्रियदर्शिनी बेबी किट..

51 ....

सम्पादकीय	04
शिक्षा में नवीन तकनीक....	05
चिकित्सा मंत्री ने किया टेली कंसलटिंग पोर्टल..	19
पैडल हैन्ड सैनेटाइज मशीन लगाई	23
लॉकडाउन के दौरान 10 लाख परिवारों को...	29
हर कोई कर रहा है मुक्तकंठ से प्रशंसा	30
रक्षक, सेवक और योद्धा भी...	31
ऑनलाइन होगी भविष्य की शिक्षा	32
ऑनलाइन पढ़ाई में आंखों की देखभाल...	33
युद्ध से ज्यादा खतरनाक रही है....	34
राजस्थान की पहल से देशभर को मिला लाभ	36
दक्षिणांचल की आदि परम्परा में शामिल है...	39
कोरोनाकाल में कला एवं संस्कृति	40
दरिद्रनारायण की उपासना	42
विधानसभा सत्र जैसा दिखा नजारा	44
प्रदेश में बनेगा लेबर एम्पलॉयमेंट एक्सचेंज	46
समय पर पूरी हो भर्तियां-मुख्यमंत्री	47
प्रवासियों को नहीं हो कोई असुविधा	48
कोरोना के डर से बीमारी को नहीं छुपाएं	49
मुख्यमंत्री ने दी सहायक रेडियोग्राफर....	49
आरटीई की आय सीमा अब ढाई लाख	50
राजस्थान के प्रवासियों को महाराष्ट्र से लेकर....	52
प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए प्रयासों...	53
दिल्ली की डाक	54
पढ़ा रहे सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ	55
सहजना - पैसों का पेड़	58

कुशल प्रबन्धन एवं बेहतर....

.... 14

सरकार का हाथ अन्नदाता....

.... 24

कौल्वी की गुफाएं.......

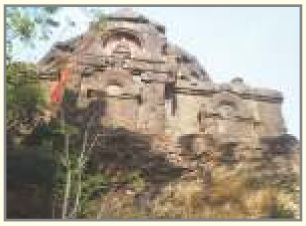

.... 56

राजस्थान सुजस के आगामी अंक के लिए मौलिक, अप्रकाशित सामग्री भिजवायें। कृपया अपने आलेख एवं फोटोग्राफ सम्पादक को e-mail : editorsujas@gmail.com पर अथवा डाक से भेजें।

सतर्क रहते किए उल्लेखनीय प्रयास

कोरोना वायरस की महामारी से इस समय पूरा विश्व त्रस्त है। यह सही है, आज पूरा देश इस महामारी की चपेट में है परन्तु इसने हमारे स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत बनाने की भी सीख हमें दी है। राजस्थान के चारों ओर के राज्य दिल्ली, पंजाब, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, गुजरात आदि में कोरोना संक्रमण वृहद् पैमाने पर फैला हुआ था। ऐसे में आरंभ से ही इस महामारी का यह प्रदेश बड़ा केन्द्र हो सकता था परन्तु मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के कुशल नेतृत्व और प्रबंधन की सूक्ष्म सूझ से राज्य में तेजी से महामारी नियंत्रण के विभिन्न स्तरों पर कार्य किए गए।

राज्य में 19 मई तक 2.55 लाख से अधिक सैम्पल लिये गये हैं। राजस्थान में अन्य राज्यों के मुकाबले अधिक टेस्ट हो रहे है। जरूरत इस बात की भी है कि कोरोना या अन्य किसी भी बीमारी को छुपाने की बजाय तुरंत उसकी जांच कराएं और उपचार लें। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर लॉकडाउन के दौरान 'कोई भूखा नहीं सोए' इस संकल्प के साथ जरूरतमंदों को राशन सामग्री एवं भोजन के पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 78 लाख लाभार्थियों को दो माह की पेंशन के रूप में 1400 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान किया है। करीब 33 लाख असहाय एवं निराश्रितों, स्टेट बीपीएल एवं अन्य जरूरतमंदों को 2500-2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों को 2 माह तक 10 किलो गेहूं निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा 54 लाख ऐसे लोग जो एनएफएसए में कवर नहीं होते उन्हें राज्य सरकार एफसीआई से 21 रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं खरीदकर प्रति व्यक्ति 10 किलो गेहूं निःशुल्क उपलब्ध करवा रही है।

प्रदेश में किसानों को राहत प्रदान करने के लिए भी कोरोना के इस संकट के दौर में महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकार ने किए हैं। किसानों को फसल का बेहतर मूल्य दिलाने, खरीद के लिए सुगम एवं विकेन्द्रीकृत व्यवस्था करने और उपज को रहन में रहकर कम से कम ब्याज दर पर ऋण उपलबध कराने जैसे महत्त्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है। लम्बे लॉकडाउन के कारण पैदा हुई बेरोजगारी की स्थितियों को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने 'ऑनलाइन लेबर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज' बनाने और 'प्रवासी राजस्थानी श्रमिक कल्याण कोष' गठित करने को मंजूरी दी है। लॉकडाउन के कारण संकट का सामना करने वाले श्रमिकों को उनके कौशल के अनुरूप रोजगार दिए जाने के साथ ही उद्योगों को उनकी जरुरत के मुताबिक श्रमिक इससे उपलब्ध हो सकेंगे।

मुख्यमंत्री जी की पहल पर शिक्षक, अभिभावकों और विद्यार्थियों के हित में समयानुरूप महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गये। शिक्षा विभाग द्वारा ऑनलाइन शिक्षण को भी प्रभावी रूप में सुनिश्चित करते हुए 'प्रोजेक्ट स्माइल' की शुरुआत की गयी। मुख्यमंत्री जी ने नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार के तहत राज्य के गैर सरकारी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटों पर दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के नि:शुल्क प्रवेश के लिए अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा एक लाख के स्थान पर ढाई लाख रुपये करने को मंजूरी दी है।

कोरोना के मुकाबले में जुटे कोरोना वॉरियर्स यथा डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, प्रशासन, पुलिस, सेनिटेशन वर्कर, राजस्व, ग्रामीण विकास, शिक्षा विभाग व अन्य सभी विभागों के कार्मिक, सामाजिक संगठन व भामाशाहों का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।

महेन्द्र सोनी
आई.ए.एस.
आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क

शिक्षा में नवीन तकनीक का प्रयोग समय की आवश्यकता

राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री कलराज मिश्र ने कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हासिल करने के लिए नवीन तकनीक का उपयोग करना आज की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के इस दौर में उच्च शिक्षा पर आये प्रभाव से निपटने के लिए विश्वविद्यालयों को उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग एकजुटता से करना होगा। श्री मिश्र का मानना है कि शैक्षणिक उत्थान के लिए इस समय के परिवर्तनों का अध्ययन और योजनाबद्ध तरीके से चुनौतियों का मुकाबला करना होगा।

राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालयों में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा नये तरीके से देना अब हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों से उच्च शिक्षा पर आये प्रभावों से विद्यार्थियों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने देंगे।

राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री मिश्र राजभवन से वीडियो क्रॉन्फ्रेंस के द्वारा राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से उच्च शिक्षा पर चर्चा कर रहे थे। राज्यपाल ने उनके द्वारा गठित टास्क फोर्स की अनुशंषाओं पर कुलपतियों से चर्चा की। कुलपतियों ने कहा कि इन अनुशंषाओं को सम्बन्धित कमेटियों में चर्चा कराकर विश्वविद्यालयों में अनुपालन कराया जायेगा ताकि विद्यार्थियों को नुकसान से बचाया जा सके। राज्यपाल ने इसके साथ ही पाठ्यक्रम के अद्यतन, स्टेट यूनिवर्सिटी मैनेजमेन्ट सिस्टम, लर्निंग मैनेजमेन्ट सिस्टम और स्मार्ट विलेज में लोगों को दिये जाने वाले मास्क, सेनेटाइजर और राशन सामग्री के बारे में जानकारी ली।

राज्यपाल ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के लॉकडाउन का असर उच्च शिक्षा पर पड़ा है। उन्होंने कहा कि हमें विद्यार्थियों की जरूरतों को देखना होगा, समझना होगा और उन्हें पूरा करने का भरसक प्रयास भी करना होगा। कुलाधिपति श्री मिश्र ने कहा कि एक अनुमान के अनुसार कोविड-19 से 1.5 बिलियन युवा प्रभावित हुए हैं। इस राष्ट्रव्यापी बन्द ने दुनिया की 91 प्रतिशत छात्र आबादी पर असर डाला है।

लॉकडाउन में नियमों का पालन दृढ़ता से करें

राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने प्रदेशवासियों से कोरोना वैश्विक महामारी से बचाव के लिए लॉकडाउन की पूरी तरह से पालना किए जाने का आह्वान करते हुए निर्धारित नियमों का पालन किए जाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सामाजिक दूरी को बनाये रखें। कोरोना से लड़ने के लिए यह अति आवश्यक है। कोविड-19 के विभिन्न फेजों में नियमों का पालन अवश्य करें, यह महत्त्वपूर्ण है।

राज्यपाल ने लोगों से अनुरोध किया है कि घर पर रहें, सावधानी से रहें और स्वस्थ रहें। श्री मिश्र ने कहा कि इसी में सभी की भलाई है। इसी में सभी का कल्याण है। उन्होंने कहा कि इस माध्यम से ही कोरोना जैसी महामारी का जबरदस्त तरीके से मुकाबला किया जा सकता है।

कोरोना से जीतेगा राजस्थान

गुलाब बत्रा

भारत सहित दुनिया में चिकित्सकीय इतिहास में कोरोना वायरस की महामारी ने ''न भूतो न भविष्यति'' की अवधारणा को चरितार्थ कर दिया है। प्राचीन भारत के ग्रन्थों की ''त्राहिमाम-त्राहिमाम'' शब्दावली मुखरित हो गई है। प्रथम और द्वितीय विश्वयुद्ध की कटु स्मृतियों को भुला बैठी दुनिया इस आपदा से भयभीत है। भारत की बात करें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् की हमारी जो पीढ़ी 1962 में भारत-चीन युद्ध, 1965 एवं 1971 के भारत-पाक युद्ध की साक्षी रही है, वह भी वैश्विक कोरोना संकट से हतप्रभ है। ज्ञान-विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार क्रांति की दृष्टि से अग्रणी पीढ़ी भी अचम्भे में है। कोरोना वायरस के कारण-निवारण पर असमंजस है।

वैज्ञानिकों की मानें तो इस जगत् में अरबों-खरबों वायरस तथा बैक्टीरिया का अस्तित्व रहा है जिसकी खोजबीन का क्रम बना हुआ है। कोरोना की बात करें तो करीब साठ वर्ष पहले 1960 में कोरोना परिवार के वायरस की पहचान कर ली गई थी। लेकिन अत्यन्त तेजी से फैलने वाले नॉवेल कोरोना वायरस (2019-एन.सी.ओ.वी.) को इस समूह के नवीनतम वायरस की संज्ञा दी गई है। इक्कीसवीं शताब्दी के दूसरे दशक के अंत में चीन के वुहान से 31 दिसम्बर, 2019 को इसका पहला मामला उजागर हुआ इसलिए इसे कोविड-19 नाम मिला। इसमें बुखार के साथ सांस लेने में दिक्कत होती है। सामान्य खांसी-जुकाम, गले में खराश तथा फ्लू के लक्षण होते हैं लेकिन इसका पता आसानी से नहीं लग पाता है। इसके लिए दो से चौदह दिन की प्रतीक्षा या टेस्टिंग किट के विशेष उपकरण से जांच करके संक्रमित रोगी का पता लगाया जाता है।

भारत में कोरोना वायरस की दस्तक केरल से हुई। वुहान यूनिवर्सिटी की छात्रा 24 जनवरी को केरल के त्रिशूर पहुँची और अगले दिन मेडिकल टीम को अपने आगमन से अवगत कराया। तब तक उसे कोरोना के कोई लक्षण नहीं थे फिर भी वह घर पर एकांत में रही। छात्रा ने 27 जनवरी को गले में खराश तथा हल्के कफ की शिकायत की। उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती किया गया। तीस जनवरी को कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई। ऐसे तीन मामले सामने आने पर केरल सरकार ने 'राज्य आपदा' की घोषणा की। चिकित्सा के बाद छात्रा स्वस्थ हो गई। धीरे-धीरे कोरोना का प्रसार देशव्यापी होता चला गया।

कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी अब इतिहास का अभिन्न अंग बन गई है। कालचक्र के साथ इसकी मुख्य कहानियां मुखरित होंगी। राजस्थान में इस कथाक्रम की विशिष्ट चर्चा भीलवाड़ा से जुड़ गयी है। गुजरात के सूरत के पश्चात् टैक्सटाइल या कपड़ा सिटी के रूप में चर्चित भीलवाड़ा ने कोरोना संकट की शुरुआत में बदनामी का दंश झेला। लेकिन मुख्यमंत्री की सूझबूझ, जिला प्रशासन की तत्परता एवं टीम वर्क की बदौलत इस जिले ने कोरोना महामारी पर काबू पाने में बखूबी सफलता अर्जित कर देश में 'रोल मॉडल' का दर्जा हासिल कर लिया। सर्वत्र इसकी चर्चा है।

राजस्थान में कोरोना वायरस के तीसरे स्टेज की एन्ट्री भीलवाड़ा से होने से वह देश-दुनिया की निगाह में आ गया। एक समय तेरह पॉजिटिव मामले सामने आने से वह सबसे 'खतरनाक' जिला मान लिया गया। दरअसल महाराष्ट्र की राजधानी मुम्बई की 1.84 करोड़ आबादी (जनसंख्या 2011) में 74 पॉजिटिव की तुलना में भीलवाड़ा की चार लाख की आबादी में तेरह पॉजिटिव मिले थे। सिंगापुर से प्रकाशित एक समाचार पत्र ने तो भीलवाड़ा को भारत के ''इटली'' की संज्ञा दे डाली।

भीलवाड़ा की आर.सी. व्यास कॉलोनी के एक निजी चिकित्सालय बांगड़ अस्पताल में निकटवर्ती जिलों तथा अन्य इलाकों से

भी रोगी इलाज के लिए आए। इसी अस्पताल से कोरोना वायरस का ज्वालामुखी फूटा और स्वयं नियंत्रक डॉ. मित्तल और उनके अन्य सहयोगी इसकी चपेट में आ गए। डॉ. मित्तल एवं अन्य स्टाफ 17 मार्च को भीलवाड़ा के सरकारी महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती किए गए। तीसरे दिन एक साथ छः रोगियों में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई। इलाज के दौरान अस्पताल में कुल 28 पॉजिटिव रोगियों में से नेगेटिव रिपोर्ट मिलने पर इन्हें क्रमशः डिस्चार्ज किया गया जिनमें चार जयपुर ले जाए गए रोगी शामिल थे। इस अस्पताल का आइसोलेशन वार्ड देशभर की निगाहों में था। गर्व की बात यह है कि इस संवेदनशील वार्ड में कोरोना संक्रमित रोगियों की सेवा के लिए तीन डॉक्टर्स, तेरह नर्सिंगकर्मी, सात वार्ड ब्वॉय तथा सफाईकर्मियों ने स्वयं आगे आकर अपने को समर्पित किया। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. राजन नंदा एवं अस्पताल के पी.एम.ओ. डॉ. अरुण डौड़ की अगुवाई में इस टीम के जज्बे को जनता की सलामी मिली।

भीलवाड़ा से खबर मिलते ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने अधिकारियों से चर्चा कर कोरोना संकट से निपटने की रणनीति को अंजाम दिया। उधर जिला कलक्टर राजेन्द्र भट्ट ने सहकारिता क्षेत्र में कार्य करने के अपने अनुभव से एकीकृत योजना का क्रियान्वयन आरम्भ किया। तत्काल कर्फ्यू लगाने के साथ ही भीलवाड़ा जिले की सीमाओं को सील करते हुए निगरानी के लिए बीस चैक पोस्ट बनाई गई। बांगड़ अस्पताल को सील किया गया तथा 75 हजार घरों की जांच के लिए तीन सौ लोगों की टीम गठित की गई। पर्याप्त स्क्रीनिंग के साथ सरकारी स्तर पर राशन सामग्री वितरण का पुख्ता प्रबंध किया गया। शहर के वार्डों को सेनेटाइज किया गया ताकि संक्रमण की रोकथाम हो सके। कर्फ्यू का सख्ती से पालन किया गया। पुलिस के फ्लैग मार्च से शरारती तत्त्वों पर अंकुश लगा। जिला प्रशासन ने सख्ती को कड़ा करते हुए तीन अप्रैल से चौदह अप्रैल तक 'महाकर्फ्यू' की घोषणा से कानून व्यवस्था में नई शब्दावली जोड़ दी। संक्रमित लोगों ने अपने घरों पर स्टिकर लगाकर आइसोलेशन का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया।

इस प्रणाली में कोरोना के खिलाफ जिला प्रशासन ने जंग लड़ी और मीडिया ने इसे प्रमुखता से उजागर किया। नवीनतम भीलवाड़ा ने देश को कोरोना पर काबू पाने की सीख दी। केन्द्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने 5 अप्रैल को राज्यों के मुख्य सचिवों से वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा कि 223 जिलों में कोरोना फैल चुका है। इस पर काबू पाना भीलवाड़ा रोडमैप से सीखना होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी भीलवाड़ा मॉडल को हर जगह लागू करने की बात कही।

समयचक्र के साथ कोरोना वायरस से दुनिया में हड़कम्प मच गया। अमरीका, इटली, स्पेन इत्यादि देशों की तुलना में भारत में संकट की चेतावनी के साथ उठाए गए प्रभावी कदमों और जनसहयोग से इस महामारी पर काबू पाने में सफलता मिली। कोरोना वायरस की आहट पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तत्परता से स्वयं कमान संभाली। एक कुशल प्रशासक के साथ उन्होंने मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए राजस्थानवासियों को ''राजस्थान सतर्क है - राजस्थान सुरक्षित है'' के उद्घोष से इस महामारी के खिलाफ लड़ी जाने वाली लम्बी लड़ाई के लिए सावचेत किया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा के साथ सभी मोर्चों पर टीम को एकजुट करते हुए शासन-प्रशासन में नई ऊर्जा का संचार किया। स्वयं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 27 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में श्री अशोक गहलोत की कार्यशैली एवं कोरोना संकट के मुकाबले के लिए हर स्तर पर की गई पहल की मुक्तकंठ से सराहना करते हुए अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से राजस्थान का अनुसरण करने का अनुरोध किया।

लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था की भावना के अनुरूप मुख्यमंत्री ने विपक्ष के नेता सहित सर्वदलीय एवं सर्वसमाज की बैठक और धर्माचार्यों

के माध्यम से धार्मिक तथा सार्वजनिक स्थलों को भीड़ से मुक्त रखते हुए कोरोना वायरस की कड़ी को जोड़ने का संदेश दिया। इसका व्यापक असर हुआ। मुख्यमंत्री ने इसे मानवता को बचाने की लड़ाई की संज्ञा दी। लोगों से नागरिक धर्म निभाने की अपील की।

अपने पूर्व के कार्यकाल में अकाल आपदा प्रबंधन के अनुभव के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने इस विषम परिस्थिति का डटकर मुकाबला करने का संकल्प लिया और अपनी दिनचर्या से पूरी टीम को प्रेरित किया। मार्च के पहले सप्ताह में मीडिया में प्रकाशित अपने आलेख से मुख्यमंत्री ने कोरोना को पराजित करने की दृढ़ इच्छाशक्ति को दर्शाया। यह भी संयोग था कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा की पहल पर निरोगी राजस्थान अभियान शुरू करने की घोषणा मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में की थी।

भीलवाड़ा में निजी अस्पताल के चिकित्साकर्मियों के कोरोना पॉजिटिव होने का खुलासा होते ही राज्य सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा करने में विलम्ब नहीं किया। रोजमर्रा कमाकर खाने वाले तथा गरीब और बेसहारा तबके को भूखा नहीं सोने देने की मुख्यमंत्री की भावनात्मक अपील रंग लाई। प्रदेशभर से सैकड़ों हाथ इन वंचितों की मदद में जुट गए। भामाशाहों की धरती राजस्थान के दानदाताओं में मुख्यमंत्री सहायता कोष को भरने की होड़ लग गई।

राज्य की अर्थव्यवस्था तथा कोरोना वायरस की चुनौती का मुकाबला करने को चिकित्सकीय व्यवस्थाओं के लिए अतिरिक्त संसाधन भी जुटाने जरूरी थे। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की सहमति से राज्य कर्मचारियों-अधिकारियों के मार्च माह के वेतन में कटौती का निर्णय लिया। मंत्रिमण्डल सहित विधायकों के वेतन का 75 प्रतिशत भारतीय प्रशासनिक सेवा के 60 प्रतिशत और राज्य एवं अधीनस्थ सेवा के कार्मिकों का 50 प्रतिशत वेतन स्थगित किया गया। राजस्थान सरकार के इस निर्णय का केन्द्र सरकार ने भी अनुसरण किया। राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति तथा राज्यपालों ने भी वेतन कटौती पर सहमति दी। सांसद निधि भी दो साल के लिए स्थगित की गई।

लॉकडाउन के दोनों चरणों में दिशा-निर्देशों की कड़ाई से अनुपालना के साथ-साथ मुख्यमंत्री ने आवश्यकता पड़ने पर सेना तथा अर्द्धसैनिक बलों की सहायता लेने के लिए संबंधित अधिकारियों से भी विचार विमर्श किया।

कोरोना के खिलाफ लड़े जाने वाले युद्ध की रणनीति बनाने के साथ मुख्यमंत्री ने इसे तत्परता से लागू करने में कोताही नहीं बरती। नियमित मॉनिटरिंग के क्रम से प्रदेश के हर कोने के हालात से अपडेट होते रहे। कहीं भी शिथिलता बरतने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्य सचिव डी.बी. गुप्ता की अगुवाई में प्रशासनिक तंत्र ने हर मोर्चे पर अपने दायित्व का निर्वाह किया। कोरोना संक्रमित की जांच हेतु स्क्रीनिंग, सैम्पल लेने तथा कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि होने तथा रोगी की रिपोर्ट नेगेटिव आने, आइसोलेशन में रखते हुए संक्रमित के ठीक होने पर डिस्चार्ज करने तक की चिकित्सकीय व्यवस्था का गहन उत्तरदायित्व मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह की टीम ने बखूबी सम्भाला। कोरोना संक्रमितों की सेवा में भावना से जुटे स्वास्थ्यकर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री ने 25 करोड़ रुपयों की राशि का प्रावधान किया। चिकित्सकों, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्टाफ की समर्पित सेवा के फलस्वरूप पीड़ितों को इस महामारी से मुक्त कराने में सफलता मिली। एक दूसरे का हौसला बढ़ाने वाले इन कार्मिकों का समाज के विभिन्न वर्गों ने अभिनंदन किया। इन कार्मिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी जिम्मेदारी निभाने वाले पुलिसकर्मियों को कोरोना वॉरियर्स के नाते शाबासी मिली। मीडिया ने इन्हें कर्मवीर के रूप में सम्मानित किया। जनता को सभी आवश्यक सूचनाएं देने, कोरोना संकट के प्रति शिक्षित करने तथा घर-घर समाचार-पत्र पहुंचाने का दायित्व निभाने की अनूठी मिसाल पेश की गई।

समाज के हर वर्ग के हितों का ध्यान रखते हुए राज्य सरकार ने प्रभावी कदम उठाए। शिक्षण संस्थान बंद होने की सूरत में दसवीं एवं

बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के अलावा अन्य कक्षाओं के विद्यार्थियों को अगली कक्षा में क्रमोन्नत करने, निजी शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों से तीन माह की अग्रिम फीस नहीं लेने तथा शैक्षणिक अवकाश के संदर्भ में आवश्यक निर्देश दिए गए। घरेलू उपभोक्ताओं, किसानों तथा उद्योगों को राहत देते हुए बिजली-पानी के बिल दो माह के लिए स्थगित किए गए। मुख्यमंत्री ने निजी संस्थानों से लॉकडाउन के दौरान पांच लाख से अधिक औद्योगिक, व्यावसायिक तथा वाणिज्यिक श्रमिकों की सेवा एवं मजदूरी में कटौती नहीं करने का अनुरोध किया। लॉकडाउन के पश्चात् प्रदेश में सामान्य जनजीवन सहित अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए रणनीति बनाई गई।

व्यापक जनहित में राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले एक करोड़ से अधिक परिवारों को निःशुल्क अनाज उपलब्ध करवाया। वहीं इस अधिनियम से कवर नहीं होने वाले दिहाड़ी मजदूरों, स्ट्रीट वैंडर्स तथा कच्ची बस्तियों में रहने वाले जरूरतमंद परिवारों के लिए प्रशासन एवं जनसहयोग से भोजन पैकेट वितरण के क्रम को बनाये रखा।

भीलवाड़ा और राजधानी जयपुर के पश्चात् कोरोना संक्रमण ने अन्य जिलों में भी अपने पांव पसार लिए। महज 45 दिनों में राज्य के 33 जिलों में से 28 जिलों को कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया। कुछ जिलों में बने नौ हॉट स्पॉट ने चिंता की लकीरें गहरी कर दीं। आंकड़ों के ग्राफ में उतार-चढ़ाव के चलते कई बार खौफ उत्पन्न करने वाली तो कभी राहत भरी खबरों का सिलसिला भी बना। संक्रमित रोगियों की मौत और बाद में मृतक के कोरोना होने की पुष्टि के भय के साये में संकट की इस घड़ी में कोरोना वॉरियर्स के रूप में इलाज करने वाले चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ तथा सुरक्षा व्यवस्था में जुटे पुलिसकर्मी भी इस महामारी से बच नहीं पाए। लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं हारी और कर्तव्यपरायणता के नये मापदंड कायम किए। राजस्थान कई मापदण्डों में देश में अग्रणी रहा।

विडम्बना यह है कि निरन्तर अनुसंधान एवं परीक्षण के बावजूद कोरोना रोगी को ठीक करने की कोई दवा या इंजेक्शन का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। चिकित्सकों ने अपने अनुभव तथा समझ के अनुसार रोगियों की दशा के अनुसार इलाज करके उन्हें स्वस्थ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कोरोना पीड़ितों को स्वाइन फ्लू, मलेरिया तथा एच.आई.वी. की दवा से ठीक करने का दावा किया गया। हालांकि होम्योपैथी एवं आयुर्वेद से जुड़े चिकित्सकों ने भी कोरोना से रोगमुक्ति के लिए दवाएं बताई हैं। इसका टीका विकसित करने के प्रयास भी जारी हैं। प्याज्मा थैरेपी सहित अन्य विधि से उपचार के प्रयास जारी हैं।

लेकिन कोरोना के फैलाव की रोकथाम के लिए लोगों को अपने घरों में रहने, दिन में कई बार साबुन-पानी से हाथ धोने तथा आपसी सम्पर्क से बचने की सलाह दी गई। सभी स्तरों पर इसका खुला प्रचार किया गया। संक्रमण की सूरत में खुद को आइसोलेशन अथवा क्वारेंटाइन में सुरक्षित रखने को प्राथमिकता दी गई। यानी सोशल इमरजेंसी जरूरी मानी गई। महामारियों के इतिहास में जाए तो 1918 में स्पेनिश फ्लू के प्रकोप से बचने के लिए मास्क पहनने, भीड़ से दूर रहने, क्वारेंटाइन में अपने को सुरक्षित रखने तथा हाथ धोने की सलाह दी गई थी। ब्रिटिश भारत में 1.8 करोड़ सहित दुनिया में लगभग पांच करोड़ लोग इस महामारी का शिकार हुए थे। तब भी लॉकडाउन के साथ-साथ लोगों को हाथ धोने की सलाह दी गई थी। उन्नीसवीं सदी के मध्य में हंगरी के फिजिशियन इग्नाज सेमलविज ने 1847 में कीटाणुओं अथवा रोगाणुओं से मुक्ति पाने के लिए हाथ धोने की बात कही। इसका अनुभव उन्हें वियना के जनरल हॉस्पिटल में पुरुषों तथा महिलाओं द्वारा प्रसव कराने से मातृ मृत्यु दर के तुलनात्मक अध्ययन से हुआ।

यह भी ध्यान देने योग्य तथ्य है कि कोरोना संक्रमित के लक्षण सामने आने में चौदह दिन की अवधि मानी गई है। भारतीय परम्परा में इसे 'सूतक काल' की संज्ञा दी गई है। नवजात तथा मां को भी अलग रखने की व्यवस्था थी। घर में मौत होने पर भी इसका पालन होता था। बौद्ध मत में भी इसी तरह की मान्यता है। बाइबिल में भी संक्रमण से बचने के लिए

अलग रहने का उल्लेख है। ब्रिटिश भारत में संक्रमित व्याधियों के लिए माउंट आबू में क्वारेंटाइन हाउस बनाया गया था।

मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन के दोनों चरणों में अपने कार्यस्थल से पलायन प्रक्रिया की मजबूरी में फंसे श्रमिकों तथा प्रवासी राजस्थानियों को अपने प्रदेश में लौटने की गुहार को संवेदनशीलता से लिया। इसी प्रकार राजस्थान में कार्यरत अन्य राज्यों के श्रमिकों एवं प्रवासियों को उनके प्रदेश में भिजवाने की चिंता की। विशेष रेलगाड़ियों का संचालन आरम्भ हो गया। इसके लिए केन्द्र से विशेष रेलगाड़ी चलाने के गहलोत के सुझाव का अन्य मुख्यमंत्रियों ने भी समर्थन किया। इसमें सफलता मिली और केन्द्र सरकार तथा संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सम्पर्क साधकर कोरोना से बचाव एवं सभी सुरक्षा निर्देशों की अनुपालना के साथ चरणबद्ध तरीके से इस कार्ययोजना को अंजाम देकर मानवीय दृष्टिकोण की मिसाल प्रस्तुत की। देश में कोचिंग सेन्टर के रूप में प्रसिद्ध शिक्षा नगरी कोटा से छात्र-छात्राओं को उनके घरों तक पहुंचाने की कारगर व्यवस्था को सराहा गया।

चिकित्सा व्यवस्था में कोरोना महामारी को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलने से अन्य सामान्य बीमारियों की चिकित्सा की अनदेखी नहीं हो जाए इस तरफ भी मुख्यमंत्री का ध्यान गया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा तथा अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों, सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर गैर कोरोना बीमारियों की चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करवाई। यही नहीं 400 ओपीडी मोबाइल वैन की सेवाएं भी उपलब्ध की गईं। प्रधानमंत्री ने भी इस कदम की प्रशंसा की।

तीसरी बार मुख्यमंत्री का दायित्व संभालते हुए अशोक गहलोत ने अपनी राष्ट्रीय छवि के अनुरूप राजस्थान सहित अन्य राज्य सरकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए कोरोना संकट से जुड़े विभिन्न बुनियादी मुद्दों को केन्द्र सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से रखने की पहल की। उन्होंने रैपिड टेस्ट किट की गुणवत्ता एवं चिकित्सकीय उपकरणों की खरीद केन्द्र स्तर पर करने संबंधी कई रचनात्मक सुझाव दिए तो केन्द्र सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने में झिझक महसूस नहीं की। लॉकडाउन के पश्चात् दी जाने वाली छूट को लेकर राज्यों में भ्रम की स्थिति दूर करने के लिए गृह मंत्रालय से मौखिक की अपेक्षा लिखित आदेश देने पर बल दिया।

स्वयं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों से वीडियो क्रॉन्फ्रेंसिंग में अशोक गहलोत को बधाई देते हुए कोरोना संबंधी पहल के लिए राजस्थान के अनुसरण की नसीहत दी। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ''भीलवाड़ा रोल मॉडल'' के अनुसरण की बात कही। मन की बात में प्रधानमंत्री ने अलवर जिले के पनियाला स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बनाए गए क्वारेंटाइन सेन्टर में रहने वाले मजदूरों द्वारा स्कूल का रंग-रोगन करके नया रूप देने की सराहना की। बहरोड़ से मध्यप्रदेश जाने वाले 21 परिवारों के 74 लोगों को इस सेन्टर में रखा गया था। जनसहयोग से रंग रोगन जुटाया गया और श्रमिकों ने निःस्वार्थ भाव से विद्यालय को सुसज्जित किया।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को भेजे पत्र में राज्यों को एक लाख करोड़ का अनुदान, जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति अवधि दस वर्ष करने, राज्य सरकारों को बकाया कर्ज की किस्तों पर छः माह का मुक्त मोरेटोरियम देने, कृषि

उत्पादन की 50 प्रतिशत तक समर्थन मूल्य पर खरीद उद्योग, व्यापार जगत के लिए व्यापक आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज, अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए राजकोषीय व्यय को बढ़ावा देने, श्रमिकों के वेतन भुगतान हेतु केन्द्रीय योजना, अटके प्रवासी श्रमिकों को उनके घरों तक पहुंचाने की राष्ट्रीय योजना बनाने, इंटरनेट सप्लाई चेन की बहाली, चिकित्सा उपकरणों की केन्द्रीयकृत खरीद तथा राज्यों को आर्थिक-औद्योगिक गतिविधियों के लिए स्वतंत्रता देने की मांग की है।

कोरोना वायरस महामारी ने देश के स्वास्थ्य ढांचे को और मजबूत बनाने की सीख दी है। इसलिए केन्द्र सरकार ने कोविड-19 इमरजेंसी रेस्पांस एंड हैल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज मद में पन्द्रह हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसका प्रथम चरण जनवरी से जून, 2020 तक, दूसरा चरण जुलाई, 2020 से मार्च, 2021 तक पूरा किया जाएगा। इसके अन्तर्गत राज्यों को जरूरी सामान की खरीद में सहायता मिलेगी। इस दिशा में पहल करते हुए मुख्यमंत्री ने 27 अप्रैल को दो वर्ष के लिए विधायक कोष के अन्तर्गत आवंटित धनराशि स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास हेतु समर्पित करने का निर्णय लिया। राज्य के 200 विधानसभा क्षेत्रों के लिए हर वर्ष 450 करोड़ की राशि इस कोष में आवंटित की जाती है।

कोरोना वायरस प्रकरण में दुनिया भर में बदनामी झेल रहे चीन में पूंजी निवेश करने वाली विदेशी कम्पनियों ने वहां से बाहर निकलने का मानस बना लिया है। कोरोना पर प्रभावी ढंग से काबू पाने में भारत अग्रणी है इसलिए विदेशी कम्पनियां यहां निवेश करने को उत्सुक होंगी। इस संभावना के मद्देनजर राजस्थान के उद्योग विभाग ने विदेशी कम्पनियों को निवेश के लिए आमंत्रित करने की मशक्कत शुरू की है। प्रारम्भिक चरण में जापान को प्राथमिकता दी जाती है। उल्लेखनीय है कि जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र में ''जापानी औद्योगिक इकाइयों का जोन'' प्रभावी ढंग से काम कर रहा है।

कोरोना संक्रमण संकट के दौरान साहित्य कला, संगीत में सृजन के नए आयाम जुड़े। सारंगी वादक उस्ताद मोइनुद्दीन खान ने सारंगी के

समक्ष दीप जलाकर दीपक राग के स्वर छेड़ नया इतिहास रचा। कहते हैं कि 1584 के अंत में अकबर के दरबार में तानसेन ने जब दीपक राग गाया तो महल के सारे दीपक जल उठे थे। पं. भीमसेन जोशी सहित अन्य गायक दीपक राग का गायन कर चुके हैं। लेकिन सारंगी या अन्य किसी वाद्य यंत्र पर दीपक राग की स्वर लहरी बिखेरने का यह पहला दावा था। विश्वविख्यात मोहन वीणा वादक पं. विश्वमोहन भट्ट अपने पुत्र शिष्य पं. सलिल भट्ट के साथ नई रचना को स्वर देने में जुटे हैं। चित्रकारों ने तूलिका के रंग दिखाए तो साहित्यकर्मियों की लेखनी ने सृजन धर्म निभाया।

कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए देश में 24 मार्च से लागू तालाबंदी (लॉकडाउन) की अवधि तीसरी बार 17 मई तक बढ़ाई गई। संक्रमण की सघनता की दृष्टि से समूचे देश को चार भागों में विभक्त किया गया है। सामान्य जनजीवन की बहाली के उद्देश्य से कंटेनमेंट जोन के अलावा रेड जोन, ऑरेंज जोन तथा ग्रीन जोन चिह्नित करके अलग-अलग छूट दी गई है जिन पर कड़ी निगरानी रखी गई है।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा के अनुसार प्रदेश में रेड जोन के आठ जिलों को ग्रीन जोन में परिवर्तित करने के लिए विशेष कार्य-योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रदेश के 33 जिलों की

338 में से सिर्फ 50 तहसीलों में कोरोना रोगी मिले हैं। शेष 288 तहसीलों का 80 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र एवं 70 प्रतिशत आबादी सुरक्षित है। डॉ. शर्मा ने बताया कि रेड जोन की कुल 109 तहसीलों में महज 20 तहसील क्षेत्र में कोरोना रोगी मिले हैं। इसलिए 89 तहसीलों को ग्रीन जोन में लाया जा सकता है। रैंडम सैम्पलिंग का दायरा बढ़ाने के साथ प्रतिदिन दस हजार की दर से टेस्ट का लक्ष्य हासिल करने के प्रयास हैं। मुख्यमंत्री ने इसे 25 हजार तक ले जाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए विदेश से मशीन मंगाई गई है। नतीजतन संक्रमण की दर 75 प्रतिशत से घटकर 4.84 प्रतिशत तक पहुंच गई है। सरकार कोरोना चेन तोड़ने के लिए हरसम्भव उपाय कर रही है। मुख्यमंत्री से लेकर हर स्तर पर मॉनिटरिंग की पुख्ता व्यवस्था है।

थार मरुस्थल की थाती लिए राजस्थान ने हर संकट का धैर्य एवं संयम से मुकाबला किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस संक्रमण को वैश्विक महामारी घोषित किया। केन्द्र सरकार ने भी महामारी अधिनियम 1897 को नए संशोधन के साथ 22 अप्रैल से लागू किया। इस एक्ट के तहत पहली बार यात्री रेल संचालन बंद किया गया। स्वतंत्रता से पूर्व तत्कालीन बीकानेर रियासत में हैजा बीमारी पर अंकुश के लिए खतरनाक फैलने वाली बीमारियों का एक्ट-1927 बनाया गया। तब बीकानेर रियासत से लगती सभी सीमाएं सील कर दी गईं। राजस्थान गठित होने तक यह एक्ट लागू रहा। इससे संबंधित दस्तावेज बीकानेर स्थित अभिलेखागार में सुरक्षित हैं। राजस्थान सरकार ने भी नए एपीडेमिक डिजीज एक्ट 1897 में कुछ नए अधिकारों के साथ अध्यादेश लागू किया है।

भारतीय काल गणना की दृष्टि से सतयुग, त्रेता, द्वापर युग के पश्चात् हम वर्तमान में आधुनिक युग के साक्षी हैं। इस युग की अत्यंत उन्नत तकनीक के बावजूद छोटे से कोरोना विषाणु से समूची दुनिया सिहर उठी है। प्रकृति तक को चुनौती देने वाला मानव समुदाय घुटने टेकने को विवश है। पूरा सिस्टम ध्वस्त होने के कगार पर है। अनेक शताब्दियों की व्याधियों के इतिहास को समेटे मानव प्रजाति ''जान है तो जहान है'' की प्रतिछाया में जी रही है। कोरोनाकाल से चिह्नित यह महामारी अब कोरोना

से पहले और कोरोना के बाद की विभाजनकारी रेखा खींच चुकी है। इसके फलस्वरूप हम आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मानसिक मोर्चे पर एक नए युद्ध की ओर अग्रसर हैं।

मानवीय जीवन में वायरस प्रसार की इस अप्रत्याशित घटना से अपेक्षित चिकित्सकीय प्रबंधन के साथ ही इससे निपटने या बचाव हेतु एकांत साधना (आइसोलेशन) एवं परस्पर दूरी बनाये रखने की उपयोगिता का सबक मिला है। इस संदर्भ में सनातन संस्कृति के अभिवादन की ''नमस्कार'' मुद्रा को विश्व ने अपनाने की पहल की है। कोरोना वायरस संक्रमण के संकट ने हमारी जीवनशैली तथा कार्य संस्कृति को प्रभावित किया है। कई मायनों में इसे गुणात्मक दृष्टि से देखना होगा।

सूचना प्रौद्योगिकी युग में सीमा मर्यादा के दायरे में ''वर्क फ्रॉम होम'' की छूट को व्यापक केनवास मिलने की संभावना बढ़ गई है। इसकी सकारात्मक पहल पर जोर दिया जा रहा है। मसलन घर पर रहते हुए काम करने पर आवागमन कम होने से यातायात एवं प्रदूषण समस्या के निदान में सहायता मिलेगी। ऊर्जा एवं समय की बचत के साथ व्यक्ति परिवार के साथ रहते हुए बेहतर महसूस करेगा। अलबत्ता काम के टार्गेट और डेडलाइन के दबाव से व्यक्तित्व क्षमता बढ़ेगी। दूसरी ओर नियोजक के संस्थागत प्रशासनिक खर्चे में कमी आएगी। शिक्षा जगत में ऑनलाइन कक्षाओं तथा पाठ्यक्रम के स्वरूप में परिवर्तन संभावित है। अब तो कोरोना वायरस को उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल करने की योजना बनाई जा रही है।

कोरोना त्रासदी जीवन बदलने वाली घटना का प्रतीक बन गई है। आने वाले वर्षों में लोग अपनी तरह की जिंदगी बिताने की आदत के लिए तरस जाएंगे। हमारी सामाजिक संरचना में क्या-क्या परिवर्तन संभावित दिखाई देते हैं, इसकी कल्पना की जा सकती है। उदाहरण के तौर पर क्या हम सामाजिक-धार्मिक उत्सव पहले की तरह जोश-खरोश से मना पाएंगे। शादी-विवाह तथा सुख-दुःख के अन्य प्रसंगों में सम्मिलित होने का हमारा क्या दृष्टिकोण रहेगा। कोरोना संकट में चिकित्सा पेशे से जुड़े जोखिम के परिदृश्य के चलते क्या भावी पीढ़ी अथवा उनके अभिभावक इसके अध्ययन के प्रति प्रोत्साहित होंगे और संसदीय लोकतंत्र की चुनाव प्रणाली में स्वास्थ्य एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा बन जाएगा। अनेक सवाल हमारा पीछा करेंगे। लेकिन डर के आगे जीत है - इस सद्भावना से हमें आगे बढ़कर समाज और राष्ट्र जीवन को नई दिशा देनी होगी।

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, 'यूनीवार्ता' के समाचार सम्पादक रहें है।

शासन सचिवालय व सूचना एवं जनसम्पर्क भवन को सेनेटाइज किया

कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए नगर निगम जयपुर हैरिटेज एवं ग्रेटर जयपुर द्वारा शासन सचिवालय एवं सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के भवन को फायर ब्रिगेड की हॉजरील पद्धति द्वारा सेनेटाइज किया गया।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के आयुक्त श्री महेन्द्र सोनी ने बताया कि सोडियम हाइपोक्लोराइड द्वारा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के पूरे भवन को सेनेटाइज किया गया। सेनेटाइज कार्य को रॉकी शर्मा तथा मनीष सैनी फायर मैन ने सम्पादित किया।

राजस्थान_सतर्क_है

कोविड-19

कुशल प्रबन्धन एवं बेहतर चिकित्सा व्यवस्था

– हेतप्रकाश व्यास

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की सजगता और दूरदर्शिता के कारण देश सहित पूरी दुनिया में कोरोना को लेकर राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को सराहा जा रहा है। यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री ने भी मुख्यमंत्री के कुशल प्रबंधन और चिकित्सा व्यवस्था की तारीफ करते हुए अन्य मुख्यमंत्रियों को इनके कदमों का अनुसरण करने की बात कही। जादुई नेतृत्व के धनी प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की सतत मॉनिटरिंग और चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा की बेहतरीन माइक्रो प्लानिंग का नतीजा रहा कि जिस कोरोना ने पूरी दुनिया को घुटनों पर ला दिया, वह राजस्थान में पूरी तरह पैर नहीं पसार पाया। कोरोना ने शुरू में अपने तेवर तो दिखाए लेकिन सरकार की मजबूत चिकित्सा व्यवस्थाओं के आगे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं कर पाया।

प्रदेश में 2 मार्च को इटली से आए पर्यटक दंपती इस अनचाहे मेहमान को अपने साथ ले आए। राजस्थान सरकार अपने स्लोगन 'राजस्थान सतर्क है' के अनुसार पहले दिन से ही सतर्क रही। श्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने महामारी की भयावहता को भांपते हुए पहले दिन से ही एक्शन लेना शुरू कर दिया। जिन जिलों में इस दंपती ने भ्रमण किया था, वहां का घर-घर जाकर सघन सर्वे, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग सहित सभी जरूरी व्यवस्थाओं के तुरंत दिशा-निर्देश दिए। चिकित्सा मंत्री के नेतृत्व में अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री रोहित कुमार सिंह, चिकित्सा शिक्षा सचिव श्री वैभव गालरिया और उनकी टीम ने पहले दिन से ही धरातल पर आकर काम करना शुरू कर दिया। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों के स्तर पर रैपिड रेस्पोन्स टीमों का गठन किया गया। इन टीमों में पीएसएम, मेडिसिन, माइक्रोबायोलोजी और पीडियाट्रिशियन विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर एवं एपीडेमोलोजिस्ट को शामिल किया गया। टीमों ने संदिग्ध पर्यटक के द्वारा ठहरे होटल एवं भ्रमण स्थलों का निरीक्षण किया और निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार ठहरने व भ्रमण किए स्थलों को डिसइंफेक्शन भी करवाया। संदिग्ध व्यक्तियों की जांच कर एपीडेमिक इन्वेस्टीगेशन व कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग प्लान बनाकर काम किया।

चिकित्सा मंत्री ने तुरंत विभागीय अधिकारियों की मीटिंग लेकर जयपुर के एसएमएस अस्पताल और आरयूएचएस अस्पताल को आइसोलेशन सेंटर बनाने, निजी अस्पतालों को किसी भी स्थिति में तैयार रहने के निर्देश जारी कर दिए। साथ ही भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार चिकित्सक, एएनएम, आशा सहयोगिनियों को संबंधित प्रशिक्षण दिलाना शुरू कर दिया। प्रदेशभर में इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट व सोशल मीडिया द्वारा जागरूकता अभियान शुरू कर दिया गया। सभी जिला मुख्यालयों और राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम बनाकर विशेष 104/108 नंबर जारी कर दिए। सभी जिला कलक्टर्स को नोडल अधिकारी बनाया गया और सभी जिलों में कंट्रोल रूम स्थापित कर एडीएम स्तर के अधिकारी को इसका प्रभारी बनाया गया। सभी जिला नोडल

अधिकारियों को पल-पल की रिपोर्टिंग करने के निर्देश दे दिए गए। साथ ही रेलवे, परिवहन और रोडवेज के अधिकारियों को विदेशी पर्यटकों की स्क्रीनिंग करवाने के सहित कई आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए। इसके अलावा 'निरोगी राजस्थान' के लिए प्रशिक्षित लगभग 27000 टीमों ने प्रदेशभर में व्यापक सर्वे और स्क्रीनिंग का काम भी शुरू कर दिया। सरकार ने पहली बैठक में कोरोना को बांधने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया था। स्वयं मुख्यमंत्री ने भी सैकड़ों वीडियो कॉन्फ्रेंस और बैठकें लेकर कोरोना को हराने का संकल्प शुरू में ही जाहिर कर दिया था।

यूं तो प्रदेश में तीसरा मरीज आठ दिन बाद 10 मार्च को दुबई की फ्लाइट से आए एक 85 वर्षीय बुजुर्ग के रूप में आया लेकिन मामला तब ज्यादा चर्चा में आया, जब 20 मार्च को भीलवाड़ा के एक निजी अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव चिकित्सक द्वारा सैकड़ों मरीजों के इलाज करने की खबर आई। खबर मिलते ही पूरा प्रशासन भीलवाड़ा को संक्रमण से बचाव में जुट गया। चिकित्सा मंत्री ने निदेशक स्वास्थ्य सहित कई उच्चाधिकारियों को तुरंत मौके पर भेजा। उदयपुर से आरआरटी (रैपिड रेस्पॉन्स टीम) को रवाना किया गया। क्षेत्र में व्यापक सर्वे और कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के निर्देश देकर रूथलेस कंटेनमेंट प्लान के अनुसार 1, 3 और 5 किलोमीटर के क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया। भीलवाड़ा से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 26 तक जा पहुंची। जिले के 6 लाख घरों के 28 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की गई और करीब 18000 आईएलआई के केसेज चिह्नित किए गए। लोग भीलवाड़ा को 'चाइना का वुहान' और 'इटली' तक की संज्ञा देने लगे लेकिन चिकित्सा विभाग की बेजोड़ रणनीति और प्रशासन के बेहतर समन्वय से कुछ ही दिनों में भीलवाड़ा के कुचक्र को तोड़ने में कामयाब हो गया। कल का 'वुहान' कहा जाने वाला भीलवाड़ा आज दुनिया के लिए 'मॉडल' बन गया।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अगुवाई में प्रदेश में कोरोना की रोकथाम के लिए उठाए गए कदम देशभर के लिए नजीर बन गए। कोरोना से प्रदेश की आमोआवाम को बचाने के लिए सबसे पहले राजस्थान ने लॉकडाउन की घोषणा की उसके बाद केन्द्र सरकार ने इसे देशभर में लागू किया। कोरोना प्रभावितों की जांच के लिए राजस्थान में पहली बार रैपिड टेस्टिंग किट का इस्तेमाल किया गया। कोरोना की जांचों में गति लाने के लिए राज्य सरकार ने अमरीका से अत्याधुनिक टेस्टिंग मशीन कोबास-8800 खरीदी। इस मशीन को अब तक राजस्थान और तेलंगाना ने ही मंगवाया है। सैंपलिंग के मामले में प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल रहा। इसके अलावा प्लाज्मा थैरेपी से इलाज करने वाला भी राजस्थान देशभर में चौथा प्रदेश ही है।

राज्य में 2 मार्च को पहला केस आने के पहले से ही सरकार भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन की पालना करने लग गया था। विभाग ने प्रदेश के सभी समाचार पत्रों, प्रादेशिक चैनल्स, एफएम रेडियो और सोशल मीडिया पर योजनाबद्ध तरीके से कोरोना के प्रति जागरूकता संबंधी विज्ञापन, जिंगल प्रकाशित और प्रसारित की गई। चिकित्सा मंत्री ने स्वयं कई एफएम रेडियो केन्द्रों, अखबारों के दफ्तर जाकर और विभिन्न चैनल्स पर जाकर लाइव शोज में हिस्सा लेकर लोगों को इस बारे में जागरूक किया। व्यापक जागरूकता और सजगता का ही परिणाम रहा कि कोरोना का संक्रमण प्रदेश में ज्यादा नहीं फैल पाया।

क्वारेंटाइन में दी बेहतरीन सुविधाएं

प्रदेश में कोरोना संदिग्धों को क्वारेंटाइन में रखने के लिए सरकार द्वारा किए प्रयासों को आमजन ने खूब सराहा। प्रदेश के हजारों लोगों को कोरोना से बचाने के लिए सरकारी भवनों, होटलों में क्वारेंटाइन रखा गया और वहां नाश्ता, लंच, डिनर सहित सभी आवश्यक सुविधाओं की भरपूर व्यवस्था की गई। जयपुर के बगराना और महला रोड सहित कई जगहों पर स्थित आवासन मंडल और जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराए गए मकानों और फ्लैट्स में लोगों को क्वारेंटाइन में रखा गया, जिससे प्रदेश में कोरोना के सामाजिक संक्रमण का खतरा टल गया।

जांचों के मामले में प्रदेश अग्रणी

देश-विदेशों के साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स के अनुसार कोरोना की जितनी ज्यादा जांचे होंगी उतने ही प्रभावी तरीके से इसके संक्रमण को रोका जा सकेगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत को इस बात का अहसास था। इसी वजह से सरकार ने पहले से टेस्टिंग के लिए योजना तैयार कर

रखी थी। जब 2 मार्च को प्रदेश में पहला कोरोना पॉजिटिव आया तब प्रदेश में कोरोना जांच की कोई सुविधा नहीं थी लेकिन महज दो महीने से भी कम समय के अंतराल में प्रदेश 12 हजार से ज्यादा जाँचे प्रतिदिन करने वाला राज्य बन गया। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप इस लक्ष्य को 25000 तक जल्द से जल्द पहुंचाने के लिए कार्य भी शुरू हो गया। प्रदेश के दो जिलों जयपुर और जोधपुर में ज्यादा से ज्यादा जांचों के लिए कोबास-8800 खरीद ली गई हैं, इसके जरिए 4-4 हजार जांचे और की जा सकेंगी। यही नहीं इससे आरएनए एस्ट्रक्शन और आरटी-पीसीआर दोनों टेस्ट ऑटोमेटिक और मैनुअली दोनों टेस्ट हो सकेंगे। भरतपुर, डूंगरपुर, पाली, बाड़मेर, उदयपुर, अजमेर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में आरटी-पीसीआर की मशीनों के जरिए जांचे शुरू करवाई गईं। भीलवाड़ा में आईसीएमआर द्वारा जांच की अनुमति मिलने के बाद लगातार जांचे हो रही हैं। इसके अलावा जोधपुर के डेजर्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी 300 जांच प्रतिदिन करवाने की सुविधा प्रारंभ हो गई है। जांचों में तेजी के लिए टीबी की जांच के लिए काम आने वाली सीबीनाट मशीनों को भी काम में लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री गहलोत की तो प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना की लैब विकसित करने की भी योजना है।

संक्रमण पर रोक नहीं होती तो आंकड़ा दोगुना–तिगुना होता

यह चिकित्सा मंत्री श्री शर्मा के प्रयासों का नतीजा था कि प्रदेश में 14 अप्रैल के बाद संक्रमण में तेजी से गिरावट आने लगी। एक समय वह भी था जब प्रदेश में संक्रमण 75 प्रतिशत की दर तक पहुंच गया था लेकिन योजनाबद्ध प्रयासों की वजह से यह 4.84 प्रतिशत तक आ गई। एक आकलन के अनुसार यदि इस बारे में सरकार के स्तर पर गंभीर प्रयास नहीं होते तो कोरोना प्रभावितों का आंकड़ा दोगुना या तीगुना हो चुका होता। देश में कुछेक राज्य ही ऐसे होंगे जो कोरोना पर इतना नियंत्रण कर पाए होंगे। संक्रमण को रोकने के लिए चिकित्सा विभाग व अन्य विभागों द्वारा बेहतरीन समन्वय के चलते ही यह संभव हो पाया।

निजी अस्पतालों को सर्विस देने के लिया किया पाबंद

कोरोना के भय के चलते एक बार तो प्रदेश के निजी चिकित्सालय भी मरीजों से कन्नी काटने लगे थे लेकिन सरकार की सजगता का परिणाम रहा कि सभी निजी चिकित्सालयों को नियमित रूप से चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवानी पड़ी। चिकित्सा मंत्री और विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के कड़े निर्देशों के बाद आम नागरिकों के अलावा आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना व सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना सहित कई योजनाओं के अधीन आने वाले लोगों को इलाज आसानी से मिलने लगा।

प्रदेश की सतर्कता से रैपिड टेस्टिंग किट पर लगी देशभर में रोक

देश में राजस्थान एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसकी सतर्कता की वजह से चीन से आयातित रैपिड टेस्टिंग किट के इस्तेमाल पर रोक लगी। प्रदेश में कोरोना की वास्तविकता को जांचने के लिए ही रैपिड टेस्टिंग किट की मदद ली जा रही थी लेकिन किट के पूर्णतया कसौटी पर खरा नहीं उतरने के बाद प्रदेश में टेस्टिंग रोक दी गई है और आईसीएमआर (भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद्) को लिखा गया। रैपिड टेस्टिंग किट का प्रभाव जानने के लिए विभाग ने माइक्रोबॉयोलोजी की हैड और मेडिसिन विभाग प्रमुख के नेतृत्व में कमेटी बनाई थी। कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार किट्स की एक्यूरेसी (शुद्धता) 90 प्रतिशत होनी चाहिए थी लेकिन (कोरिलेशन) 5.4 प्रतिशत ही आ रहा है। राजस्थान सहित अन्य प्रदेशों से मिले फीडबैक के बाद आईसीएमआर को देशभर में इसके द्वारा की जाने वाली टेस्टिंग पर रोक लगा दी।

550 से ज्यादा मोबाइल ओपीडी वैन कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों हेतु वरदान

प्रदेश के ऐसे क्षेत्र जहां लॉकडाउन, कर्फ्यू होने के कारण लोग चिकित्सा सुविधाओं से वंचित हैं उन क्षेत्रों में सभी सुविधाओं से युक्त

430 से ज्यादा मोबाइल ओपीडी वैन लोगों को लाभान्वित कर रही हैं। आमजन को जांच एवं दवा वितरण की सेवाएं इन मोबाइल वैन के जरिए दी जा रही हैं। ये वैन उपखंड मुख्यालयों के साथ अन्य महत्त्वपूर्ण स्थानों पर सुबह 8 बजे से 2 बजे तक चिकित्सा उपचार सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। अब प्रदेश के 6 अन्य जिलों में 120 अतिरिक्त वैन चलाई जायेगी। जहाँ अधिक संख्या में प्रवासी बाहर से आ रहे है। कोई भी व्यक्ति इस सेवा के अंतर्गत नि:शुल्क उपचार ले सकता है। इन मोबाइल वाहनों में लाउडस्पीकर की व्यवस्था भी की गई है ताकि घरों में रह रहे लोगों को इसकी सूचना आसानी से मिल सके। वैन में नियुक्त चिकित्सक व पैरामेडिकल स्टाफ जुकाम, बुखार जैसी सामान्य बीमारियों के अलावा मधुमेह, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों की दवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं।

सरकार ने वैज्ञानिक तरीके से किया काम

गौरतलब है राज्य में जहां भी हॉट स्पॉट बने वहां सरकार ने वैज्ञानिक तरीके से काम करते हुए बढ़ते संक्रमण को रोकने की कोशिश की है। राज्य में पिछले कई दिनों में संक्रमण का खतरा कम हुआ है। हालांकि कोरोना हॉट स्पॉट कहीं भी बनना संभव है लेकिन उस पर नियंत्रण करना बड़ी बात थी और इसमें सरकार कामयाब भी रही है। सरकार ने हर हॉट स्पॉट की अलग से योजना बनाकर उस पर काम किया है। भले ही भीलवाड़ा, रामगंज हो या फिर जोधपुर, बीकानेर सभी जगहों पर योजनाबद्ध तरीके से काम कर कोरोना को मात देने की कोशिश की गई।

प्लाज़्मा थैरेपी से इलाज में राजस्थान बना अग्रणी

चिकित्सा मंत्री के सफल नेतृत्व में जयपुर का सवाई मानसिंह अस्पताल प्रदेश का पहला ऐसा चिकित्सालय बन गया है जहां दो लोगों का ट्रायल बेस पर प्लाज्मा थैरेपी से इलाज किया गया है। केरल, मध्यप्रदेश और दिल्ली के बाद चौथा ऐसा राज्य बन गया है, जो प्लाज्मा थैरेपी के जरिए कोरोना का इलाज कर पाने में समक्ष है। जयपुर के बाद जोधपुर को भी प्लाज्मा थैरेपी के जरिए इलाज करने की अनुमति आईसीएमआर से मिल गई है। चिकित्सा मंत्री का मानना है कि प्रदेश में कोरोना से होने वाली मृत्युदर राष्ट्रीय मृत्युदर से कम है। प्लाज्मा थैरेपी के आने से कोरोना से होने वाली मृत्युदर के आंकड़ो में और कमी आएगी। प्लाज्मा थैरेपी के जरिए उन्हीं मरीजों का इलाज किया जा सकता है, जो गंभीर रूप से संक्रमित हो, वेंटिलेटर पर हो या किडनी, हार्ट, डायबिटीज

जैसी अन्य क्रॉनिकल बीमारियों से ग्रसित हो। कुछ ही दिनों पहले खबर आई कि चीन, अमरीका सहित कई राज्यों में प्लाज्मा थैरेपी से इलाज किया जा रहा है। सरकार ने इसे भी हाथोंहाथ लिया और चिकित्सा विभाग का दल इसकी तैयारी में जुट गया। सरकार ने तैयारियों की सूचना आईसीएमआर को भेज दी। वहां से अनुमति मिलने के साथ ही प्लाज्मा थैरेपी से इलाज शुरू कर दिया गया।

नर्सिंगकर्मियों की नियुक्तियों की खुली राह

कोरोना से लड़ाई में मानव संसाधन की कमी नहीं आए इसके लिए चिकित्सा मंत्री के निर्देश पर 2000 नए चिकित्सकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों ही 735 नए चिकित्सकों को जिलों में नियुक्ति देकर कोरोना के खिलाफ मैनपॉवर मजबूत की गई थी। यही नहीं मुख्यमंत्री के निर्देश पर न्यायालय में अटकी 12 हजार 500 जीएनएम और एएनएम की भर्ती का रास्ता साफ करते हुए 9 हजार एएनएम और जीएनएम को नियुक्ति दे दी गई।

आधारभूत ढांचे को किया मजबूत

राजस्थान सरकार ने सुनियोजित काम कर लॉकडाउन के दौर का सदुपयोग किया। चिकित्सा मंत्री की पहल पर इस समय प्रदेश में चिकित्सा के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने का काम किया है। राज्य में जब 2 मार्च को पहला कोरोना पॉजिटिव आया तब प्रदेश में कोई जांच की सुविधा नहीं थी, आज विभाग 5 हजार से ज्यादा जांचे कर पाने में सक्षम है। मुख्यमंत्री का लक्ष्य 10 हजार जांचे प्रतिदिन करने का है, इस ओर भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन कोरोना का स्थाई समाधान नहीं है। इसे चरणबद्ध तरीके से खोलने से जिंदगी दोबारा पटरी पर आ सकती है।

बेहतर चिकित्सकीय प्रबंधन से मृत्युदर महज 2.63 फीसदी

सरकार के बेहतरीन चिकित्सकीय प्रबंधन के चलते कोरोना से होने वाली मौतों के मामले में राज्य देश के आखिरी पायदानों पर खड़ा

नजर आया। प्रदेश में कोरोना से होने वाली मृत्युदर 2.63% है, जबकि देश में यह दर 3.23% है। राज्य में जो मौतें हुई हैं वे मरीज भी कोविड़ नहीं अन्य घातक बीमारियों से ग्रसित थे।

बिना पर्ची के दवाओं की बिक्री पर रोक

प्रदेश में कोरोना के एक-एक मरीज को चिह्नित करने के लिए सरकार ने हर तरीका अपनाया। उसी में से एक था बिना चिकित्सक की पर्ची के खांसी, जुकाम और बुखार की दवाओं पर रोक लगाना। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री रोहित कुमार सिंह ने योजनाबद्ध तरीके से किसी भी केमिस्ट या दवा विक्रेता को बिना चिकित्सक की पर्ची के सामान्य बीमारियों की दवाइयां उपलब्ध नहीं कराने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी व्यवस्था की कि दवा विक्रेता ऐसे व्यक्ति का नाम-पता और टेलीफोन नंबर लेकर औषधि नियंत्रक अधिकारी या चिकित्सा संस्थान के प्रभारी को तुरंत सूचित करें। उन्होंने सभी औषधि नियंत्रक अधिकारी या चिकित्सा संस्थान के प्रभारियों को भी प्रतिदिन उक्त सूचना को अपने जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं ताकि विभाग की टीम द्वारा ऐसे व्यक्तियों से संपर्क कर स्क्रीनिंग और जांच आदि की कार्यवाही की जा सके।

घर बैठे मिल रही दवाइयां

लॉकडाउन या कर्फ्यू के दौरान नियमित रूप से दवा लेने वाले मरीजों को होने वाली समस्या को देखते हुए चिकित्सा मंत्री ने विशेष व्यवस्था कर राज्य स्तरीय दवा आपूर्ति नियंत्रण कक्ष स्थापित करवाया है। यह नियंत्रण कक्ष प्रतिदिन सुबह 9.30 बजे से सायं 6 बजे तक कार्य करता है। दवा की आपूर्ति के लिए कोई भी मरीज नियंत्रण कक्ष के दूरभाष सम्पर्क नंबर 0141-2228600 या ईमेल- **pharmacycouncilrajasthan@gmail.com** पर सम्पर्क कर सकता है। नियंत्रण कक्ष द्वारा मरीज को उसके निवास के निकटतम दवा की दुकान या फर्म का मोबाइल नंबर (व्हाट्सएप नम्बर) उपलब्ध कराया जाता है। मरीज द्वारा चाही गई दवा का पर्चा उस दवा विक्रेता को व्हाट्सएप पर भेजा जाता है और वांछित दवाओं को औषधि विक्रेता मरीज के घरों पर बिल सहित आपूर्ति करते हैं।

संदिग्धों के लिए जिलों में बनाए जा रहे हैं कोविड केयर सेंटर

प्रदेश में कोविड संक्रमण के बचाव एवं रोकथाम के लिए राजस्थान ने एडवांस मैनेजमेंट पर काम करना शुरू कर दिया है। सरकार ने फैसला किया है कि आने वाले दिनों में प्रदेश के सभी जिलों में आवश्यकता के अनुसार 500 या 1 हजार बैडेड की क्षमता वाले कोविड केयर सेंटर बनाए जाएंगे। शुरुआत 30 हजार बैडेड से की जाएगी और फिर जरूरत के अनुसार इसे 50 हजार बैडेड तक पहुंचाया जा सकता है। इन केन्द्रों का चयन आबादी से दूर किया जाएगा और वहां सभी आवश्यक सुविधाएं मसलन भोजन, बिजली, पानी, पंखे-कूलर, वाटर कूलर आदि की व्यवस्था भी की जाएगी ताकि मरीज को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने बताया कि सेंटर पर व्यक्तियों के प्रवेश

और निकास के लिए एक ही एंट्री गेट रखा जाएगा ताकि संपूर्ण व्यवस्था पर निगरानी रखी जा सके और संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इसके अलावा सेंटर्स पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुख्य स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे ताकि हर जगह की निगरानी की जा सके। इसके अलावा माइकिंग की भी व्यवस्था की जाएगी। इन सभी सेंटर्स पर चिकित्सक कक्ष, सैंपल कलेक्शन, दवा स्टोर, चिकित्सकों के चेंजिंग रूम (डॉनिंग एंड डोफिंग रूम) की भी व्यवस्था की जाएगी ताकि मरीज को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े।

प्रवासी राजस्थानियों के लिए बेहतर क्वारेंटाइन सुविधा

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में प्रदेश के बाहर से आने वाले प्रवासी राजस्थानियों के लिए प्रदेश भर में बेहतरीन क्वारेंटाइन सुविधा विकसित की जारी है। सभी प्रवासियों की चिकित्सा जांच भी की जा रही है। जाँच के आधार पर यह तय किया जाएगा कि आने वाले प्रवासियों में से किसे होम या संस्थागत क्वारेंटाइन में रखा जाए, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सकें। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जिला कलक्टर्स को राज्य में बाहर से आने वाले सभी प्रवासियों को बेहतर क्वारेंटाइन सुविधा देने के निर्देश दिए है। प्रदेश के सभी शहरों, गाँवों, कस्बों में क्वारेंटाइन सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। हॉम क्वारेंटाइन, संस्थागत क्वारेंटाइन, कोविड़ केयर सेन्टर और कोविड डेडिकेटेड अस्पतालों की चैन यदि प्रदेशभर में सुचारू रुप से चलेगी तो भले ही कितने ही लोग प्रदेशभर में आ जाए बढ़ते संक्रमण पर रोक लगाई जा सकती है। प्रदेश में क्वारेंटाइन सुविधाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती वीनू गुप्ता को क्वारेंटाइन कमेटी का प्रभारी बनाया है। उनके साथ कई वरिष्ठ अधिकारीगण लगातार क्वारेंटाइन सेंटर्स की मॉनिटरिंग कर हरे है।

चिकित्सा मंत्री ने किया टेली कंसलटिंग पोर्टल का शुभारंभ

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने esanjeevaniopd.in पोर्टल लॉन्च कर हैल्थ टेली कंसलटेंसी सेवा प्रदेशवासियों को समर्पित की। इस अवसर पर श्री धर्मेंद्र सिंह राठौड़ भी मौजूद थे। डॉ. शर्मा ने बताया कि कोविड के दौरान भी हालांकि सभी चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं लेकिन फिर भी जो लोग लॉकडाउन और कर्फ्यू का पालन करते हुए चिकित्सकीय परामर्श चाहते हैं वे इस पोर्टल के जरिए लाभ उठा सकते हैं। इससे आमजन गुणवत्तापूर्ण चिकित्सकीय सेवाएं घर बैठे निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आने-जाने में लगने वाले समय की भी बचत होगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में चिह्नित 100 चिकित्सा संस्थानों पर इस वेबपोर्टल एवं 30 चिकित्सकों के माध्यम से ऑनलाइन टेली-कन्सल्टेशन सेवाएं मरीजों के लिये प्रारंभ की जा रही हैं। कोई भी व्यक्ति सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक सामान्य बीमारियों के लिए टेली कंसलटेंसी सेवाएं प्राप्त कर सकता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक श्री नरेश कुमार ठकराल ने बताया कि ऑनलाइन परामर्श के लिए अब तक 240 चिकित्सकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। उन्होंने बताया कि यह योजना चरणबद्ध तरीके से सभी चिकित्सा संस्थानों में लागू की जाएगी ताकि ऑनलाइन सेवाओं के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो सकें।

विशेषाधिकारी और कार्यक्रम के नोडल अधिकारी श्री रविन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए सबसे पहले मरीज esanjeevaniopd.in पोर्टल से अपना मोबाइल नम्बर ओटीपी के माध्यम से सत्यापित कर पंजीकरण करें। इसके बाद पेशेंट आईडी और टोकन नम्बर मरीज के मोबाइल पर एसएमएस के जरिए भेज दिए जाएंगे। मरीज अपने मोबाइल नम्बर या पेशेंट आईडी या टोकन नंबर डालकर सिस्टम में लॉग-इन करें। मरीज अपनी बारी का इन्तजार करें और टोकन नम्बर आने पर ऑनलाइन चिकित्सक से परामर्श प्राप्त करें। टेली-कन्सल्टेशन पूर्ण होने पर ई-प्रिस्क्रिप्शन करें।

कुशल नेतृत्व से कोरोना नियंत्रण

चम्पा शर्मा

कोरोना महामारी से विश्व के 213 देश और क्षेत्र महामारी से जूझ रहे हैं। भारत में कोरोना पॉजिटिव और मृतकों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। प्रशासनिक सतर्कता और समझदारी से ही यह संभव हो सका है। इस बीमारी का अब तक कोई इलाज नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है। बचाव ही इसका इलाज है, इसलिए उन्होंने 'स्टे होम स्टे सेफ', 'मास्क लगाए', 'हाथ बार-बार धोएं' जैसे निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील की। प्रदेश में 19 मार्च को धारा 144 लागू की गई। राजस्थान पहला राज्य था जिसने 22 मार्च को लॉकडाउन शुरू करने की घोषणा की। संवेदनशील इलाकों को सील करवाया और कर्फ्यू के आदेश भी दिए। विदेशी विमानों से आने वाले सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई। सार्वजनिक यातायात सुविधाओं पर रोक लगा दी गई। सड़कों पर निजी वाहन भी बंद कर दिए गए। कोरोना की संख्या अचानक बढ़ने पर 7 मई को अनधिकृत लोगों के प्रवेश को रोकने के लिए राजस्थान की सीमाएं सील कर दी गईं और केवल एमएचए निर्देशों की सीमा में आने वाले लोगों को छूट दी गई।

पहली जीत

राजस्थान सरकार के सख्त फैसले और जन सहयोग के चलते भीलवाड़ा सबसे पहले कोरोना-मुक्त होकर पूरे विश्व के लिए मॉडल बना। यह राजस्थान की पहली सबसे बड़ी जीत थी। न हारे हैं, न हारेंगे संकल्प के साथ प्रदेश प्रशासन सफलता की दिशा में आगे बढ़ता रहा, और बढ़ रहा है। इसमें पुलिस, चिकित्सक, नर्सें, सफाईकर्मी जैसे कोरोना महायोद्धाओं और तन, मन, धन से सेवा करने वाले भामाशाहों का पूरा सहयोग रहा और आज भी अपनी जान की परवाह किए बिना दिन-रात सेवा में जुटे हुए हैं।

जब अमरीका, रूस, स्पेन, ब्रिटेन, इटली जैसे विश्व के सम्पन्न देशों में भी कोरोना से लोग मरते जा रहे हैं, तो हमारे लिए तो यह बहुत

बड़ी चुनौती है। इसका कोई इलाज नहीं है। इलाज की कोशिश अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। पर राजस्थान सरकार ने अपने स्तर पर प्रशंसनीय कोशिश की और कोरोना संक्रमण के नियंत्रण में सफलता भी मिली।

रोज 10 हजार टेस्ट

प्रदेश में कोविड-19 का पहला केस 2 मार्च को सामने आया। 17 मई तक प्रदेश में 231946 सैंपल लिए गए। गौरतलब है कि 2 मार्च को जब पहला केस सामने आया, इसके परीक्षण की सुविधा नहीं थी। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा के मुताबिक सैंपल पुणे लेब भेजे जा रहे थे लेकिन अब राजस्थान देश के उन राज्यों में है, जहां सर्वाधिक टेस्ट किए गए हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों के टेस्ट हो सकें, इसके लिए राज्य सरकार ने प्रतिदिन 10,000 लोगों के टेस्ट का लक्ष्य बनाकर, महज दो महीने में, 2 मई से इसकी शुरुआत भी कर दी। 14 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 7 कॉलेज और जोधपुर का एम्स राज्यभर में आरटी-पीसीआर टेस्ट कर रहे थे। तब स्वचालित न्यूक्लियर एक्सट्रेक्शन मशीनें केवल सवाई मानसिंह अस्पताल में थीं। सरकार ने सभी 33 जिलों के लिए पीसीआर मशीनें और शेष 7 मेडिकल कॉलेजों के लिए स्वचालित एक्सट्रेक्शन मशीनें ऑर्डर कीं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने जयपुर और जोधपुर में टेस्ट की गति बढ़ाने के लिए कोबास-8800 मशीनें खरीदीं ताकि दोनों शहरों में 4000-4000 टेस्ट अतिरिक्त हो सकें। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करने की कवायद इसलिए की गई ताकि प्रदेश में कोरोना की सही स्थिति का पता लगाया जा सके और आइसोलेशन की क्वारेंटाइन सुविधाओं के माध्यम से राजस्थान में वायरस को फैलने से रोका जा सके।

पर यह जंग आसान नहीं थी। राजस्थान 18 अप्रैल को रैपिड टेस्टिंग किट्स से त्वरित टेस्ट करने वाला पहला राज्य बना। इसके परिणाम भी हाथोंहाथ मिल रहे थे और संदिग्ध को तुरन्त आइसोलेट करना आसान हो रहा था। पर 21 अप्रैल को रैपिड टेस्टिंग किट्स का इस्तेमाल बंद करना पड़ा क्योंकि जांचें सही नहीं आ रही थीं। आईसीएमआर की सलाह पर इनसे तब तक टेस्ट बंद करना पड़ा जब तक कि जांच के परिणाम प्रामाणिक नहीं हों। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा के

मुताबिक 29 अप्रैल को कोरोना की त्वरित जांच के लिए टी.बी. टेस्ट करने वाली मशीनें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और कोटा के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में भेजी गईं। यह निर्णय आईसीएमआर की अनुमति से लिया गया। मरीजों की संख्या को देखते हुए निजी अस्पतालों की भी जरूरत थी। पर ये संक्रमण से डर रहे थे। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 और राजस्थान एपिडेमिक डिजिजीज एक्ट, 1957 के तहत सरकार ने आदेश जारी किए और अकेले जयपुर जिले में 1377 पलंग की क्षमता वाले 84 निजी अस्पताल रिजर्व किए गए। आवश्यकता पड़ने पर महज दो घंटे पहले की सूचना पर निजी अस्पतालों के अधिकारियों को कोरोना के इलाज, आइसोलेशन और क्वारेंटाइन के लिए अपना अस्पताल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अथवा उप-डिवीजन अधिकारी को सौंपना होगा।

पीपीई किट

कोरोना वायरस से बचने के लिए बड़े पैमाने पर सुरक्षा उपकरणों की जरूरत थी। खासतौर से स्वास्थ्यकर्मियों के लिए। चिकित्सक, नर्सें और अन्य स्टाफ जब खुद कोरोना वायरस से सुरक्षित रहेंगे तभी तो

संक्रमित मरीजों का इलाज कर पाएंगे। सरकार ने उनके लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) उपलब्ध करवाए। प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा शहर की न्यू जील सीजनल वियर कंपनी में 400 से अधिक आदिवासी महिलाएं रोजाना 3000 किट तैयार कर रही हैं।

मुख्यमंत्री राहत कोष

कोरोना पीड़ितों की आर्थिक मदद के लिए राज्य सरकार ने राहत कोष बनाया और इसी के तहत कोविड-19 का अलग से राहत कोष बनाया गया। एसबीआई की जयपुर सचिवालय शाखा में इसके लिए अलग से खाता खुलवाया गया। इसका खाता नंबर 39233225397 और IFSC कोड SBIN 0031031 है। मुख्यमंत्री की अपील पर जरूरतमंदों की मदद से लिए दान-दाता, भामाशाह और आमजन ने बढ़-चढ़कर सहयोग किया और अब भी कर रहे हैं।

इलाज

इस महामारी का कोई इलाज ही नहीं है, तो इसका उपचार कैसे किया जाए? सरकार और चिकित्सकों के सामने बड़ी कठिन समस्या थी। शुरुआत में राजस्थान में कोरोना को मलेरिया, स्वाइन फ्लू और एचआईवी की दवाओं का कॉम्बिनेशन दिया गया। सफलता मिली। तीन मरीज ठीक हुए। देश के कई राज्यों में प्लाज़्मा थैरेपी से उत्साहजनक परिणाम मिल रहे थे। राजस्थान सरकार ने भी जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में कोरोना के गंभीर रोगियों पर इस थैरेपी से उपचार करने की आईसीएमआर से अनुमति ली। राजस्थान इस थैरेपी का सफलतापूर्वक प्रयोग करने वाला देश का चौथा राज्य बना। एसएमएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ने दो रोगियों का इलाज किया। इसके बाद एसएमएस

मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को आईसीएमआर ने 20 और रोगियों की जिम्मेदारी दी। राजस्थान सरकार ने आईसीएमआर से जोधपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में भी क्लिनिकल ट्रायल (नैदानिक परीक्षण) के लिए प्लाज़्मा थैरेपी की अनुमति दी। इस तरह अब राज्य में दो सरकारी और एक निजी अस्पताल (महात्मा गांधी अस्पताल) में इस थैरेपी का प्रयोग किया जा रहा है।

वेब पोर्टल

विगत 4 मई को स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने एक वेब पोर्टल esanjeevaniopd.in लांच किया था। इस पोर्टल पर लोग कोरोना से सम्बन्धित नि:शुल्क ऑनलाइन परामर्श ले रहे हैं। इससे सुरक्षा के साथ-साथ समय की बचत हो रही है। ये सेवाएं राज्य के तय अस्पताल और चिकित्सक दे रहे हैं। राजस्थान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक राजेन्द्र कुमार ठकराल के मुताबिक 4 मई तक 240 चिकित्सकों को ऑनलाइन परामर्श के लिए प्रशिक्षित किया जा चुका था। केन्द्रक अधिकारी (नोडल ऑफिसर) के अनुसार इस सुविधा के उपयोग के लिए

पहले इस पोर्टल आईडी पर खुद को रजिस्टर करना होता है और ओटीपी के जरिए अपने मोबाइल नंबर को प्रामाणिक करना होता है। इसके बाद रोगी के मोबाइल पर उसका आईडी और टोकन नंबर भेजा जाता है। रोगी परामर्श के लिए अपना मोबाइल नंबर या आईडी या टोकन नंबर डाल सकते हैं। इसके बाद अपनी बारी के लिए थोड़ा इंतजार करना होता है। राजस्थान सरकार ने भारतीय स्टार्टअप मेडकोर्ड्स के माध्यम से आयु और सेहत साथी एप के साथ खास साझेदारी की है। इस एप पर कोरोना रोगी लॉकडाउन में ऑनलाइन परामर्श ले सकते हैं।

फिलहाल सफलता की मंजिल भले ही दूर हो, रास्ते पथरीले हों, पर यह तो तय है कि राजस्थान सरकार की समझदारी, संवेदनशीलता और सहयोग से कोरोना के नियंत्रण में निश्चित ही सफलता मिलेगी।

लेखिका वरिष्ठ पत्रकार हैं.

पैडल हैन्ड सैनेटाइज मशीन लगाई

कोरोना महामारी से उत्पन्न संक्रमण की गम्भीर स्थिति को देखते हुए सचिवालय परिसर स्थित सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग में पैडल हैन्ड सैनेटाइज मशीन लगाई गई।

विभाग के आयुक्त श्री महेन्द्र सोनी ने मशीन का उद्घाटन करते हुए इसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों एवं विभाग में आने वाले पत्रकारों के लिए आवश्यक एवं बेहद उपयोगी बताया।

इस सैनेटाइज मशीन को पैरों से इस्तेमाल किया जाता है। बायें पैर से दबाने पर नल से लिक्विड सोप निकलता है तथा दायें पैर से दबाने पर पानी निकलता है। इस प्रकार बिना नल को हाथ से छुए, हाथों को सैनेटाइज किया जा सकता है।

सरकार का हाथ अन्नदाता के साथ

ओटाराम चौधरी

वर्तमान विश्व एक नए संकट के दौर से गुजर रहा है। कोरोना महामारी के रूप में आए इस संकट ने प्रत्येक देश को आर्थिक मोर्चे पर अपनी नीतियों को पुनः निर्धारित करने हेतु विवश किया है। इस संकट से उभरने में सभी राज्य भी विकास में निवेश की नीतियों को परिवर्तित कर रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में कोरोना संकट को लेकर जो प्रबंधन किया है उसकी सराहना विश्व स्तर पर हो रही है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए किये गये प्रबंधन ने सामाजिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, चिकित्सा व्यवस्था, कृषक कल्याण के माध्यम से सभी वर्गों यथा श्रमिक, पेंशनर्स, गरीब एवं वंचित, किसान को राहत देने का अभूतपूर्व कार्य किया है। साथ ही मध्यम वर्ग, व्यवसायी, एमएसएमई के लिए भी अलग योजना बनाई गई है।

राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग 25 प्रतिशत है एवं इसमें एक तिहाई योगदान पशुपालन गतिविधियों का है। राज्य की 60 प्रतिशत आबादी कृषि क्षेत्र पर निर्भर है एवं पशु जनसंख्या देश में सर्वाधिक है। राज्य में बहुत सी फसलों यथा जीरा, धनियां, ईसबगोल, सरसों, चना, जौ, मूंगफली, सोयाबीन आदि एवं दूध उत्पादन बहुलता के बावजूद भी राज्य में कृषि उद्योगों का अपेक्षित विकास नहीं हो पाने के कारण राज्य के किसानों को आपूर्ति एवं मूल्य संवर्धन शृंखला का विकास नहीं हो सका। राज्य में कृषि उद्योगों के विकास के लिए विशिष्ट योजनाओं का अभाव, प्रक्रियात्मक मुद्दे, कृषि उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण का अभाव एवं कृषि निर्यात संभावनाओं के दोहन की ओर कम झुकाव मुख्य रूप से इस कमजोर विकास के कारण रहे हैं। अत: उक्त सभी मुद्दों का समाधान करते हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ पर एक नई समन्वित ''राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति- 2019'' लागू की है।

कोरोना संकट को देखते हुए कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के विशेष प्रयास शुरू किए गए हैं। इस नई नीति के तहत लगभग 60 करोड़ रुपये की 39 परियोजनाओं के प्रस्ताव प्राप्त हो गए हैं। इनमें से राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति ने अपनी पहली बैठक में 15.94 करोड़ रुपये की 8 परियोजनाओं के लिए 4.32 करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकृत किया है। इनमें से ढाई करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान महिला किसानों की परियोजनाओं के लिए मंजूर हुआ है। 8 में से 3 परियोजनाएं जोधपुर जिले की महिला किसानों द्वारा स्थापित की जा रही हैं। स्वीकृत की गई परियोजनाएं वेयर हाउस, ग्रेडिंग, दुग्ध प्रसंस्करण प्लान्ट, लहसुन-प्याज डिहाइड्रेशन प्लान्ट, क्लीनिंग आदि से संबधित हैं।

सहकारिता विभाग द्वारा प्रदेश में कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए शृंखलाबद्ध इकाइयों (प्रसंस्करण, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज आदि) की स्थापना हेतु अपेक्स

बैंक एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों से वित्त पोषण की योजना लागू की गई है। सहकारिता मंत्री श्री उदयलाल आंजना का कहना है कि इसके तहत इकाई स्थापित करने वाले कृषकों एवं उद्यमियों को 500 करोड़ रुपये के ऋण उपलब्ध कराएं जाएंगे। साथ ही राज्य में स्थापित होने वाले नए एवं वर्तमान में स्थापित कृषि प्रसंस्करण और कृषि व्यवसाय उद्यम जो आधुनिकीकरण, विस्तार या विविधीकरण को अपना रहे हैं, को वित्त पोषण सहकारी बैंकों द्वारा किया जाएगा।

सहकारी बैंकों द्वारा इकाइयों की स्थापना के लिए 75 प्रतिशत तक ऋण दिया जाएगा, जिसकी ब्याज दर 10 प्रतिशत होगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से इस ब्याज दर में कृषक एवं कृषक समूह द्वारा स्थापित होने वाली इकाइयों पर 5 वर्ष के लिए 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान जो अधिकतम 1 करोड़ रुपये होगा जबकि अन्य उद्यमियों को 5 वर्ष के लिए 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान जो अधिकतम 50 लाख रुपये होगा।

इसी प्रकार कृषक एवं कृषक समूहों द्वारा स्थापित होने वाली इकाई की लागत में होने वाले व्यय पर अनुदान के रूप में पूंजीगत लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 1 करोड़ रुपये तथा अन्य उद्यमियों के लिए पूंजीगत लागत का 25 प्रतिशत या अधिकतम 50 लाख रुपये का अनुदान भी दिया जाएगा। इकाई स्थापित करने वाले उद्यमियों को राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड स्तर पर स्थापित की जाने वाली एकल खिड़की के माध्यम से वित्त पोषण हेतु अपेक्स बैंक को भेजे जाएंगे।

योजना के तहत बैंक ऋण पर आदिवासी क्षेत्रों, पिछड़े जिलों में स्थित इकाइयों, अनुसूचित जाति व जनजाति, महिला एवं 35 वर्ष से कम आयु के उद्यमियों को भी 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जाएगा। सरकार के इस निर्णय से कृषि उद्योगों का विकास होगा वहीं किसानों को आपूर्ति एवं मूल्य संवर्धन श्रृंखला का भी विकास होगा। इससे राज्य में कृषि निर्यातकों को बढ़ावा एवं बिचौलियों से किसानों को मुक्ति मिलेगी।

किसान एवं किसान संगठनों द्वारा इकाइयां स्थापित होने पर ऋण एवं पूंजीगत लागत के रूप में 2 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य की विशिष्ट फसलों जैसे जीरा, धनियां, मेथी, सौंफ, अजवायन, ग्वार, ईसबगोल, दलहन, तिलहन, मेहंदी, ताजा

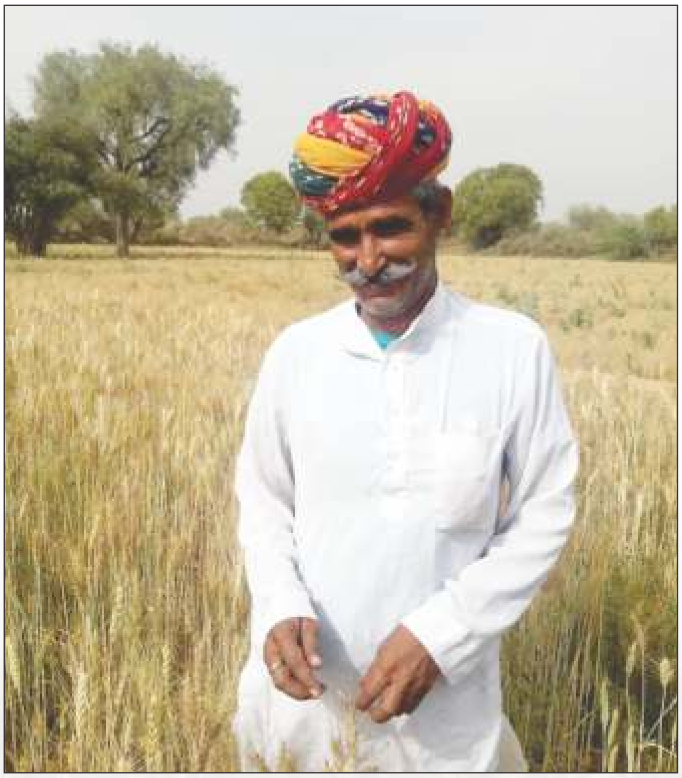

सब्जियां, किन्नू, अनार, आदि के मूल्य संवर्धन तथा निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा तथा इन उत्पादों की पहुंच राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर होगी।

उल्लेखनीय है कि राज्य में अल्प समय में ही 39 परियोजनाओं के प्रस्ताव प्राप्त हो गए हैं। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति के अध्यक्ष एवं प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं सहकारिता, श्री नरेश पाल गंगवार के अनुसार राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, नाबार्ड एवं शीर्ष सहकारी बैंक के माध्यम से कृषकों एवं उद्यमियों को इस नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहित कर राज्य में कृषि व्यवस्था को मजबूत बनाने का कार्य किया जा रहा है। इससे प्रदेश में कृषि प्रसंस्करण एवं संबंधित क्षेत्रों जैसे डेयरी, पोल्ट्री, शहद प्रसंस्करण, ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं क्रय विक्रय सहकारी समितियों के स्तर पर कृषकों को भंडारण, क्लीनिंग, ग्रेडिंग, पैकिंग आदि की सुविधा उपलब्ध

कराने में मदद मिलेगी। कृषि क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना, रोजगार सृजन तथा किसानों को होने वाली फसलोत्तर हानि में कमी कर बाजार में किसानों को अतिरिक्त विकल्प की उपलब्धता भी हो पाएगी।

15.94 करोड़ रुपये की 8 परियोजनाओं को मंजूरी

भारत की दो तिहाई आबादी कृषि पर निर्भर है और यह पूरे देश का खाद्यान्न उत्पादन कर रही है। राजस्थान की 60 प्रतिशत आबादी कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। राज्य की अर्थव्यवस्था में लगभग 25 प्रतिशत योगदान कृषि क्षेत्र का है एवं इसमें एक तिहाई योगदान पशुपालन गतिविधियों का है। आबादी का यह हिस्सा अपनी आय के लिए कृषि पर ही निर्भर है। कोरोना महामारी से बनी विपरीत परिस्थितियों ने किसान पर भी प्रहार किया है। ऐसे समय में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने किसानों के हित में कदम उठाकर राहत देने का महत्त्वपूर्ण कार्य किया है।

कोरोना संकट के दौरान राज्य सरकार द्वारा सहकारी अल्पकालीन फसली ऋण चुकाने की अवधि को बढ़ाना, ट्राइबल एरिया में मक्का बीज के मिनी किट का नि:शुल्क वितरण, सीमान्त एवं लघु किसानों को नि:शुल्क बाजरा बीज मिनी किट का वितरण, फसल बीमा योजना में प्रीमियम का शीघ्र भुगतान, समर्थन मूल्य खरीद में केन्द्रों की संख्या बढ़ाना, किसानों से सीधी खरीद हेतु जीएसएस, केवीएसएस एवं भंडार गृहों को निजी गौण मंडी का दर्जा देना, ओलावृष्टि प्रभावित जिलों में नुकसान की स्थिति का आकलन करवाना, टिड्डी नियंत्रण के लिये तैयारियां, नि:शुल्क ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र किराए पर उपलब्ध करवाना, सहकारी अल्पकालीन फसली ऋण वितरण कार्यक्रम, खाद एवं बीज का अग्रिम भंडारण, किसानों को बारदाने की उपलब्धता, दीर्घकालीन कृषि ऋण की पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना की अवधि बढ़ाना, किसानों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए टोल फ्री नम्बर जैसे अनेक निर्णय लेकर किसानों को राहत देने का विशेष कार्य किया है।

कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेश के किसानों को राहत देते हुए खरीफ-2019 के सहकारी अल्पकालीन फसली ऋणों की चुकारा अवधि 31 मार्च, 2020 से 30 जून, 2020 अथवा खरीफ फसली ऋण लेने की तिथि से एक वर्ष, जो भी पहले हो तक बढ़ा दी गई। इससे राज्य में केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से वर्ष 2019 में खरीफ फसल के लिए ऋण लेने वाले करीब 22 लाख किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज सुविधा का लाभ मिल सकेगा।

30 जून तक मिलेगा 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ

राज्य सरकार ने सहकारी भूमि विकास बैंकों से दीर्घकालीन कृषि ऋण लेने वाले काश्तकारों को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना की अवधि को 31 मार्च, 2020 से बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर दिया है। अब समय पर ऋण का चुकारा करने वाले काश्तकारों को 6.65 प्रतिशत ब्याज दर से कृषि ऋण का लाभ मिल पाएगा।

केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा वितरित होने वाला अल्पकालीन फसली ऋण खरीफ सीजन में 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक तथा रबी सीजन में 1 सितम्बर से 31 मार्च तक किसानों को वितरित किया जाता है लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते देशभर में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन प्रथम चरण होने के कारण खरीफ सीजन में ऋण वितरण की शुरुआत 16 अप्रैल से की गई। 18 मई तक 7 लाख 56 हजार से अधिक किसानों को 2292 करोड़ रुपये से अधिक का फसली ऋण वितरित हो चुका है।

कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम के लिए चल रहे लॉकडाउन के बीच रबी फसलों की कटाई के दौरान काश्तकारों को फसल पैकिंग के लिए बारदाने की जरूरत रहती है। बारदाना को लेकर काश्तकारों को कहीं भी समस्या नहीं हो, इसके लिए सहकारिता एवं कृषि विभाग द्वारा पूरे बंदोबश्त किए गए। कृषि उपज मंडी समितियों एवं क्रय-विक्रय सहकारी

समितियों में किसानों को फसल पैकिंग के लिए पर्याप्त मात्रा में बारदाना उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई।

कोरोना संक्रमण एवं लॉकडाउन के चलते कृषि कार्यों में आ रही कठिनाई को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने आर्थिक रूप से कमजोर लघु एवं सीमांत किसानों को फसल कटाई, थ्रेसिंग एवं अन्य कृषि गतिविधियों के लिए नि:शुल्क ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र किराए पर उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए थे। इस पर विभागीय अधिकारियों ने कृषि यंत्र निर्माता टैफे कम्पनी से समन्वय कर अजमेर, अलवर, बारां, भरतपुर, बूंदी, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनूं, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक, धौलपुर, जालोर, पाली, बाड़मेर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बीकानेर एवं दौसा जिलों में यह सुविधा शुरू करवाई।

कंट्रोल रूम एवं एसएमएस की सुविधा

आर्थिक रूप से कमजोर लघु एवं सीमांत किसान इस योजना का लाभ उठाने के लिए 9282222885 नम्बर पर एसएमएस भेजकर जेफार्म सर्विसेज से सम्पर्क कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट की कुछ समस्या पर कृषि उपज के सुचारु परिवहन के लिए किसान एवं व्यापारी ''किसान रथ'' एप के उपयोग की सुविधा दी गई। इसमें लगभग 5 लाख ट्रक एवं 20 हजार ट्रैक्टर जुड़े हुए हैं, जो किसानों के उत्पाद जैसे अनाज, दालें, सब्जियां, फल आदि को प्रतिस्पर्धी रेट पर मंडियों, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट आदि तक ले जाएंगे। कृषि एवं इससे संबद्ध विभिन्न गतिविधियों के कोरोना महामारी से जुड़े विषयों से संबंधित जानकारी के लिए यहां पंत कृषि भवन में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। कंट्रोल रूम सुबह 8 बजे से सायं 8 बजे तक कार्य कर रहा है। किसान एवं कृषि से जुड़े अन्य हितधारक कंट्रोल रूम के टेलीफोन नम्बर 0141-2227471 पर कॉल करके आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

किसानों से सीधी खरीद हेतु गौण मंडियों में की वृद्धि

किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने तथा खरीद की प्रक्रिया को गति देने के लिए राज्य सरकार ने 1522 से अधिक प्रसंस्करण इकाइयों को किसानों से सीधी खरीद करने की अनुमति दी है।

साथ ही 604 सहकारी समितियों को निजी गौण मण्डी के रूप में अधिसूचित किया गया। इसके अलावा राजस्थान राज्य भण्डारण निगम के 93 गोदामों को भी निजी गौण मंडी घोषित किया है।

निजी गौण मंडी घोषित सहकारी समितियों को कार्य करने में वित्तीय सहायता की कमी नहीं हो इसके लिए सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों को नियमानुसार बिना प्रतिभूति के साख-सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश भी प्रदान कर दिये गये हैं, जिससे किसानों को अपने खेत एवं गांव के नजदीक ही उपज बेचान की सुविधा के साथ-साथ कृषि उपज मंडियों के अनुरूप ही कृषि जिन्सों को खुली नीलामी में बेचकर प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य की सुविधा भी मिलेगी।

टिड्डी नियंत्रण के लिए तैयारियां

टिड्डी प्रकोप की आशंका के मद्देनजर लगातार सर्वे एवं मॉनिटरिंग की जा रही है। टिड्डी प्रभावित जिलों में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जा चुके हैं। राज्य में सफल टिड्डी नियंत्रण एवं प्रबंधन के लिए केन्द्र सरकार से 84.62 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया। भारत-पाक सीमावर्ती क्षेत्र में टिड्डियों के प्रवेश को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत गंभीर हैं।

उन्होंने अभी से इन्हें नियंत्रित करने की प्रभावी योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं ताकि बाद में यह समस्या बढ़े नहीं। उन्होंने संबंधित जिला कलक्टरों के जरिए कंटींजेंसी प्लान तैयार करवाने के निर्देश भी दिए हैं। पिछली बार टिड्डी नियंत्रण को लेकर राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को केंद्र सरकार ने सराहा था।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2019 तक का प्रीमियम का भुगतान राज्य द्वारा किया जा चुका है जिससे किसानों को फसल नष्ट होने पर जल्द से जल्द इसका लाभ मिल सकेगा।

समर्थन मूल्य पर सरसों, चना एवं गेहूं की खरीद

कोविड-19 से उत्पन्न हुई परिस्थितियों के कारण समर्थन मूल्य पर सरसों, चना एवं गेहूं की खरीद पर भी असर पड़ा है। ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश की वजह से किसानों को दिक्कत हुई है लेकिन मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की दूरदर्शी सोच की वजह से किसानों से जिन्सों की खरीद को आसान बनाया गया है। भारत सरकार द्वारा राजस्थान को समर्थन मूल्य पर गेहूं के लिए 17 लाख मीट्रिक टन, सरसों 10.46 लाख मीट्रिक टन एवं चना 6.15 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य दिया गया है।

राजस्थान में इससे और बेहतर रणनीति को अपनाते हुए किसानों को उनके खेत के समीप ही खरीद केन्द्र की सुविधा उपलब्ध कराई गई। गेहूं के लिए एफसीआई एवं राजफैड के द्वारा 425 से अधिक खरीद केन्द्र खोले गए जबकि सरसों एवं चने के लिए राजफैड द्वारा 799 खरीद केन्द्रों को खोला गया। जहां पहले सरसों एवं चने के 250 से 300 केन्द्र होते थे। अब दोगुने से अधिक खरीद केन्द्रों के माध्यम से किसानों से जिन्सों की खरीद को सुनिश्चित किया गया है। गेहूं का समर्थन मूल्य 1925, सरसों का 4425 तथा चने का 4875 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है।

राज्य में खरीद के लिए क्रय विक्रय सहकारी समितियों के अलावा ग्राम सेवा सहकारी समितियों को भी केन्द्र बनाया गया है। इस सुविधा से किसानों को अपने नजदीक उपज बेचान का केन्द्र मिला है। वहीं कोरोना महामारी के चलते एक ही दिन में अधिकतम किसानों से खरीद हो रही है।

तीन दिन में हो रहा है किसानों को भुगतान

प्रदेश में किसानों से होने वाली समर्थन मूल्य पर खरीद में त्वरित भुगतान सुनिश्चित करने के लिये सरकार द्वारा वेयर हाउस रिसिप्ट जारी करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है। सरकार के इस कदम से खरीद केन्द्र से वेयर हाउस भेजे जाने वाली उपज त्वरित ढंग से जमा होने के परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार से भुगतान भी शीघ्र प्राप्त होने लगा है, जिससे किसानों को 3 दिवस की अल्पावधि में ही उपज का भुगतान उनके खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है।

नियंत्रण कक्ष स्थापित

समर्थन मूल्य पर सरसों एवं चना खरीद के लिए राजफैड मुख्यालय पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। यह कक्ष महाप्रबंधक (वाणिज्य) के अधीन कार्य कर रहा है। नियंत्रण प्रकोष्ठ समस्त आवश्यक व्यवस्थाओं के सुचारु रूप से संचालन एवं समस्याओं के समाधान के लिए कार्य कर रहा है। इसके लिए टोल फ्री नम्बर 1800-180-6001 तथा लिखित शिकायत के लिए rajfed.kissansamadhan @gmail.com निर्धारित किया गया है।

सहकारिता के कोरोना योद्धा

लॉकडाउन के दौरान 10 लाख परिवारों को वितरण हुई खाद्य सामग्री

देश में 25 मार्च से लॉकडाउन होने से राजस्थान के निवासियों को घर-घर तक वाजिब दरों पर खाद्य सामग्री पहुंचाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। इस चुनौती को सहकारिता विभाग ने स्वीकार किया और सहकारिता उपभोक्ता भण्डारों के माध्यम से उचित दरों पर गुणवत्तापूर्ण सामग्री पहुंचाने की पहल की गई। राज्य के सभी जिला कलक्टरों के साथ समन्वय कर जिलों की मांग के अनुसार वैन के संचालन तथा विभाग एवं सहकारी संस्थाओं के 1000 से अधिक कार्मिकों की संयुक्त टीम बनाकर रूट मैप के अनुसार खाद्य सामग्री के घर-घर वितरण की योजना बनाई गई। प्रमुख शासन सचिव नरेश पाल गंगवार के अनुसार राज्य में संचालित 34 उपभोक्ता भण्डारों एवं जयपुर में कॉनफैड को घर-घर तक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई। सहकारिता के कोरोना योद्धाओं ने राज्य के कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में विशेषतौर पर अपनी सेवाएं देकर सहकारिता की पहचान को सिद्ध किया है। लॉकडाउन के दौरान विभाग एवं संस्थाओं ने एक टीम के रूप में कार्य कर ''एक सबके लिए - सब एक के लिए'' की भावना को साकार रूप दिया है।

सबसे पहले भीलवाड़ा जिले में 21 मोबाइल वैन के द्वारा लोगों को खाद्य सामग्री पहुंचाना प्रारम्भ किया गया और पूरे जिले में 1.25 लाख से अधिक परिवारों को खाद्य सामग्री का वितरण किया जा चुका है। इस प्रकार लोगों को राहत पहुंचाने के लिए अजमेर संभाग में 33, भरतपुर संभाग में 36, बीकानेर संभाग में 103, जयपुर संभाग में 22, जोधपुर संभाग में 88, कोटा संभाग में 20 तथा उदयपुर संभाग में 24 मोबाइल वैन सहित कुल 326 वैन का संचालन प्रारंभ कर दिया गया और आज राज्य के 10 लाख से अधिक परिवारों को उचित मूल्यों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जा चुकी है तथा प्रतिदिन औसतन 23 हजार परिवारों को खाद्य सामग्री का वितरण हो रहा है। इसके अलावा 1 लाख राशन किट वितरित कर परिवारों को राहत पहुंचाई है। कोरोना वॉरियर्स द्वारा शहरों के साथ-साथ गांवों में भी वैन के जरिए डोर टू डोर खाद्य सामग्री का वितरण किया जा रहा है।

खाद्य सामग्री वितरण में लगे सहकारिता के कार्मिकों की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। कार्मिकों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए उपभोक्ता भण्डारों की ओर से नि:शुल्क सेनेटाइजर एवं मास्क उपलब्ध कराए गए हैं। उन्हें खाद्य सामग्री वितरण के दौरान उचित दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।

संकट के इस दौर में प्रदेशवासियों को सही मूल्य पर खाद्य सामग्री मिले इसके लिए वितरण में लगी प्रत्येक वैन पर वितरित होने वाली

सामग्री की रेट लिस्ट भी लगाई जाती है ताकि खरीददारी के दौरान लोगों के मन में किसी प्रकार का संशय पैदा नहीं हो।

प्रत्येक जिले में संचालित हो रही खाद्य सामग्री वैन की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए जिला स्तर पर उप रजिस्ट्रार, संभाग स्तर पर खण्डीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार को जिम्मेदारी दी गई है। ये अधिकारी प्रतिदिन जिला कलक्टर से समन्वय बनाकर निर्देशों के अनुसार घर-घर तक खाद्य सामग्री वितरण को सुनिश्चित कर रहे हैं।

राज्य में 34 उपभोक्ता भण्डारों तथा 150 से अधिक केवीएसएस एवं पीडीएस का कार्य कर रही ग्राम सेवा सहकारी समितियां भी लॉकडाउन के दौरान लोगों को जरूरत के अनुसार खाद्य सामग्री उपलब्ध करा रही हैं। ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं क्रय-विक्रय सहकारी समितियों को उनकी मांग के अनुरूप उपभोक्ता भण्डार खाद्य सामग्री सप्लाई कर रहे हैं तथा जहां केवीएसएस एवं सुपर स्टोर पहले से ही खाद्य सामग्री का वितरण कर रहे हैं, उनके द्वारा भी जीएसएस को सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है।

वैन के माध्यम से वितरित हो रही खाद्य सामग्री में मुख्यतया आटा, सरसों तेल, सोयाबीन तेल, मूंग दाल, चना दाल, शक्कर, चावल, नमक, मिर्ची, हल्दी, धनियां, नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, सर्फ पाउडर, चाय पत्ती सहित अन्य वस्तुएं आमजन को मिल रही हैं।

पेंशनर्स को टोकन के आधार पर विशेष सुविधा

कोरोना वायरस संक्रमण से पेंशनर्स को बचाने के उद्देश्य से उपभोक्ता संघ द्वारा पेंशनर्स से एनएसी बिल क्लेम प्राप्त करने के लिए नई व्यवस्था प्रारम्भ की गई। नई व्यवस्था के तहत पेंशनर्स को अपने क्लेम

प्रस्तुत करने के लिए टोकन दिया गया तथा पेंशन डायरी वापिस प्राप्त करने के लिए एक निश्चित तिथि नियत की गई ताकि कार्यालय परिसर में पेंशनर्स के ठहराव के दौरान समूह बनने से रोका जा सके।

नेहरू प्लेस स्थित उपभोक्ता संघ के कार्यालय में पेंशनर्स की भीड़ इकट्ठा न हो तथा उन्हें संभावित कोरोना संक्रमण से बचाया जा सके, इसके लिए यह कदम उठाया गया है। इससे पेंशनर्स को कार्यालय में अधिक समय तक इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा।

उपभोक्ता संघ को सभी काउण्टर एवं कार्यालयों में सेनेटाइजर उपलब्ध कराने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं ताकि संक्रमण से तात्कालिक रूप से बचा जा सके।

–ओटाराम

कोटा के विद्यार्थियों को घर पहुंचाने के प्रयास

हर कोई कर रहा है मुक्तकंठ से प्रशंसा

राज्य सरकार के प्रयासों से कोटा के हजारों विद्यार्थी अपने-अपने घर सकुशल पहुंच रहे हैं। अब तक कुल 46687 विद्यार्थी राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित ट्रेन और बसों से अपने गंतव्य तक पहुंच चुके हैं। अब तक इस कार्य के लिए 1048 बस और 16 ट्रेन काम में ली गईं। कुल 1048 बसों से 28491 विद्यार्थी और 16 ट्रेन से 18196 विद्यार्थी अपने गंतव्य तक पहुंचाए गए। विद्यार्थियों को रवाना करने से पहले उन्हें मास्क, फूड पैकेट एवं पानी की बोतलें प्रदान की गईं। रवाना करने से पहले सभी विद्यार्थियों की मेडिकल स्क्रीनिंग की गई। विद्यार्थियों को अपने गंतव्य भिजवाने की इस प्रक्रिया की हर किसी के द्वारा प्रशंसा की जा रही है। कई राज्य सरकारें और विद्यार्थी राजस्थान सरकार की व्यवस्थाओं की मुक्तकंठ से प्रशंसा कर चुके हैं।

रक्षक, सेवक और योद्धा भी...

लक्ष्मी प्रसाद पंत

छाया : सविता चौहान

कोरोना महामारी के बीच पुलिस के जितने जबरदस्त मानवीय चेहरे आज हमारे सामने हैं, उसने खाकी को देखने वाले हमारे उदासीन, खौफ भरे और 'इनकी न दोस्ती अच्छी, न दुश्मनी' वाले परम्परागत नजरिए को बदल दिया है। कह सकते हैं कि पुलिस की योग्यता और सक्षमता मुखौटों के बीच छिपी हुई थी। पुलिस से प्यार करने के जो असाधारण दृश्य आज हमारे सामने हैं वे बताते हैं कि खाकी के कठोर और सपाट चेहरों के भीतर कितना कुछ अनदेखा-अनकहा छिपा हुआ है।

राजस्थान का भीलवाड़ा हो, राजधानी जयपुर या कोरोना से तड़पता देश का कोई भी हिस्सा, भीषण मानवीय संकट के बीच अस्पतालों में डॉक्टर और चिकित्साकर्मी कोरोना के विरुद्ध जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वही सड़क पर पुलिसकर्मी भी लड़ रहे हैं। डॉक्टर तो इलाज कर रहे हैं, लेकिन हमारे शहरों-गांवों को बीमार होने से सिर्फ पुलिस वाले ही रोक रहे हैं। दरअसल, कोरोना की बीमारी का लॉकडाउन ही इलाज है और यह इलाज पुलिस कर रही है। दिलचस्प यह है कि हर चीज में पलिस से घृणा और नफरत करने वाले भी इन दिनों खाकी की तारीफ कर रहे हैं। वैज्ञानिक-विचारक भी कहने लगे हैं कि भय और आतंक के बीच पुलिस को लेकर जो सामाजिक प्रक्रिया आ रही है वह असाधारण है। इस विकटतम संकट में पुलिस ने जो गजब का काम किया है उसने हमारे दिल-दिमाग की सारी खिड़कियों को खोल दिया है।

कोरोनाकाल के कुछ शानदार उदाहरण पेश हैं। अक्सर लाठी की जुबां से बात करने वाले खाकी वर्दी वालों के हाथों में माइक और जुबां पर आग्रहपूर्ण गीत हैं। कड़क और कर्कश आवाज सुरीली हो चली है। लॉकडाउन की पालना दिलकश नगमों और खूबसूरत अंदाज में करवा रहे हैं। व्यस्ततम चौराहों पर केवल वसूली के लिए आने का आरोप सहते पुलिसकर्मी आज उन्हीं चौराहों पर खड़े हैं, जहां उनके सिवा कोई नहीं है। ठीक वहीं, जहां कोरोना के रक्तबीज जान लेने को बेचैन हैं। वहीं पुलिस अन्नदेवता बनी हुई है। हर फ्लाईओवर के नीचे या अंधेरे कोने में जमा सैकड़ों निर्धन, बेसहारा दिन में तीन बार पुलिस के हाथों खाने के पैकेट लेते वक्त यह चेहरा देखते हैं। यही चेहरे पुलिस को लेकर हमारे पुराने पाखंड और पूर्वाग्रहों को सिलसिलेवार तोड़ रहे हैं।

जयपुर के रामगंज में जब स्थानीय लोगों ने मेडिकल टीमों से जांच में आनाकानी की तो 25 पुलिस वाले सबसे पहले आगे आए और सैंपल दिए। उद्देश्य बताते-बताते वे क्लीनिकल ट्रायल के सब्जेक्ट की तरह पेश आए। जैसे कह रहे हों - लो... हमसे शुरू करो। हमें न मृत्यु का डर न कोरोना का आतंक। हम एक निराशाजनक वर्तमान से गुजर रहे हैं, लेकिन पुलिस के ये भावनात्मक चेहरे बहुत सुकून देते हैं।

इन चेहरों के कुछ दर्द भी हैं। डॉक्टरों के साथ ही पुलिस वाले भी महीनों से घर नहीं गए हैं। थाने की बेरकों में सो रहे हैं। संवेदनशील इलाकों में सर्वे टीम का सुरक्षा कवच बने हुए हैं। दुर्भाग्यवश राजस्थान पुलिस के 40 पुलिसकर्मी और 60 बोर्डर होमगार्ड्स जवान कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन किसी ने मैदान नहीं छोड़ा है। युद्ध की तरह एक योद्धा के घायल होने पर दूसरा उसकी जगह ले रहा है।

कोरोनाकाल में हर तरफ पुलिस की कथा-कहानियों की चर्चा है। जयपुर पुलिस कमिश्नर आनन्द श्रीवास्तव के इन शब्दों पर भी गौर करें - 'पुलिस को लेकर एक पूर्वाग्रह पलता रहा है। हम या तो नायक होते हैं या खलनायक, हमें देखने का यही नजरिया है। अगर आप पुलिसफोर्स को दिल से महसूस करेंगे तो सोच के दायरे खुल जाएंगे। यह समय ऐसी गिरहबान खोलने के लिए सबसे सही है। हमें देखिए और फिर से सोचिए।'

सच कहूं तो एक पत्रकार के तौर पर पुलिस को देखने का मेरा दर्शनशास्त्र भी बदला है। ●

लेखक दैनिक भास्कर के संपादक हैं
साभार : दैनिक भास्कर

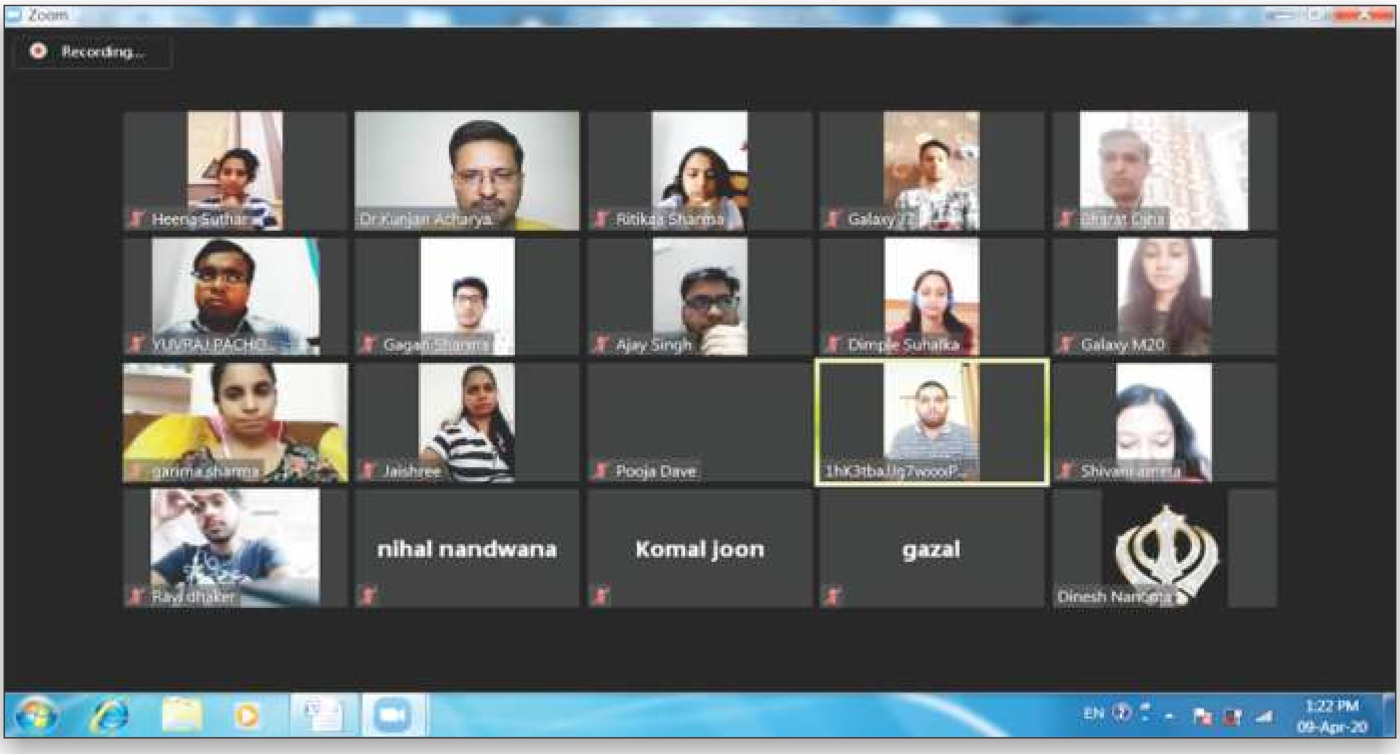

ऑनलाइन होगी भविष्य की शिक्षा

डॉ. कुंजन आचार्य

कोरोना महामारी में जीवन जीने का तरीका बदल गया है और यह तरीका आगे भी ऐसा ही रहेगा। यह एक नया दौर है। इसमें ना सिर्फ जीवनशैली में बदलाव आएगा बल्कि व्यवसाय, शिक्षा, बैंकिंग और अन्य क्षेत्रों में भी काम करने का ढंग बदल जाएगा। लॉकडाउन के दौरान स्कूल और कॉलेज बंद हैं, लेकिन इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन कक्षाएं जारी हैं। यह शिक्षा का एक नया दौर है जिसमें शिक्षा और शिक्षण दोनों के ही तरीके में बदलाव दर्ज हो रहा है।

हालांकि ऑनलाइन शिक्षण पहले भी चलन में था लेकिन व्यवहार में नहीं था क्योंकि उसकी इतनी जरूरत महसूस नहीं हुई थी। कई एप्स और वेबसाइट शिक्षण सामग्री टेक्स्ट और विजुअल के रूप में उपलब्ध करवाते रहे हैं। यूट्यूब की इसमें एक अहम भूमिका है जहां पर कई शिक्षक विभिन्न विषयों पर अपने लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं और ऑनलाइन निःशुल्क उपलब्ध करवाते हैं। लोकडॉउन में ऑनलाइन शिक्षण एक कदम आगे निकल गया है।

अगर हम डिजिटल शिक्षण की शुरुआत की बात करें तो इंटरनेट थोड़ा नया माध्यम है। इसमें टेलीविजन के योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। दूरदर्शन और यूजीसी ने मिलकर ज्ञानवाणी कार्यक्रम शुरू किया था जिसमें टेलीविजन पर वर्चुअल क्लासरूम की संकल्पना करीब 2 दशक पहले साकार हुई थी।

डिजिटल शिक्षण के इन दोनों ही रूपों में पढ़ाई एकतरफा होती थी। यानी टेलीविजन पर शिक्षक अपने रिकॉर्डेड विषयों पर अपना लेक्चर देते थे और यही तरीका यूट्यूब के ऑनलाइन लेक्चर में अपनाया जाता रहा है। इनमें दोतरफा संवाद की व्यवस्था नहीं थी यानी शिक्षक ने जो पढ़ाया है उसमें सवाल करने की गुंजाइश नहीं होती थी, लेकिन मौजूदा लॉकडाउन ने शिक्षण के नए और दोतरफा व्यवस्था को पूरी तरह अंगीकार कर लिया है।

इंटरनेट का नया दौर 4जी का दौर है इसमें तेज गति का इंटरनेट आपको वो सब कुछ मुहैया करवाता है जो आपको निर्बाध गति से चाहिए और इसी का फायदा ऑनलाइन क्लास की नवीन संकल्पना को मिला है। वीडियो कॉलिंग इंटरनेट का एक बेहतरीन नमूना है जिसमें दो व्यक्ति आपस में देखते हुए बात कर सकते हैं लेकिन ऑनलाइन क्लास के लिए एक से अधिक लोगों का वीडियो कॉलिंग से जुड़ना जरूरी होता है और इसके लिए अच्छे एप्स होना भी जरूरी है। इंटरनेट के महासमुद्र में अच्छे एप्स तो कई दिखाई पड़ते हैं लेकिन साइबर सुरक्षा की दृष्टि से वे कतई उचित नहीं होते। गृह मंत्रालय ने भी अपनी एडवाइजरी में शिक्षण संस्थान से ऐसे एप्स से बचने की सलाह दी थी जो तेज़ इंटरनेट के साथ समूह वीडियो कॉलिंग से वर्चुअल क्लासरूम की सुविधाएं देते हैं। इनमें से कुछ एप्स का इस्तेमाल लॉकडाउन काल में देश के अधिकांश शिक्षण संस्थान ने किया। देश और प्रदेश की अन्य शिक्षण संस्थाओं की तरह मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने भी इस दौरान संपूर्ण शिक्षण का

कार्य ऑनलाइन क्लासेस के जरिए संपन्न करवाया। इस विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग ने एक कदम आगे बढ़कर इस अवसर का लाभ विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के इतर बाहरी क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों से रूबरू करवाने में किया। इसमें टेलीविजन इंडस्ट्री के लोकप्रिय धारावाहिक 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के निर्देशक रुचि दवे, एबीपी न्यूज़ के अरविंद पांडे, इंडिया न्यूज़ के रूपेश आदि मुख्यधारा के पत्रकारों को ऑनलाइन क्लास में आमंत्रित करके विद्यार्थियों से रूबरू करवाया और विस्तृत संवाद करवाया। आमतौर पर बड़े शहरों में काम करने वाले ऐसे पत्रकार छोटे शहरों में सामान्य क्लास- रूम में तो नहीं आ पाते लेकिन यदि उनके अनुसार समय निर्धारित करके उन्हें ऑनलाइन क्लास के जरिए बच्चों से मिलवाया जाए तो फायदेमंद साबित हो सकता है और यही विभाग ने किया जिससे कि उनके कामकाज और उनके अनुभवों से बच्चे लाभ प्राप्त कर सकें।

लॉकडाउन काल में वर्चुअल क्लासरूम का यह नव प्रयोग हमारी भावी जीवन शैली का हिस्सा बनने जा रहा है और आगे आने वाले समय में यह अभिन्न अंग बन जाएगा क्योंकि यह दोतरफा संवाद तो कायम करता ही है साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के फार्मूले को भी सुविधायुक्त बनाता है जो ना सिर्फ विद्यार्थियों के लिए बल्कि शिक्षकों एवं शिक्षण संस्थानों के लिए भी उपयोगी और सुरक्षित है।

भविष्य का दौर ऑनलाइन शिक्षण का दौर रहेगा लेकिन इसकी चुनौतियां भी कम नहीं होंगी। यदि इन चुनौतियों पर नज़र डालें तो सबसे बड़ी चुनौती इंटरनेट कनेक्टिविटी की होगी। विदेशों में तो निर्बाध गति से

इंटरनेट समान रूप से उपलब्ध होता है लेकिन भारत में हम अभी इस सुविधा से पीछे हैं। शहरी क्षेत्रों में तो अच्छी स्पीड मिल जाती है लेकिन जो बच्चे ग्रामीण इलाको में रहते हैं, दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में रहते हैं वहां इंटरनेट की कनेक्टिविटी और स्पीड अभी भी दूर की कौड़ी है। ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान यह सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी। दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में निवास करने वाले विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण एवं उच्च गति वाले इंटरनेट के बारे में हमे गंभीरता से सोचना होगा। दूसरा महत्त्वपूर्ण पक्ष सरल, सुविधायुक्त और सुरक्षित एप्स को लेकर है, क्योंकि साइबर सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यदि मानव संसाधन विकास मंत्रालय कोई स्वदेशी एप विकसित करें और सबको एक साथ उपलब्ध करवाएं तो मुझे लगता है वह विद्यार्थियों के भविष्य के लिए सुखद और हितकारी होगा।●

ऑनलाइन पढ़ाई में आँखों की देखभाल जरूरी

डॉ. वैभव त्रिपाठी

कहते हैं, आँखे हैं तो जहान है। कोविड-19 के इस दौर में जब लॉकडाउन की पालना करते हम सभी को घरों में ही रहना पड़ रहा है, आँखों पर निर्भरता अधिक हो गयी है। वर्क फ्रॉम होम के अंतर्गत कार्यालय का कार्य हो या फिर बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई-कम्प्यूटर और मोबाइल पर ही आँखें समय गड़ी रहती है। स्वाभाविक ही है कि हमारी आँखो पर दबाव भी अधिक पड़ने लगा है।

ऑनलाइन पढ़ाई में अक्सर इस बात की शिकायत रहती है कि देर तक आंखे मोबाइल, कम्प्यूटर पर टिकी रहने से उनमें दर्द और खुजली जैसी समस्या भी आम हो रही है। आंखों की सार-संभाल यदि ठीक से की जाए तो इस समस्या से काफी हद तक निजात पाया जा सकता है।

कलाकृति–डॉ. मोहनीश ग्रोवर

आंखों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी यह है कि खूब पानी पीएं। दिन में कम से कम 5 लीटर पानी पीना ही चाहिए। कम्प्यूटर पर यदि अधिक काम करना पड़ता है तो पोश्चर सही रखना भी जरूरी है। पर्याप्त रोशनी में ही कम्प्यूटर पर काम किया जाए। मोबाइल एप का प्रयोग कर रहे हैं तो लेटकर कभी नहीं करें। अंधेरे में मोबाइल स्क्रिन किसी भी स्थिति में नहीं देखें। चश्मा यदि पहले से लगा हुआ है तो यह ध्यान रखें की उसका नम्बर नहीं बढ़े। इसके लिए सावधानियां रखना जरूरी है। पढ़ने-लिखने, टीवी, कम्प्यूटर, मोबाइल देखने का काम चश्मा लगाकर ही करें। यह भी देखा गया है कि 80 प्रतिशत प्रकरणों में काला-पानी और मोतियाबिंद इसलिए हो जाता है कि व्यक्ति बगैर डॉक्टर की सलाह लिए आँख में डालने की दवाई का इस्तेमाल करने लग जाता है। केमिस्ट से आई ड्रॉप लेकर उसके इस्तेमाल की प्रवृति खतरनाक है। ऐसे आई ड्रॉप काला-पानी कर आँख की नस को धीरे-धीरे सुखा देते हैं। बाद में ऑपरेशन ही एकमात्र विकल्प रहता है। कम्प्यूटर या मोबाइल पर यदि काम कर रहे हैं तो आंखों की पलकों को निरंतर झपकाते रहें। इससे आंखे थकेगी नहीं। कम्प्यूटर की स्क्रीन को लगातार देखते रहने से बचें, बीच-बीच में काम को रोक दें और आंखों को आराम दें।●

युद्ध से ज़्यादा ख़तरनाक रही है भारत में महामारी

प्रो. बद्रीनारायण

उत्तर भारत में विभिन्न सामाजिक शोध परियोजनाओं के तहत क्षेत्र अध्ययन के लिए हम लोगों को गाँवों में जाना होता था। गाँवों-देहातों के अध्ययन के सिलसिले में घूमते वक़्त दूरस्थ क्षेत्रों में कुछ गाँवों से थोड़ी दूर पर कुछ टीले दिखते थे।

आस-पास के लोगों से पूछने पर कहीं-कहीं यह सुनने को मिलता था कि इन टीलों पर कभी गाँव था, आबादी बसती थी किन्तु महामारी में बर्बाद हो गया। लोग या तो मर गए या गाँव छोड़कर चले गए। कई जगह इन्हें 'बीमारी का टीला' कहते हैं। गाँवों में महामारी को लोग 'हैजा, चेचक' के नाम से याद करते हैं।

कहीं-कहीं यह भी सुनने को मिलता था कि कुछ टीले 1857 के आंदोलन में बर्बाद हुए गाँवों के अवशेष हैं। उस समय जहाँ भी लोगों के मुँह से महामारी से तबाह हुए गाँवों के बारे में सुनने को मिला, उन्हें तब गहरा अध्ययन कर उनके इतिहास को हम उकेर नहीं पाए थे। किन्तु आज कोरोना महामारी का वर्तमान हमें उस अतीत की तरफ़ ले जाता है। विशेषकर उस औपनिवेशिक अतीत की तरफ़ जब महामारियों ने भारतीय आबादी की एक बड़ी संख्या को तबाह कर दिया था।

भारत में हैजा, प्लेग, चेचक (स्मॉलपॉक्स), मलेरिया, टायफाइड, टी.बी. इत्यादि आते रहे हैं। भारतीय इतिहास में 1870 से 1910 के कालखण्ड को 'महामारी एवं अकाल का युग' ही कहा जाता है। अकाल ने तो किया ही, महामारियों ने भी भारत में व्यापक जनसंहार किया।

1892-1940 के बीच बताया जाता है कि भारत में प्लेग से एक करोड़ के आस-पास लोग मरे। 1880 में प्रति हज़ार में 40 लोग मृत्यु के आगोश में समा जाते थे। इसी तरह कॉलरा, मलेरिया सबमें मरने वालों के अपने-अपने आँकड़े मौजूद हैं।

इन महामारियों ने भारतीय समाज की जनसंख्या में भारी फेरबदल किया। उन महामारियों के कारण अनेकों गाँव हमारे मानचित्र से ग़ायब हो गए। इतिहासकारों ने वर्णन किया है कि किस प्रकार 1880 के आस-पास लोग गाँव छोड़-छोड़ भाग रहे थे। तब महामारियाँ गाँवों में ज्यादा फैली थीं। शहरों में कम। वहीं अब नया कोरोना महामारी शहरों में ज्यादा दिख रहा है। गाँवों में इसका प्रसार अभी काफ़ी कम है।

गोवा में सैन्गुएम तालुका पर हुए एक अध्ययन से पता चलता है कि महामारी के कारण 1900-1910 के बीच वहाँ से 15 गाँव मानचित्र से ही ग़ायब हो गए। वहीं उसी कालखण्ड में दक्षिणी गोवा के कोना-कोना क्षेत्र में इसी कालखण्ड में चार गाँवों के हमारे भौगोलिक मानचित्र से ग़ायब हो जाने की भी सूचना मिलती है।

इसी के कारण इन्हीं महामारियों के कालखण्ड में भारत में जनसंख्या दर 0.37 प्रतिशत से ज्यादा नहीं थी। 1920 के बाद भारतीय जनसंख्या वृद्धि दर में बढ़ोतरी पाई गई।

न केवल गोवा और उत्तर भारत में बल्कि पंजाब में हुए अध्ययनों में भी पाया गया है कि वहाँ के भी अनेक गाँव महामारियों के कारण ख़त्म हो गए थे। इतिहासकारों ने अपने अध्ययनों से दक्षिण भारत विशेषकर तमिलनाडु में बताया है कि किस प्रकार महामारियों के कारण वहाँ के अनेक गाँव तबाह हो गए थे।

युद्ध के वक्त लोग आस-पास की पहाड़ियों और जंगलों में शरण ले लेते थे। युद्ध ख़त्म होने पर गाँवों में वापस लौट आते थे किन्तु महामारियों से बचकर कहीं शरण लेना भी मुश्किल था। ऐसे में या तो बीमारी से अपने भीतर की प्रतिरोधक शक्ति और देशज जीवनचर्या के कारण वे किसी तरह बच जाएं या बर्बाद हो जाएं, दो ही रास्ते थे।

दक्षिण भारत में 68 प्रशासनिक इकाइयों के 32 हज़ार 993 स्थलों के अध्ययन में लगभग 12.8 प्रतिशत ऐसे स्थल पाए गए हैं जो पहले गाँव थे, जहाँ आबादियाँ बसती थीं, लेकिन 1800-1825 दौर में वे तबाह हो गए थे। न केवल भारत में बल्कि अफ़्रीकी मुल्कों में भी महामारियों के कारण गाँवों या समुदायों के समूल नाश की सूचनाएँ

मिलती हैं। इबोला और स्मॉलपॉक्स से चिली, अमेजन के साथ कई मुल्कों में कई गाँव मिट गए। कई जातीय समुदाय बर्बाद हो गए।

महामारियों से गाँव के गाँव उजड़ जाने की सूचना हमें कई पश्चिमी मुल्कों के सामाजिक इतिहासों के अध्ययन करने पर भी मिलती है। कई बार युद्ध से ज़्यादा महामारियों ने तबाही बरपाई है। पहले विश्व युद्ध से ज़्यादा 1918-20 में आए फ्लू ने दुनिया भर में तबाही मचाई थी।

जब आधुनिक मेडिकल प्रणाली और विज्ञान इतना सशक्त नहीं था तो लोगों ने अपने देशज रहन-सहन, देशज क्वारेंटाइन और देशज चिकित्सा पद्धति से इन रोगों का प्रतिकार किया।

पूजा, पाठ, लोक विश्वास सबका सहारा तब मानवीय समाज ने लिया होगा। किसी तरह से इन विपदाओं का सामना करते हम यहाँ पहुँचे हैं। 1600 ई. में बंगाल में पहला आधुनिक चिकित्सा पद्धति का डॉक्टर ईस्ट इण्डिया कम्पनी के जहाज से एक जहाजी डॉक्टर के रूप में उतरा था। धीरे-धीरे अंग्रेज़ों ने भारत में आधुनिक चिकित्सा पद्धति जिसे अंग्रेजी चिकित्सा कहा गया, का विकास एवं विस्तार किया।

19वीं शताब्दी में बंगाल से होकर भारत के अन्य भागों में फैले एक महत्त्वपूर्ण घातक महामारी मलेरिया को 'बर्द्धवानफीवर' का नाम दिया गया था।

अंग्रेज़ी चिकित्सा पद्धति अभी भारत में ठीक से विकसित भी नहीं हो पाई थी, उसे 18वीं-19वीं शताब्दी में भारत के गाँवों में फैल रहे प्लेग, मलेरिया जैसे महामारियों का मुक़ाबला करना पड़ा।

यह चिकित्सा पद्धति भारत में महामारियों से लड़ने में तब कितनी सक्षम हो पाई, यह तो कहना मुश्किल है, किन्तु मानव समाज इन आपदाओं से उबरकर निकल ही आया। यह ठीक है कि हमने इन आपदाओं में एक बड़ी आबादी को खोया। हमारे अनेक गाँव नेस्तनाबूद हो गए। वे हमारे मानचित्र एवं स्मृतियों से भी ग़ायब हो गए, किन्तु भारतीय समाज ने हर महामारी से कुछ सीखा और अपनी जीवनशैली में कुछ सुधार किया।

महामारियों ने तब मानवीय पलायन को गति भी दी थी। जो क्षेत्र इन महामारियों से ज़्यादा प्रभावित थे, उन्हें छोड़कर वहाँ की आबादी से कुछ लोग भागकर किसी दूसरे क्षेत्र में भी जाकर बस गए थे।

मध्यप्रदेश के बुन्देलखंड के एक गाँव के कुछ परिवार याद करते हैं कि उनके पूर्वज बिहार के रहने वाले थे। किन्तु 1920 के आस-पास फैले महामारी के दौर में बिहार छोड़ यहाँ आकर बस गए थे। इस प्रकार महामारियों ने हमारी आबादी के एक भाग को 'स्थायी विस्थापन' के लिए बाध्य भी किया था।

आज कोरोना के समय में हो रही प्रवासी मजदूरों की घर वापसी या विस्थापन अस्थायी है। जैसे ही कोरोना का असर कम होगा, कामकाज खुलेंगे तो ये लोग फिर अपने उन्हीं शहरों की ओर लौट आएंगे, जिन्हें वे छोड़कर गए थे। वहीं आज प्रशासन इतना डॉक्यूमेन्टेशन पर आधारित है कि स्थायी प्रवसन अब उतना आसान नहीं रहा। दूसरे ज़मीन के भाव भी अब बहुत बढ़ गए हैं। ऐसे में एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जा बसना अब उतना आसान नहीं रहा।

अब हम जहाँ हैं वहीं रहकर कोरोना से हमें जूझना है। सूचनाओं, सुविधाओं और विज्ञान की शक्ति आज हमें उतना बेबस भी नहीं होने देगी, जैसा हम औपनिवेशिक काल में आई महामारियों के दौर में थे। फिर भी हानि तो हानि है, उससे उबरने के जद्दोजहद में आज पूरी दुनिया का मानव समाज लगा है। ●

–साभार : बीबीसी, दैनिक भास्कर, जोधपुर

जोधपुर का महामारियों से जीतने का इतिहास पुराना

मारवाड़ ने 1893 में कोविड-19 जैसी ही भयंकर एक आपदा झेली है। यह इतनी खतरनाक थी कि मारवाड़ को 'द लैंड ऑफ डेथ' कहा जाने लगा। इसका उल्लेख मारवाड़ के इतिहास की बहियों में भी मिलता है। इसके अनुसार 1893 के सितम्बर-अक्टूबर में जोधपुर शहर में कोरोना जैसी महामारी फैली थी। बहियों में इसका 'शहर में रोग चळियो' शीर्षक से उल्लेख किया गया है। बीमारी को रोकने के लिए महाराजा मानसिंह ने तुला दान (शरीर के वजन के बराबर दान किया। उस समय 8800 रुपये दान दिए गए। इस दौरान सभी गेट और शहर की चारदीवारी को सेनेटाइज करने के साथ ही दूध से धुलवाया गया ताकि संक्रमण को रोका जा सके। सभी दरवाजों के बाहर हवन और होम भी किए गए।

इतिहास के अनुसार महाराजा मानसिंहजी ने आसोज बदी 6 संवत् 1893 मुकाम गढ़ जोधपुर में ब्राह्मणों को बुलाकर भंडारे में भैरूजी की पूजा की और शहर के सभी दरवाजों जिनमें चांदपोल, सोजती गेट, भिवानी गेट, जालोरी गेट, नागौरी गेट, मेड़ता गेट और बारियों (खिड़कियों) पर बाहर पूरे शहर पनाह की दीवार के चारों ओर सेनेटाइज किया।

मार्च, 1918 प्लेग मरीजों के लिए खोले सरकारी भवन

ज्यादा बारिश के कारण मार्च, 1918 में प्लेग फैल गया। तब भी मारवाड़ ने आज ही की भांति धैर्य का परिचय दिया था। जैसे आज शहर के बाहर क्वारेंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, वैसे ही शहर से बाहर मकानों की व्यवस्था की गई। महाराजा सुमेरसिंह की ओर से शहर के बाहर सरकारी मकान खुलवाकर नगरवासियों के रहने की व्यवस्था कराई गई। अनाज और खान-पान की सामग्री नियत भाव से बेचने के लिए दुकानें खुलवाई गईं। सरकारी रिसाला नगर में गश्त करता था और खाली पड़े घरों की सुरक्षा भी रिसाले के सैनिकों पर ही थी।

1918 इन्फ्लूएंजा के दौरान गरीबों हेतु की भोजन व्यवस्था

प्लेग का संक्रमण कम हुआ तो जोधपुर में एक नई बीमारी 'युद्ध ज्वर' (इन्फ्लूएंजा) का प्रकोप हो गया। महाराजा ने तुरन्त एक 'रिलीफ कमेटी' बनाकर गरीब लोगों को सभी प्रकार की सुविधा देने का प्रयास किया। यह कमेटी गरीब बीमारों के लिए दवा के साथ-साथ खाने-पीने का प्रबन्ध भी करते थे।

डॉ. महेन्द्र सिंह

शैक्षिक प्रसारण के लिए निःशुल्क समय आवंटन

राजस्थान की पहल से देशभर को मिला लाभ

शिक्षा विकास की सचेतन और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। स्वाभाविक ही है कि कैसी भी परिस्थितियां हों, शिक्षा कभी थमती नहीं है। कोरोनाकाल में बहुत से स्तरों पर जीवन जैसे ठहर सा गया। घरों में रहकर ही इस महामारी से बचाव को परिणत किया गया है परन्तु इस दौर में भी राजस्थान में शिक्षा क्षेत्र में नवाचारों को अपनाते हुए निरंतर बहुत कुछ महत्त्वपूर्ण करने का राज्य सरकार ने प्रयास किया है। प्रत्यक्ष विद्यालयों में उपस्थिति की बजाय ऑनलाइन शिक्षण के नए रास्ते खोलने के साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया कि शिक्षण की गुणवत्ता में किसी तरह का कोई ठहराव नहीं आए।

यही नहीं, कोरोनाकाल में दूसरी आवश्यक सेवाओं की ही मानिंद शिक्षा विभाग के कार्मिकों ने भी योद्धा की भूमिका निभाते हुए इस दौरान हर स्तर पर अपनी महत्ती भूमिका निभाई है। सर्वे का कार्य हो, खाद्य सामग्री वितरण का कार्य हो या फिर स्कूलों में ठहरे लोगों की विभिन्न अन्य व्यवस्थाओं का कार्य, शिक्षा विभाग के शिक्षकों और दूसरे कार्मिकों ने निरंतर कोरोना योद्धा के रूप में अपना योगदान दिया है। शिक्षण की दृष्टि से यह बेहद महत्त्वपूर्ण रहा है कि जीवन के घरों में थमने के इस दौर में भी शिक्षकों ने विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम निर्माण का विशिष्ट कार्य संपादित किया है। उनके लिए कैरियर विकल्पों, व्यक्तित्व विकास के साथ ही सीखने की सतत प्रक्रिया के लिए भी निरंतर कार्य हुआ है। आकाशवाणी से सुदूर स्थानों के विद्यार्थियों को शैक्षिक कार्यक्रमों से लाभान्वित करने के लिए विशेष कार्यक्रमों को भी तैयार करने की महत्ती पहल शिक्षा विभाग द्वारा हुई है।

शिक्षा क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार के स्तर पर कोरोनाकाल में कुछ समयानुरूप शिक्षकों, अभिभावकों के लिए विशेष पहल भी की गयी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने एक वीडियो कॉन्फ्रेन्स में शिक्षा विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करने के

दौरान निजी शिक्षण संस्थाओं को तीन माह तक फीस नहीं लेने, फीस नहीं देने पर विद्यार्थियों का नाम नहीं काटने के साथ ही कार्यरत शिक्षकों के वेतन नहीं रोकने संबंधित विशेष निर्देश दिए। साथ ही शिक्षण संस्थाओं द्वारा ऑनलाइन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रसार की भी उन्होंने हिदायत देते हुए स्कूल एवं उच्च शिक्षा मंत्री से संवाद कर राजस्थान में शिक्षा, शिक्षकों और अभिभावकों के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य किए जाने पर जोर दिया।

बहरहाल, राजस्थान का शिक्षा विभाग लॉकडाउन के दौरान देशभर में इस दृष्टि से भी सिरमौर रहा है कि यहां से हुई शुरुआत का लाभ देशभर को मिला। शिक्षा मंत्री श्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने कोरोना के समय में प्रसार भारती द्वारा राज्य सरकार को नि:शुल्क शिक्षा के अधिकार का हवाला देते हुए विद्यार्थियों के हित में शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण का शुल्क नहीं लेने का विशेष आग्रह किया था। उन्होंने बाकायदा इसके लिए केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री को पत्र लिखा और बाद में मानव संसाधन विकास मंत्री के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेन्स में भी इसकी जरूरत को अपने तर्कों से पुरजोर ढंग से स्थापित किया। समय पर तत्परता से इस संदर्भ में कही बात का असर हुआ और अंतत: केन्द्र सरकार के निर्देश पर आकाशवाणी जयपुर द्वारा कोरोना के समय में शैक्षिक प्रसारण के लिए नि:शुल्क समय आवंटित किया गया। इसी का परिणाम है कि आज आकाशवाणी द्वारा सुदूर स्थानों तक शिक्षा के प्रसार के लिए प्रारंभ 'शिक्षावाणी' राजस्थान स्थित सभी 16 प्राथमिक एवं स्थानीय केन्द्रो के साथ 9 रिले केन्द्रों द्वारा इस समय प्रसारित किया जा रहा है।

एक बड़ी सफलता राजस्थान सरकार के खाते में यह भी रही कि केन्द्र सरकार ने ग्रीष्मकालीन अवकाश में भी पात्र बच्चों को 'मिड-डे-मील' सामग्री उनके घरों तक पहुंचाने पर सहमति जताई। मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा राज्यों के शिक्षा मंत्रियों से ऑनलाइन शिक्षण और शैक्षिक नवाचारों पर एक वीडियो कॉन्फ्रेन्स का आयोजन किया गया। इस अवसर को अनुकूल जानकर शिक्षा मंत्री श्री डोटासरा ने मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' से वीडियो कॉन्फ्रेन्स में इस संबंध में विशेष अनुरोध किया था। केन्द्र सरकार ने सिद्धान्तत: इसे स्वीकार कर लिया और अब ग्रीष्मकालीन अवकाश में भी पात्र बच्चों को 'मिड-डे मील' सामग्री उनके घरों तक पहुंचाने की पहल हो सकेगी।

कोरोनाकाल के अंतर्गत प्रदेश में 22 मार्च से ही शिक्षण संस्थाएं बंद रखे जाने के निर्देश जारी कर दिये गये थे। राज्य सरकार ने इस दौरान महत्ती निर्णय लेते हुए कक्षा एक से आठ एवं कक्षा 9 एवं 11 के विद्यार्थियों को आगामी उच्च कक्षाओं में क्रमोन्नति एवं प्रवेश हेतु पात्र किए जाने के संबंध में भी बाकायदा आदेश जारी किए। शिक्षण संस्थानों में चूंकि परीक्षा मूल्यांकन, परख आदि गतिविधियों का आयोजन नहीं हो रहा था, यह एक बारीय शिथिलन शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए दिये जाने का निर्णय हुआ।

यह भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है कि शैक्षिक कार्यों की निरन्तरता में किसी तरह की बाधा नहीं आए, इसे ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्री श्री

गोविन्द सिंह डोटासरा ने कोरोनाकाल के इस समय में निरंतर सक्रिय रहते लगभग प्रतिदिन ही ऑनलाइन अधिकारियों, शिक्षकों, शिक्षक संघों के प्रतिनिधियों, अभिभावकों आदि से संवाद निरंतर जारी रखा।

कोरोना के दौरान घरों में रहे जाने के मुख्यमंत्री के आह्वान के तुरंत बाद ही मीडिया के जरिए संवाद में लॉकडाउन की पालना करने और सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्ण पालना की अपील करते हुए ऑनलाइन शिक्षण हेतु भी विशेष कार्ययोजना के तहत कार्य करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गये।

उन्होंने घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई और अधिक प्रभावी किए जाने के साथ ही फेसबुक लाइव के जरिये कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे शिक्षा विभाग के अधिकारियों, शिक्षकों की सराहना की तथा कहा कि विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक विभिन्न स्तरों पर इस समय में जिला प्रशासन को अपनी सेवाएं दे रहे हैं और व्यक्तिगत भी आमजन के हितार्थ जो कार्य कर रहे हैं, वह अनुकरणीय है। यह भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है कि फेसबुक लाइव के अंतर्गत 16 हजार से अधिक लोग शिक्षा मंत्री से सीधे जुड़े। इस दौरान 53 हजार से अधिक कमेंट आये।

एक महत्ती पहल शिक्षा विभाग की कोरोनाकाल में यह भी रही है कि प्रदेश में ऑनलाइन शिक्षा के अंतर्गत प्रोजेक्ट 'स्माइल' (सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट) की शुरुआत हुई। इसके अंतर्गत प्रदेशभर के विद्यार्थियों और शिक्षकों के वाट्सएप ग्रुप बनाकर उन्हें पढ़ने-पढ़ाने की तैयार सामग्री भेजी जाने की पहल की गयी। यह महत्त्वपूर्ण है कि राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य भी बन गया जहां पर विद्यार्थियों-शिक्षकों को घर बैठे सोशल मीडिया के जरिए पढ़ाई करवाने की अनूठी पहल हुई। प्रोजेक्ट 'स्माइल' के अंतर्गत विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए सीखने-सिखाने की निरंतरता सुनिश्चित करने के साथ ही अभिभावकों और शिक्षकों के साथ पीईईओ द्वारा प्रदेशभर में 20 हजार से अधिक वाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए। छात्रों और शिक्षकों के लिए दैनिक वीडियो सामग्री प्रतिदिन प्रात: 9 बजे देना प्रारंभ किया गया। कक्षा एक से बारह के लिए तैयार यह वीडियो सामग्री प्रत्येक विषय के लिए, 30-40 मिनट की तैयार कर सोशल मीडिया के जरिए प्रसारित की जा रही है। यह वीडियो सामग्री ग्रेड एक-दो, 3 से 5, 6 से 8 और 9 से 12 वीं कक्षा स्तर के लिए तैयार किए गए। सामग्री की समीक्षा राजस्थान स्टेट काउन्सिल ऑफ एजूकेशन रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग, उदयपुर के विषय विशेषज्ञों द्वारा की गयी। इससे पहले समग्र शिक्षा अभियान के परियोजना निदेशक अभिषेक भगोतिया के स्तर पर इस संबंध में बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेन्स की गयी और शिक्षा अधिकारियों को सोशल मीडिया से सीखने-सिखाने की निरंतरता के लिए और प्रोजेक्ट 'स्माइल' की सफलता के टिप्स भी दिए गए।

इस पहल के तहत विभाग द्वारा राजीव गाँधी कैरियर गाइडेंस योजना के अंतर्गत राज्य के विद्यार्थियों को 10 अप्रैल, 2020 से घर बैठे ऑनलाइन लाइव सेशन के जरिए करियर मार्गदर्शन की सुविधा उपलब्ध करवाई गयी। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक के बच्चों के लिए करियर मार्गदर्शन की घर बैठे यह ऑनलाइन सुविधा प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को देने का निर्णय लिया गया। यूट्यूब सीरीज के माध्यम से करियर मार्गदर्शन की यह सुविधा विद्यार्थियों को उपलब्ध कराने की शुरुआत प्रदेश में हुई। इसके तहत लाइव सेशन में मंगलवार एवं शुक्रवार को सायं 4 से 5 बजे के दौरान कैरियर प्लानिंग, 10 वीं और 12 वीं के बाद विषय और विकल्पों के चयन, कॉलेज चयन, विभिन्न परीक्षाओं एवं छात्रवृत्तियों आदि के साथ ही 546 प्रकार के रोजगारोन्मुखी अध्ययन, विकल्पों की जानकारियां भी विद्यार्थियों को निरंतर प्रदान की गयी हैं।

विद्यार्थियों के अध्ययन में किसी तरह की कोई बाधा नहीं हो, इसे दृष्टिगत रखते हुए प्रोजेक्ट 'स्माइल' के अतिरिक्त पढ़ाई के ऑनलाइन कंटेंट तैयार करवाने की दिशा में भी महत्ती पहल हुई। इसके तहत प्रदेश के शिक्षकों से डिजिटल मीडिया में शैक्षिक प्रसारण की सामग्री तैयार कर आमंत्रित की गयी। श्रेष्ठ सामग्री के आधार पर शिक्षकों का राज्य स्तरीय पैनल तैयार किया गया और ई-लर्निंग की प्रक्रिया उच्च कक्षा में क्रमोन्नति के अनुसार जारी रखने का भी हरसंभव प्रयास किया गया।

लॉकडाउन अवधि में विभागीय स्तर पर शिक्षकों, कार्मिकों की नवीन नियुक्तियां, परीक्षाओं के आयोजन, शिक्षा की बेहतरी आदि की भविष्य की योजनाओं पर भी निरंतर चिंतन-मनन किया गया। यह सही है, कोरोनाकाल में जीवन बहुत से स्तरों पर घरों में ठहर सा गया है परन्तु राजस्थान में शिक्षा क्षेत्र में 'चरैवेति' की भारतीय परम्परा का नाद करते हुए निरंतर नवाचारों को अपनाते हुए बहुत कुछ महत्ती किया गया है, किया जा रहा है। ●

–डॉ. अरुणा

दक्षिणांचल की आदि परंपरा में शामिल है सोशल डिस्टेंसिंग

आज पूरी दुनिया कोविड-2019 की महामारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कर रही है लेकिन राजस्थान, मध्यप्रदेश और गुजरात की स्नेहिल सरहदों से घिरा तथा लोक संस्कृतियों और सामाजिक परंपराओं का जीवन्त प्रतिदर्श रहा राजस्थान का दक्षिणांचल वागड़ क्षेत्र इस मामले में पुरातन काल से आगे रहा है।

प्रकृति के उपहारों से लक-दक समूचे वागड़ क्षेत्र में उन्मुक्त प्राकृतिक परिवेश के बीच दूर-दूर टापरे-टापरे निवास का चलन वागड़ क्षेत्र में पुरातन काल से चली आ रही परंपरा का अहम हिस्सा है जो कि वर्तमान समय में कोरोना संक्रमण सामाजिक दूरीकरण (सोशल डिस्टेन्सिंग) के वैश्विक संदेश का पुरातन संकेत दर्शा रहा है।

इस परम्परा के तहत जनजाति क्षेत्रीय बांसवाड़ा जिले के ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले जनजाति वर्ग के कृषक परिवार पुरातन काल से ही दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित कृषि भूमि पर टापरा बनाकर अपना जीवनयापन करने की महत्त्वाकांक्षी परम्परा वर्तमान समय में बहुपयोगी साबित हो रही है।

जनजाति बहुल जिलों के ग्रामीण क्षेत्र में जनजाति वर्ग के कृषक मूलभूत सुविधाओं से वंचित होकर भी कृषि भूमि पर टापरा बनाकर निवास करते आ रहे हैं एवं इसी अरण्य स्थल में निवास के साथ जीवन का आनन्द उठाते रहे हैं। वर्तमान समय में टापरे-टापरे निवास की परम्परा सोशल डिस्टेन्सिंग के मूलभूत सिद्धान्त को पूरा करती नजर आ रही है। जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में आज भी सोशल डिस्टेन्सिंग की पालना के जीवन्त उदाहरणों को आसानी से देखा जा सकता है।

आदिवासी परिवार में यह चलन है कि परिवार में जितने भी बच्चे हैं उनका अपना अलग टापरा होता है। परिवार में बड़े बेटे की शादी होने के तुरन्त बाद ही अपने घर से थोड़ी दूरी पर उसका टापरा बना दिया जाता है और इसी प्रकार अन्य लड़कों का भी शादी के बाद उनका अपना टापरा अलग बना दिया जाता है। यह अपने आप में आत्मनिर्भर एवं स्वतंत्र जीवनयापन के साथ ही परम्परा सोशल डिस्टेन्सिंग को ही अभिव्यक्त करता रहा है। जनजाति क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में आज भी अलग-अलग टापरे बनाकर रहते हैं।

सेहत की दृष्टि से भी इनके टापरे अत्यन्त अनुकूल और सादगीपूर्ण हैं। घर के आगे खुला आँगन, चारों तरफ हरियाली का दिग्दर्शन और सूरज की भरपूर रोशनी इनके स्वास्थ्य और शारीरिक सौष्ठव की दृष्टि से प्रभावकारी होते हैं।

आज कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेन्सिंग का होना ही आवश्यक है। कोविड-19 के बचाव व सुरक्षा के लिए जहां सोशल डिस्टेन्सिंग को अपनाना सर्वोपरि प्राथमिकता हो गई है और विश्व स्तर पर माना गया है कि मौजूदा परिप्रेक्ष्य में सामाजिक दूरीकरण ही इस महामारी के प्रसार को रोकने का बेहतर और सहज-सरल एवं सर्वस्वीकार्य उपाय है।

इस दृष्टि से जनजाति अंचलों को इस मायने में आदर्श परंपराओं का आदि संवाहक कहा जा सकता है कि उनमें संक्रमण को रोकने के लिए बचाव के उपाय सदियों से चले आ रहे हैं और यह सामाजिक परंपराओं का हिस्सा रहे हैं। मौजूदा समय में सोशल डिस्टेंसिंग के मामले में जनजाति क्षेत्रों को अग्रणी माना जा सकता है।●

–कल्पना डिण्डोर

कोरोनाकाल में कला एवं संस्कृति

फुरकान खान

'कोरोना वायरस' जनित महामारी ने एक ऐसा रूप धारण किया है कि इस समय को इतिहास में 'कोरोनाकाल' के रूप में ही याद रखा जायेगा। कोरोनाकाल ने सरकार और जनता के लिये अनेक चुनौतियां प्रस्तुत कर दी हैं। यह चुनौतियां ना केवल मानव त्रासदी से संबंधित हैं बल्कि जीवन के हर उस पहलू को अपने में समेटे हुये हैं जिससे आम जनता अथवा राज्य सत्ता का सरोकार होता है। सरकारें अपने-अपने ढंग से इस चुनौती का सामना कर रही हैं लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के कुशल और सकारात्मक नेतृत्व में राजस्थान जिस तरह से इस आपदा का सामना कर रहा है वो भी अपने आप में एक ऐतिहासिक मिशाल ही है। इस महामारी से जनता को होने वाले कष्ट को कम से कम किये जाने के लिये राजस्थान सरकार ने जिस प्रकार से मानवीय दृष्टिकोण अपनाया है वो इतिहास में अवश्य याद किया जायेगा। इसी मानवीय दृष्टिकोण का एक उदाहरण है 'मुख्यमंत्री लोक कलाकार सहायता योजना' जिसके माध्यम से दूरदराज़ के लोक कलाकारों को कोरोना के दौर में संबल देने का प्रयास किया जा रहा है।

यह कालखण्ड इस प्रकार का है कि इसके बीत जाने पर भी कला एवं संस्कृति संबंधी कार्यक्रमों को परंपरागत ढंग से आयोजित किये जाने में लम्बे समय तक समस्या बनी रहेगी। यदि आयोजन प्रशासनिक और चिकित्सीय दृष्टि से अनुमत हो भी जायें तो भी आम जनता में फैली कोरोना की दहशत कला रसिकों को एक जगह इकट्ठा होने से बहुत समय तक रोके रखेगी। ऐसे में कला, संस्कृति, साहित्य एवं पुरातत्त्व के क्षेत्र में ऐसे विकल्प तलाश करने थे जो ना केवल कोरोनाकाल में कला एवं संस्कृति की धारा को अविरल बहने दें बल्कि उसके बाद भी एक विकल्प के रूप में सदैव उपलब्ध रहें। कला एवं संस्कृति मंत्री डॉ. बी डी कल्ला और प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा के नेतृत्व में जब विकल्प तलाशना शुरू किये तो विभाग के अधीन समस्त अकादमियां और संस्थान अपने-अपने व्यावहारिक विकल्प लेकर उपस्थित हो गये और आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुये कला एवं संस्कृति विभाग का एक समर्पित यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज तैयार किया गया और अनेक प्रकार की सामग्री तैयार की जाकर इन सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर डाली जाने लगी। रविन्द्र मंच को इसके समन्वय का उत्तरदायित्व सौंपा गया।

सबसे पहले प्रसिद्ध शास्त्रीय गायकों के द्वारा कोरोना वॉरियर्स के लिये एक कार्यक्रम 'सहर' संस्था और कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा तैयार किया गया। यह पहला ऐसा प्रयास था जिसमें घर बैठे ही कलाकारों ने उपलब्ध मोबाइल पर अपना कार्यक्रम रिकॉर्ड किया और वो दर्शकों के मोबाइल तक पहुँच गया। यह आधुनिक तकनीक का प्रयोग ही था कि बिना किसी के भौतिक यात्रा किये हुये कला ने यात्रा कर ली थी और यह यात्रा आगे भी जारी है। इसके पश्चात् बारी थी लोक कलाकारों की जिनके लिये 'मुख्यमंत्री लोक कलाकार सहायता योजना' स्वीकृत की गई। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के लोक कलाकारों द्वारा अपनी कला के प्रदर्शन का वीडियो बनाकर उसे ऑनलाइन भिजवाना होता है और फिर गठित समिति यदि उपयुक्त पाती है तो उसे विभागीय चैनल पर अपलोड करती है तथा चयनित प्रविष्टियों को एक

निश्चित राशि भी प्राप्त होती है। यह एक ऐसी अनूठी योजना थी जो किसी अन्य राज्य सरकार ने सोची भी नहीं थी। सम्पूर्ण भारत में इस योजना की मुक्तकंठ से प्रशंसा होने लगी तथा अन्य राज्य भी इस दिशा में सोचने लगे। इस कठिन समय में घर बैठे लोक कलाकारों को कुछ राशि मिल जाये और कला आपके घर और आपके हाथों में पहुँच जाये और पूरा भारत इसका अनुसरण करता नज़र आये, इससे अधिक किसी योजना की सफलता क्या होगी ?

चूंकि शास्त्रीय कलाकार कोरोना वॉरियर्स के लिये अपना योगदान दे चुके थे तो लोक कलाकार क्यों पीछे रहते ? लोक कलाकारों ने भी अपने-अपने घरों में मोबाइल से अपनी कला का वीडियो बनाकर 'लोकांजलि' नाम की प्रस्तुति तैयार की जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का संदेश भी था और कोरोना से लड़ रहे लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिये उनकी कला का प्रदर्शन भी था। विभाग के चैनल पर यह शीघ्र ही लोकप्रिय हो गया और अभी तक समस्त अपलोडेड वीडियो से कहीं ज़्यादा देखा भी जा रहा है।

फिर बारी आई ऑनलाइन लाइव कार्यक्रमों की। इसमें सबसे पहले बाज़ी मारी राजस्थान ललित कला अकादमी ने जिन्होंने बहुत ही व्यवस्थित ढंग से पेंटिंग की ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित की, जिसमें 120 कलाकारों ने हिस्सा लिया। अकादमी के सचिव श्री विनय शर्मा बताते हैं कि शुरुआत में इसको 40-50 की संख्या तक ही सीमित करना था और भाग लेने वालों को टोकन स्वरूप कुछ मानदेय भी देना था लेकिन जैसे ही कैम्प आरम्भ हुआ तो और कलाकार जुड़ते चले गये और उन्होंने मानदेय लेने से भी इनकार कर दिया बल्कि यह तय किया कि इस कैम्प के माध्यम से जो पेंटिंग तैयार होंगी उनकी आय मुख्यमंत्री सहायता कोष में जायेगी। यह बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय था जिसकी प्रशंसा स्वयं माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी की गई। ललित कला अकादमी और कला एवं संस्कृति विभाग की यह पहल एक और ऐसी पहल थी जिसने सम्पूर्ण भारत का ध्यान आकर्षित किया और देश की कई अन्य संस्थाओं ने ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित करने प्रारंभ किये। फिर राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य संवाद श्रृंखला प्रारंभ की गई जिसमें प्रत्येक बुधवार को किसी एक विषय पर हिन्दी के किसी एक वरिष्ठ साहित्यकार से किसी युवा साहित्यकार द्वारा वार्ता की जाती है जो घर बैठे ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से वार्ता से जुड़ते हैं और सामान्य जनता फेसबुक पर साहित्य अकादमी की पत्रिका 'मधुमति' के पेज से जुड़कर लाइव देख पाती है। घर बैठे साहित्य से जुड़े रहने का यह कमाल तकनीक के सही और रचनात्मक प्रयोग के कारण ही संभव हो पाया।

तकनीक के अतिरिक्त ऑनलाइन कार्यक्रम का महत्त्वपूर्ण हिस्सा होता है 'सामग्री' यानी कन्टेन्ट, जिसे तैयार किया जाना आम दिनों में भी आसान कार्य नहीं होता और लॉकडाउन में तो और भी मुश्किल है लेकिन कला एवं संस्कृति विभाग की सभी अकादमियां और संस्थायें ऑनलाइन सामग्री तैयार करने में जुट गईं। शीघ्र ही संस्कृत अकादमी ने आचार व्यवहार नियम के नाम से नई सीरीज़ तैयार कर लीं जो कि विभाग के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। पुरातत्त्व विभाग ने बहुत ही सुन्दर ऑनलाइन फोटो प्रदर्शनी आयोजित करने के साथ ही अल्बर्ट हाल की उपस्थिति को ट्विटर पर भी दर्ज करवाया तथा कई ऐतिहासिक धरोहरों के विज़ुअल ट्यूर भी तैयार किये। राजस्थान पुरालेखागार (आर्काइव्ज़) ने भी अपने बहुमूल्य खजाने तलाशे और कई रोचक जानकारियां उपलब्ध करवाईं। टोंक के अरबी फारसी शोध संस्थान द्वारा केलिग्राफी और पेपरमेशी की ऑनलाइन वर्कशाप के साथ-साथ मुशायरे आयोजित किये तथा तैयार की गई सामग्री से प्राप्त आय को मुख्यमंत्री सहायता कोष में दिये जाने का निर्णय लिया गया। जवाहर कला केन्द्र द्वारा भी ऑनलाइन लर्निंग के नाम से 'समर कैम्प' आरम्भ किया गया है जो प्रथम कड़ी के लाइव प्रसारण से ही लोकप्रिय हो गया।

ऑनलाइन सामग्री तैयार होने के कई लाभ भी अब महसूस किये जाने लगे हैं। सबसे पहला तो यह कि भले ही सड़कें और चौराहे सूने हो गये लेकिन कला और साहित्य की दुनिया सूनी नहीं रही और घर बैठे-बैठे इसका ना केवल आनंद लिया जा रहा है बल्कि कलारसिक मानसिक रूप से स्वयं को अधिक जुड़ा हुआ भी महसूस कर रहे हैं और समय भी अच्छा व्यतीत हो रहा है। दूसरा लाभ यह कि कला और साहित्य से संबंधित जो डिजिटल डाक्यूमेंटेशन स्वत: अब हो रहा है वो अपने आप में भविष्य के लिये बड़ा खज़ाना साबित होने वाला है। तीसरा यह कि इसकी पहुँच देशातीत और कालातीत है। आप कहीं भी और कभी भी इसको देखकर आनंद ले सकते हैं जिससे दर्शकों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है। यही नहीं लागत भी कोई बहुत अधिक नहीं आती।

ऑनलाइन कार्यक्रमों में इतना सब कुछ होते हुये भी यह नहीं कहा जा सकता कि ऑनलाइन कार्यक्रम उन कार्यक्रमों का विकल्प हैं जिनमें दर्शक व्यक्तिश: कलाकार और साहित्यकार से रूबरू होकर प्रस्तुतियों का आनंद लेता है। कलाकारों की प्रस्तुति, दर्शकों का जमावड़ा, उनकी तालियां उनकी वाह-वाह और कलाकारों द्वारा जोश में और अच्छी प्रस्तुति देने का अपना ही एक अलग आनंद है लेकिन कुछ नहीं होने से कुछ होना बड़ी बात है। जब तक स्थितियां सामान्य नहीं हो जातीं तब तक इस प्रकार ही कला से अपना जुड़ाव बनाये रखें और कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा किये जा रहे नवाचारों का पूरा लाभ उठायें। यह तय है कि कोरोनाकाल में राजस्थान सरकार द्वारा की गई इस पहल को संस्कृति के इतिहास में सदैव याद रखा जायेगा।●

दरिद्रनारायण की उपासना

–विनोबा भावे

महात्मा गांधी गरीबों के उद्धार के प्रबल समर्थक थे। अपनी इसी सोच के चलते उन्होंने दरिद्रता, शोषण दूर करने, दु:ख निवारण को ही जीवन का जैसे ध्येय बना लिया था। स्वराज्य की मांग उनके लिए वह साधन था जिससे गरीबों का भला हो सकता था। स्वराज्य प्राप्ति के काम को भी उन्होंने मानव सेवा का रूप दिया। 'दरिद्रनारायण' शब्द को घर–घर पहुंचाने का कार्य महात्मा गांधी ने किया। उनकी सोच थी– कहीं कोई गरीब, दरिद्र न रहे। आचार्य विनोबा भावे ने कभी काशी में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के उद्घाटन अवसर पर आयोजित समारम्भ में बड़े बड़े विद्वानों, राजा–महाराजाओं और वायसराय की उपस्थिति में उनके ओजस्वी भाषण को अखबार में पढ़ा और उसका उन पर गहरा असर हुआ। विनोबा गांधी जी से मिलने उनके आश्रम पहुंच गए। वह लिखते हैं , 'जब मैं छोटा था तभी से मेरा ध्यान बंगाल और हिमालय की ओर खिंचा था। हिमालय और बंगाल जाने के सपने मैं देखता था। बंगाल में वन्दे मातरम् की क्रांति की भावना मुझे खींचती थी और दूसरी ओर हिमालय का ज्ञानयोग मुझे खींचता था।...गांधी जी के पास मुझे हिमालय की शांति भी मिली और बंगाल की क्रांति भी मिली। जो विचारधारा मैंने वहां प्राप्त की, उसमें क्रांति और शांति का अपूर्व संगम हुआ था।'

विनोबा ने गांधी जी को जैसा देखा, उस पर पूरी एक किताब लिखी है। इसमें गांधीजी के जीवन का मर्म समाया हुआ है। उनकी पुस्तक 'गांधी : जैसा विनोबा ने देखा, समझा' का यह अंश दरिद्रता के निवारण में उनके योगदान और इस सोच का एक तरह से आलोक है। 'सुजस' के पाठकों के लिये खासतौर से यह आलेख...

–संपादक

भागवत में एक कथा है। शुकदेवजी जब घर त्याग कर निकल पड़े, तब उनके परम-विरक्त, ज्ञान शिरोमणि, विद्यानिधि पिता व्यासजी को भी सम्मोह हुआ और वे पुत्र के पीछे दौड़ने लगे और कहने लगे- 'हे पुत्र, तुम कहां जाते हो, जरा ठहरो तो सही।' लेकिन शुकदेवजी रुके नहीं, चलते ही गये। अत: जब शुकदेवजी ने पिता को उत्तर नहीं दिया, तो अविनय न हो, इसलिए शुकदेवजी के साथ तन्मय हो जाने वाले वृक्षों ने उनकी तरफ से जवाब दिया। शुकदेव इतने सर्वभूत-हृदय हो गये थे कि उनकी ओर से बोलने का काम, जवाब देने का काम, वृक्ष भी करते थे। ऐसी ही एकात्मता गांधीजी ने हिन्दुस्तान के लोगों के साथ साधी थी।

वे कहते थे कि मेरी तपस्या का हिमालय वही है, जहां अभी दरिद्रता पड़ी है और उसे मिटाना है, शोषण दूर करना है, दु:ख निवारण करना है। देश में एक भी आदमी जब तक जीवन की आवश्यकताओं से वंचित होगा, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी और मैं पांव सिकोड़कर नहीं बैठूंगा।

इसीलिए हमने देखा कि जब स्वराज्य आया, तब भी बाबू नोआखाली में ही घूम रहे थे और दुखियों के आंसू पोंछने के काम में ही रत थे। उनका यह रवैया पहले से ही था। वे गोल-मेज परिषद् में गए थे, तब भी उन्होंने वहां कहा था कि मैं अत्यन्त नम्रतापूर्वक स्वराज्य की मांग करता हूं। उन्होंने यह एक विचित्र लगने जैसी ही बात कही थी क्योंकि- 'स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे हम लेकर ही रहेंगे'। ऐसी भाषा बोली जाती थी, तब बापू वहां कहते थे कि स्वराज्य की मांग नम्रतापूर्वक करता हूं क्योंकि उसके बिना हिन्दुस्तान के गरीबों का उद्धार होने वाला नहीं है। स्वराज्य उनके लिए एक साधन ही था। अंत में तो गरीबों का भला करने की बात ही मुख्य थी।

'दरिद्रनारायण' शब्द विवेकानंद का दिया हुआ है। अद्वैत विचार को दरिद्रनारायण की सेवा के साथ जोड़ने की प्रक्रिया मूल में विवेकानंद की ही है। आधुनिक युग में सेवायोग की शुरुआत विवेकानंद

ने की, ऐसा कह सकते हैं। यह 'दरिद्रनारायण' शब्द लोकमान्य तिलक को भी बहुत प्रिय था। देशबंधु चितरंजन दास ने भी उसे प्रचलित किया। लेकिन उस शब्द को घर-घर पहुंचाने का काम और तद्नुसार सारा रचनात्मक कार्यक्रम खड़ा करने का काम गांधीजी ने किया। उन्होंने स्वराज्य प्राप्ति के काम को भी मानव-सेवा का रूप दिया।

महात्मा गांधी ने मानव-सेवा के इस विचार को अधिक व्यापक बनाकर उसके साथ उत्पादक शरीर-श्रम की आवश्यकता भी स्पष्ट कर दी। उन्होंने सेवावृत्ति को निर्माण कार्य का स्वरूप देकर उसमें वृद्धि की। सामने भूखा आदमी खड़ा हो तो उसे खिलाना, यह हुई सेवा। इसके बदले चरखा देकर या जमीन देकर उससे उत्पादन करके खाना सिखाना, यह हुआ निर्माण। यही सच्ची सेवा मानी जाएगी।

एक दूसरी बात भी ध्यान में रखनी है। गांधीजी ने अपने जीवन में 'दरिद्रनारायण' की उपासना का एक उत्तम उदाहरण पेश किया, परन्तु अब हमें आगे विचार करना है। हम सब चाहते हैं कि 'दरिद्र' शब्द न रहे, केवल 'नारायण' रहे। दुनिया में कोई दरिद्र रहे और मैं उससे अलग रहकर उसकी सेवा करूं, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे सेवा का मौका देने के लिए भगवान् हमेशा दरिद्र के रूप में आयें, यह मैं पसंद नहीं करता। मैं सीधे नारायण की सेवा करना चाहता हूं। इसलिए अब कोई दरिद्र और कोई अमीर न रहे, सभी 'अमृतस्य पुत्रा:' बन जायें। अमृत के पुत्रों में असमानता नहीं हो सकती। फिर सब कंधे-से-कंधा मिलाकर भगवान् की और सृष्टि की सेवा करें।

गांधीजी के जमाने से कार्यकर्त्ताओं के विषय में मेरी एक शिकायत रही है। उत्तम काम में लगे हुए हमारे लोग विचारों का अध्ययन कम करते हैं, अधिकांश समय कर्म में ही चला जाता है। इसलिए पढ़ने के नाम पर अल्लाह।

सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह वगैरह ग्यारह व्रतों पर गांधीजी ने बहुत जोर दिया है। वे उसके बारे में बार-बार कहते थे और उन्होंने अपना जीवन उन्हीं पर बांधा था। लेकिन अध्ययन पर जोर देने का कोई मौका उन्हें नहीं मिला। यद्यपि वे स्वयं अध्ययन का महत्त्व समझते थे और अपने अंतेवासियों से भी इस विषय पर कहते थे। किन्तु एक भारी जन-आंदोलन था; इस कारण व्रतों को उन्होंने जितना महत्त्व दिया, उतना विद्या को नहीं दिया। इससे गांधीजी के जीवन-कार्य में तीव्र अध्ययन की प्रेरणा की न्यूनता हमें लगती है।

बापू के जीवन को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि उनके साथ कितने ही आध्यात्मिक सवाल थे। बापू की आत्मकथा पढ़ने पर इसकी कुछ झलक तो मिलती है। श्रीमद् रामचन्द्रजी के साथ उनकी चर्चा हुई थी। लेकिन बावजूद इसके उनके मन में कितनी ही आध्यात्मिक शंकाएं थीं और जब तक इन शंकाओं का निवारण नहीं हो गया और जिन्हें हम गूढ़ अनुभव (मिस्टिक एक्सपीरिएन्सेज) कहते हैं, वैसे नहीं हो गये, तब तक वे काम में नहीं लगे थे। बापू कहते थे, सत्य ही परमेश्वर है- ट्रुथ इज गॉड। लोग इतने में मान लेते थे कि यह वैज्ञानिक बात है, लेकिन यह सिर्फ वैज्ञानिक बात नहीं थी। खान अब्दुल गफ्फार खां की कुमुक जाने की बात चल रही थी, तब उन्हें लगा कि ऐसा भी हो सकता है कि वापस लौटना न हो। इसलिए मुझे बात करने को बुलाया। लगभग पन्द्रह दिन तक हमारी बातें चलीं। दो-तीन दिन तो वे सवाल पूछते गये और मैं जवाब देता गया। फिर एक दिन मैंने उन्हें ईश्वर विषयक अनुभव के बारे में छेड़ा।

मैंने कहा- 'आप 'सत्य ही परमेश्वर है' कहते हैं, सो तो ठीक है। लेकिन उपवास के समय आपने कहा था कि आपको अंदर की आवाज सुनाई दी थी, यह क्या बात है? इसमें कोई रहस्य-गूढ़ता है?'

तब उन्होंने जवाब दिया- 'हां, इसमें कुछ ऐसा है, जरूर। यह बिल्कुल साधारण बात नहीं है। मुझे आवाज साफ-साफ सुनाई दी थी।' मैंने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए? तो उन्होंने जवाब दिया- 'उपवास करना चाहिए।' मैंने फिर पूछा कि कितने उपवास करने चाहिए? उन्होंने कहा- 'इक्कीस।'

इसमें एक पूछने वाला था और दूसरा जवाब देने वाला था। यानी बिल्कुल कृष्णार्जुन-संवाद ही था। बापू तो सत्यवादी थे, इस वास्ते यह कोई भ्रम नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि साक्षात् ईश्वर ने मुझसे बात की। इसलिए मैंने फिर पूछा- 'ईश्वर का कोई रूप हो सकता है?'

उन्होंने कहा- 'रूप तो नहीं हो सकता, लेकिन मुझे आवाज सुनाई दी थी।' मैंने कहा- 'रूप अनित्य है तो आवाज भी अनित्य है। फिर भी आवाज सुनाई देती है, तो फिर रूप क्यों नहीं दिखता?'

फिर मैंने उनसे दूसरों को हुए ऐसे गूढ़ अनुभव की बातें कहीं। अपने भी कुछ अनुभव कहे। ईश्वर दर्शन क्यों नहीं होता, इस बारे में भी बातें हुईं। फिर मैंने कहा- 'आपके मन में सवाल-जवाब हुए, उनका सम्बन्ध ईश्वर के साथ तो है ही न?'

उन्होंने कहा- 'हां, उसके साथ सम्बन्ध है। लेकिन मैंने आवाज सुनी, दर्शन नहीं हुए। मैंने रूप नहीं देखा, लेकिन उसकी आवाज सुनी है। उसका रूप होता है, ऐसा अनुभव मुझे नहीं हुआ और उसके साक्षात् दर्शन नहीं हुए, लेकिन हो सकते हैं जरूर।'

मुझे कहना ही पड़ेगा कि ऐसी किसी अनुभूति को हम भ्रम या मिथ्या नहीं कह सकते। परमेश्वर जिस भूमिका में अ-शब्द है, उस भूमिका में अ-रूप भी है; और जिस भूमिका में वह स-शब्द है, उस भूमिका में उसका स्वरूप भी है।

यह सब मैं आपके सामने इस वास्ते रखता हूं कि बापू को हमने ऊपर-ऊपर से ही पहचाना है। हमने उन्हें राजनीति आदि में ही रचे-पचे देखा है या रचनात्मक कामों में डूबे देखा है। लेकिन यह बापू की सही पहचान नहीं है। उनके व्यक्तित्व का मूलभूत पहलू तो आध्यात्मिक है।●

प्रदेश के सांसदों–विधायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस

विधानसभा सत्र जैसा दिखा नजारा

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कोविड-19 की जंग में सबको साथ लेकर चलने की मिसाल पेश की है। मानवता पर आए इस संकट का सामना करने के लिए उन्होंने बिना किसी राजनीतिक भेदभाव सभी दलों, धर्मगुरुओं , उद्यमियों, भामाशाहों सहित हर वर्ग को साथ लिया है। राजस्थान में जैसे ही इस महामारी ने कदम रखा था, मुख्यमंत्री ने इसकी व्यापकता को देखते हुए हर वर्ग से संवाद करने की पहल की थी। अब लॉकडाउन के कारण पैदा हुए हालातों, आगे की रणनीति और इस चुनौती से सफलतापूर्वक निपटने के लिए मुख्यमंत्री प्रदेश के सभी सांसदों एवं विधायकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक मंच पर लेकर आए और उनके सुझाव जाने ताकि इस जंग को और बेहतर ढंग से लड़ा जा सके।

श्री गहलोत जब प्रदेश की सभी पार्टियों के सांसदों और विधायकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 महामारी पर चर्चा कर रहे थे तो नजारा विधानसभा सत्र जैसा नजर आया। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी पी जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे, नेता प्रतिपक्ष श्री गुलाबचंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष श्री राजेन्द्र राठौड़ और पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री पी पी चौधरी भी वीसी के माध्यम से इस चर्चा में शामिल हुए। कांग्रेस और भाजपा विधायकों के साथ ही सीपीएम, बीटीपी, आरएलडी एवं निर्दलीय विधायक भी कोरोना महामारी के खिलाफ मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चल रही लड़ाई में एकजुट नजर आए। राज्य सरकार के मंत्रियों ने भी विभिन्न जिलों के प्रभारी मंत्री एवं अपने क्षेत्र के विधायक के रूप में फीडबैक और सुझाव दिए।

सभी का सहयोग जरूरी

श्री गहलोत ने उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा एवं भरतपुर संभाग के विधायकों एवं सांसदों से चर्चा कर लॉकडाउन के तीसरे चरण के बाद की रणनीति पर सुझाव आमंत्रित किए। उन्होंने कहा कि हमारे देश और प्रदेश की संस्कृति रही है कि आपदा के समय हमने सारे मतभेद भुलाकर पूरी एकजुटता के साथ पीड़ित मानवता की सेवा का काम किया है। कोरोना की लड़ाई भी ऐसी ही है, जिसे सभी के सहयोग से जीता जा सकता है। राज्य सरकार संक्रमण रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और इसमें हर वर्ग का साथ भी मिल रहा है। उन्होंने आह्वान किया कि सभी दल इसी तरह इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में साथ देते रहें।

पूरे देश ने सराहा राजस्थान मॉडल

मुख्यमंत्री ने बताया कि झुंझुनूं और भीलवाड़ा में कोरोना केस मिलने के बाद सरकार ने रूथलेस कंटेनमेन्ट पर फोकस करते हुए घर-घर सर्वे करवाया और इन जिलों की सीमाएं सील कर संक्रमण को नियंत्रित किया। भीलवाड़ा मॉडल की पूरे देश में सराहना हुई। प्रदेश में हॉट स्पॉट वाले इलाकों में बड़े स्तर पर टेस्ट कराए जा रहे हैं और प्रतिदिन टेस्ट

क्षमता 11 हजार 770 तक पहुंच गई है। चिकित्सा सुविधाओं को लगातार मजबूत किया जा रहा है। विधायक कोष की राशि अगले दो साल तक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में ही उपयोग करने का फैसला किया है। राजस्थान में कोविड-19 से मृत्यु का प्रतिशत 2.9 है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। मरीजों के ठीक होने का प्रतिशत भी 55.43 है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 29.97 प्रतिशत है। कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में राजस्थान अभी मजबूत स्थिति में है।

'कोई भूखा नहीं सोएं'

श्री गहलोत ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान 'कोई भूखा नहीं सोएं' इस संकल्प के साथ सभी जरूरतमंदों को राशन सामग्री एवं भोजन के पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 78 लाख लाभार्थियों को दो माह की पेंशन के रूप में 1400 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान किया है। करीब 33 लाख असहाय एवं निराश्रितों, स्टेट बीपीएल एवं अन्य जरूरतमंदों को 2500-2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों को 2 माह तक 10 किलो गेहूं निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा 54 लाख ऐसे लोग जो एनएफएसए में कवर नहीं होते उन्हें राज्य सरकार एफसीआई से 21 रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं खरीद कर प्रति व्यक्ति 10 किलो गेहूं निःशुल्क उपलब्ध करवा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि कनेक्शनों के मार्च, अप्रैल एवं मई के बिजली बिलों का भुगतान स्थगित किया गया है, इससे 13 लाख किसानों को राहत मिली है। साथ ही अन्य श्रेणियों के बिजली बिलों एवं पानी के बिलों का भुगतान भी स्थगित किया गया है। लॉकडाउन के तीसरे चरण में भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार उद्योग एवं फैक्ट्रियां पुन: प्रारम्भ की गई हैं, इससे आर्थिक गतिविधियां फिर से शुरू हुई हैं।

विधायक उपलब्ध कराएं कलक्टर को सूची

श्री गहलोत ने कहा कि संकट की इस घड़ी में फंसे हुए प्रवासियों एवं श्रमिकों को अपने गृह स्थान पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने जो पहल की थी उसके तहत करीब 19 लाख 20 हजार लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है। इसमें आने वालों की संख्या 12 लाख है। प्रवासी श्रमिकों के दर्द को समझते हुए भारत सरकार की गाइडलाइन और अन्य राज्यों के साथ समन्वय स्थापित कर उन्हें लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने विधायकों से कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र के प्रवासी जो भी सूचनाएं भेज रहे हैं, उनसे सरकार को अवगत कराएं। विशेष ट्रेनों के माध्यम से इन्हें लाने के लिए केन्द्र एवं सम्बन्धित राज्यों से समन्वय हो गया है।

नेता प्रतिपक्ष ने किया स्वागत

नेता प्रतिपक्ष श्री गुलाबचंद कटारिया ने मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा सभी दलों को एक मंच पर आमंत्रित करने की पहल की

मुक्तकंठ से प्रशंसा की। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि संकट की इस घड़ी में सभी को आरोप-प्रत्यारोप से परे होकर एकजुटता दिखानी चाहिए। तभी हम सफलतापूर्वक इसका सामना कर पाएंगे। वीसी के दौरान कई विधायकों ने गौशालाओं को अनुदान के फैसले का स्वागत किया।

अधिकतर सांसद–विधायकों ने प्रयासों को सराहा

अधिकतर सांसदों और विधायकों ने फंसे हुए श्रमिकों एवं प्रवासियों को अपने गृह स्थान पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री की पहल का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इससे लम्बे समय से पीड़ा झेल रहे श्रमिकों को संबल मिला है। उन्होंने इस आवागमन को अधिक सुगम बनाने के लिए अतिरिक्त ट्रेन एवं बसों की व्यवस्था करने का सुझाव दिया। साथ ही पास प्रक्रिया को सरल करने, दूसरी जगह से आने वाले लोगों के लिए गांव के स्कूल अथवा पंचायत भवन में संस्थागत क्वारेंटाइन की व्यवस्था, मनरेगा की सूचियों में नए मजदूरों के नाम जोड़ने सहित अन्य सुझाव दिए। जनप्रतिनिधियों ने कृषि मण्डियों में फसल खरीद की प्रक्रिया में सुधार करने, खाद और बीज की उपलब्धता, गर्मी के मौसम में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति एवं गौशालाओं में चारे-पानी की व्यवस्था सुदृढ़ करने की भी मांग की। सांसदों और विधायकों की ओर से कृषि मण्डियों में खरीद पर किसान कल्याण शुल्क हटाने की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह शुल्क किसान पर नहीं आढतियों पर लगाया गया है। उन्होंने सभी को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार यह भार किसी भी कीमत पर किसान पर नहीं पड़ने देगी।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान कोविड-19 महामारी को लेकर राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है।

इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री डी बी गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) श्री राजीव स्वरूप, अतिरिक्त मुख्य सचिव (चिकित्सा) श्री रोहित कुमार सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग) श्री सुबोध अग्रवाल, सूचना एवं जनसम्पर्क आयुक्त श्री महेन्द्र सोनी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

राजस्थान आने वाले श्रमिकों के रोजगार के लिए सरकार चिन्तित

प्रदेश में बनेगा 'लेबर एम्पलॉयमेंट एक्सचेंज'

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोविड-19 महामारी के कारण पैदा हुई स्थितियों को देखते हुए प्रदेश में ऑनलाइन 'लेबर एम्पलॉयमेंट एक्सचेंज' बनाया जाए ताकि लॉकडाउन के कारण संकट का सामना कर रहे श्रमिकों को उनके कौशल के अनुरूप रोजगार मिल सके और उद्योगों को उनकी जरूरत के मुताबिक श्रमिक उपलब्ध हो सकें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आने वाले एवं जाने वाले श्रमिकों तथा संनिर्माण श्रमिकों की ऑनलाइन मैपिंग की जाए।

श्री गहलोत मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से श्रम विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आपदा के इस दौर में श्रमिकों को संबल देना हमारा दायित्व है। इसे लेकर राज्य सरकार चिन्तित है। दूसरी तरफ उद्योगों को पटरी पर लाने के लिए श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना जरूरी है। श्रम विभाग की इसमें बड़ी भूमिका है। विभाग इसके लिए वे सभी प्रयास करें जिनसे पीड़ा झेल रहे इन श्रमिकों को जल्द से जल्द राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि स्किल डवलपमेंट के नए प्रॉजेक्ट डिजाइन किए जाएं जिनसे वर्तमान जरूरतों के मुताबिक श्रमिकों का कौशल विकास हो सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देशव्यापी लॉकडाउन के कारण बड़ी संख्या में राजस्थान में प्रवासी श्रमिक आए हैं और यहां से श्रमिक अन्य राज्यों में गए हैं। श्रम विभाग आने वाले श्रमिकों की योग्यता एवं उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करें ताकि ये श्रमिक उद्यमों में नियोजित होकर अपनी आजीविका अर्जन कर सकें। साथ ही श्रमिकों की अनुपलब्धता के कारण बंद बड़ी औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन शुरू हो सके।

प्रवासी राजस्थानी श्रमिक कल्याण कोष के गठन को मंजूरी

मुख्यमंत्री ने बैठक में प्रवासी राजस्थानी श्रमिकों के कल्याण के लिए बजट में घोषित 'प्रवासी राजस्थानी श्रमिक कल्याण कोष' के गठन को भी मंजूरी प्रदान की। उन्होंने कहा कि इस कल्याण कोष के माध्यम से प्रवासी राजस्थानी श्रमिकों को उनकी जरूरत के अनुरूप आवश्यक मदद प्रदान की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गरीब, जरूरतमंद एवं श्रमिकों के कल्याण के लिए जो भी योजनाएं संचालित हैं, मुसीबत के इस समय में उनके माध्यम से हर सम्भव सहायता सुनिश्चित की जाए। श्रम विभाग भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार यह भी सुनिश्चित करें कि कोई उद्यमी श्रमिकों को नहीं हटाएं और उनका वेतन नहीं काटें।

राज्य सरकार श्रमिकों के हित में कर रही बेहतर काम

श्रम राज्यमंत्री श्री टीकाराम जूली ने कहा कि राजस्थान सरकार श्रमिकों के आवागमन एवं उनके हितों को लेकर बेहतर ढंग से काम कर रही है। उन्होंने बताया कि विभाग प्रवासी श्रमिकों के कौशल के अनुरूप उनका डाटाबेस तैयार करवा रहा है ताकि उन्हें उद्योगों की आवश्यकता

के अनुरूप रोजगार से जोड़ा जा सके। कौशल विकास राज्यमंत्री श्री अशोक चांदना ने कहा कि प्रदेश में आए श्रमिकों का राजस्थान राज्य आजीविका विकास निगम के माध्यम से कौशल विकास करवाया जाएगा।

अब तक 6 लाख श्रमिक आ चुके राजस्थान

शासन सचिव (श्रम) डॉ. नीरज के पवन ने बताया कि अब तक करीब 6 लाख श्रमिक राजस्थान आ चुके हैं और करीब एक लाख 35 हजार श्रमिक राजस्थान से जा चुके हैं। श्रम विभाग इनका डाटाबेस तैयार करवा रहा है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों की मैपिंग का कार्य पूरा होने के बाद राज्य आजीविका विकास निगम के माध्यम से इनका कौशल विकास करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि विगत वर्षों में विभाग द्वारा प्रशिक्षित करीब 4 लाख लोगों की सूची उद्योग एवं स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध करवाई गई है ताकि उन्हें आवश्यकता के अनुरूप नियोजित किया जा सके।●

समय पर पूरी हो भर्तियां – मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार वह हर संभव प्रयास करेगी जिससे भर्तियां समय पर पूरी हों और अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए इंतजार न करना पड़े। उन्होंने कहा कि जो भर्तियां न्यायालयों में लंबित हैं, उनमें प्रभावी पैरवी करने के प्रयास करें जिससे लंबित भर्ती प्रक्रिया पुनः शुरू हो सके। श्री गहलोत ने कहा कि भर्तियों के न्यायिक वादों में उलझने के कारण नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ता है। इसका उनके मनोबल पर विपरीत असर पड़ता है और उनमें व्यवस्था के प्रति नकारात्मक सोच उत्पन्न होती है।

श्री गहलोत मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विभिन्न विभागों में प्रक्रियाधीन भर्तियों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रयास कर रही है कि आरपीएससी एवं राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड कैलेंडर के अनुरूप भर्तियां कराना सुनिश्चित करें। कोविड-19 के कारण यह कार्य प्रभावित हुआ है, लेकिन हम इसे जल्द से जल्द सुचारु करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कई बार सेवा नियमों की अड़चनों के कारण भी भर्तियां अटक जाती हैं। इन अड़चनों को दूर करने के लिए आवश्यक हो तो सेवा नियमों में भी संशोधन किया जाए। सभी विभागाध्यक्ष अपने-अपने विभागों में भर्तियों की प्रक्रिया को प्राथमिकता दें।

प्रथम पदस्थापन काउंसलिंग के आधार पर ही हो

उन्होंने निर्देश दिए कि भर्तियों में प्रथम नियुक्ति मेरिट एवं काउंसलिंग के आधार पर ही दी जाए ताकि पदस्थापन को लेकर किसी प्रकार की शिकायत नहीं रहे। मुख्यमंत्री ने शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, कृषि, कार्मिक सहित अन्य विभागों में प्रक्रियाधीन भर्तियों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी भर्तियों को टाइम बाउंड फ्रेम में पूरा किया जाए। जिन भर्तियों में परिणाम जारी हो चुके हैं, उनमें जल्द नियुक्तियां दी जाएं।

अब तक दी जा चुकीं 56 हजार 523 नियुक्तियां

वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 56 हजार 523 नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। साथ ही 12 हजार 341 पदों के परिणाम जारी किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त 26 हजार से अधिक पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए जा चुके हैं।

राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. बीएल जाटावत तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव श्री आशीष गुप्ता ने आश्वस्त किया कि जिन भर्तियों में प्रक्रिया पूरी हो चुकी है उनमें नियुक्ति के लिए जल्द से जल्द अभ्यर्थियों की सूची विभागों को भिजवाई जाएगी। अन्य भर्तियों को भी समय पर पूरा करने का प्रयास किया जाएगा।●

जिला एवं उपखण्ड स्तरीय अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस

पंचायत स्तर तक पुख्ता हो क्वारेंटाइन व्यवस्था

प्रवासियों को नहीं हो कोई असुविधा

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में जो कामयाबी हमें अभी तक मिली है उसे बरकरार रखने के लिए क्वारेंटाइन व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना होगा। श्री गहलोत मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला कलक्टर, जिला एवं उपखंड स्तरीय अधिकारियों से क्वारेंटाइन व्यवस्थाओं पर चर्चा कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले से लेकर पंचायत स्तर तक मौजूद सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को मिलकर क्वारेंटाइन व्यवस्था को ग्राम स्तर तक सुचारु बनाना होगा। इस काम में सांसदों, विधायकों के साथ-साथ सभी शहरी एवं पंचायत जनप्रतिनिधियों की बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि ट्रेन से आने वाले लोगों की रेलवे स्टेशन पर ही स्क्रीनिंग करवाकर बसों से उन्हें गन्तव्य स्थल तक पहुंचाने की व्यवस्था करें। संभव हो तो रेलवे स्टेशन पर उन्हें चाय-नाश्ता उपलब्ध कराएं और बसों में खाने के पैकेट व पानी रखवाया जाए ताकि उन्हें आगे के सफर में आसानी हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि जालोर, सिरोही एवं पाली जैसे जिलों को क्वारेंटाइन व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना होगा क्योंकि वहां बाहर से आने वाले प्रवासियों की संख्या हजारों में हैं। डूंगरपुर एवं भरतपुर जैसे सीमावर्ती जिलों को भी प्रवासियों के लिए समुचित इंतजाम रखने होंगे।

उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले प्रवासियों के क्वारेंटाइन के लिए स्थानीय विधायकों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों का सहयोग लें, उनसे संपर्क स्थापित करें ताकि बेहतर तालमेल के साथ ग्राम स्तर पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो सकें। क्वारेंटाइन के लिए जगह चिह्नित करने और ग्राम स्तर पर बनाये गये संस्थागत क्वारेंटाइन सेंटर्स पर भोजन-पानी की व्यवस्था में भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाए। गांव वालों को भी विश्वास में लेकर होम क्वारेंटाइन रखे गए एवं बाहर से आने वाले प्रवासियों की मॉनिटरिंग में उनका सहयोग लिया जाए। एनसीसी, एनएसएस, स्काउट और नेहरू युवा केन्द्र से जुड़े युवाओं का भी सहयोग लिया जा सकता है। आपदा के समय जिस गंभीरता से काम किया जाता है वैसा हमारे प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं भामाशाहों सभी ने मिलकर किया है। कोरोना का सामना करने में राजस्थान ने प्रो-एक्टिव होकर काम किया है। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए यहां अपनाये गये उपायों की देश-विदेश में जमकर प्रशंसा हुई है। स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा मजबूत करते हुए हमें आगे भी इसी जज्बे के साथ लड़ाई जारी रखनी होगी। हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि प्रदेश में अभी 12 हजार से ज्यादा टेस्टिंग की सुविधा प्रतिदिन उपलब्ध है। •

कोरोना के डर से बीमारी को नहीं छुपाएं

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेशवासी कोविड-19 को लेकर डरने के बजाय तुरंत अस्पताल पहुंचकर अपनी जांच कराएं और उपचार लें। कोरोना सहित किसी भी बीमारी को छुपाने की कोशिश नहीं करें। हमारा माइक्रो मैनेजमेंट ऐसा हो कि प्रदेश में इलाज के अभाव में कोई जान नहीं जाए।

कोरोना के संक्रमण, जांच एवं इलाज, क्वारंटाइन सुविधाओं तथा गैर-कोविड रोगों के लिए चिकित्सकीय सुविधाओं की स्थिति के बारे में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि हमें लगातार सतर्क एवं सजग रहने की जरूरत है। विशेषकर राजस्थान आ रहे श्रमिकों की प्रभावी स्क्रीनिंग, जांच एवं क्वारंटाइन को मजबूत किया जाना जरूरी है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में सैम्पलिंग बढ़ाई जाए।

अब तक कोरोना से हुई मौतों का कराएं गहन विश्लेषण

उन्होंने निर्देश दिए कि राजस्थान में अब तक कोरोना से हुई 125 मौतों का विशेषज्ञों द्वारा विश्लेषण किया जाए। इन मौतों का गहन अध्ययन करने के लिए मृतकों के परिजनों से मिलकर रोगियों की पूरी केस हिस्ट्री, देरी से अस्पताल पहुंचने के कारणों, अन्य पुरानी बीमारियों की स्थिति की जानकारी लेकर उसका तार्किक विश्लेषण किया जाए। तभी हम कोरोना की लड़ाई के लिए चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार और लोगों को जागरूक करने की बेहतर रणनीति तैयार कर सकेंगे।

जेलों में भी मेडिकल प्रोटोकॉल की हो पूरी पालना

मुख्यमंत्री ने जयपुर जेल में एक साथ बड़ी संख्या में कैदियों के कोरोना पॉजिटिव होने के मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा कि इन मरीजों को उचित चिकित्सा उपलब्ध करवाने के साथ ही कोरोना के तय मेडिकल प्रोटोकॉल की जेलों में भी पूरी पालना सुनिश्चित की जाएं।

आमजन को कोरोना के साथ जीने के लिए तैयार करें

श्री गहलोत ने कहा कि प्रदेश में कोरोना से होने वाली मौतों का प्रतिशत कम है। हमने अपनी टेस्ट क्षमता काफी बढ़ा ली है। अब गिने-चुने मामलों में ही वेंटीलेटर की आवश्यकता पड़ रही है। ये सब अच्छे संकेत हैं, लेकिन आगे कोरोना किस रूप में सामने आए, इसे लेकर हमें सजग रहने की जरूरत है। उन्होंने विशेषज्ञों से कहा कि वे ऐसी नियमावली बनाएं, जिसका पालन कर आमजन खुद को कोरोना के साथ जीने के लिए तैयार कर सकें। जिससे आमजन जागरूक हो सकें और उसे दिनचर्या का हिस्सा बना पाएं।●

मुख्यमंत्री ने दी सहायक रेडियोग्राफर के 1058 रिक्त पदों पर भर्ती को मंजूरी

कोविड-19 महामारी के संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सहायक रेडियोग्राफर के 1058 रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। श्री गहलोत ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में 37 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है। इसमें सूचना सहायक के 10, लिपिक ग्रेड द्वितीय के 10, लिपिक ग्रेड प्रथम के 4 पद तथा 6 पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के हैं। इसके अलावा अनुभागाधिकारी, सहायक अनुभागाधिकारी एवं सहायक प्रोग्रामर के 2-2 पद तथा सहायक शासन सचिव का 1 पद सृजित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत सीकर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, चूरू, जालोर एवं पुलिस जिला भिवाड़ी में स्थापित विशिष्ट न्यायालयों में सहायक निदेशक अभियोजन के 1-1 पद के सृजन की स्वीकृति दी है।

इसके अलावा राजकीय महाविद्यालय, राजाखेड़ा को स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत करने एवं वहां राजनीति विज्ञान विषय में सहायक आचार्य के 2 पद सृजित करने तथा महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर में विधि संकाय के सहायक आचार्य के 2 पदों के सह आचार्य के पदों पर क्रमोन्नत करने के प्रस्तावों को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी है।●

फीस जमा नहीं होने पर स्कूल नहीं काटें किसी विद्यार्थी का नाम, अभिभावकों को राहत के लिए कराएं परीक्षण

आरटीई की आय सीमा अब ढाई लाख

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा है कि लॉकडाउन के कारण कोई अभिभावक आर्थिक स्थिति के चलते फीस जमा नहीं करा पाता है तो निजी स्कूल ऐसे विद्यार्थी का नाम नहीं काटें। यदि कोई स्कूल ऐसा करता है तो राज्य सरकार उसकी मान्यता निरस्त कर सकती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग इस बात का भी परीक्षण कराएं कि निजी स्कूल विद्यार्थियों को फीस एवं अन्य शुल्कों में किस प्रकार राहत दे सकते हैं और उन विद्यालयों का संचालन भी प्रभावित नहीं हो।

श्री गहलोत मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए स्कूल शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा से जुड़े विषयों पर समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मानवता के समक्ष यह ऐसा संकट है जिसका हम सभी को मिलकर सामना करना है। ऐसे वक्त में एक-दूसरे का ध्यान रखकर ही हम इस मुश्किल वक्त का मुकाबला कर सकते हैं।

सीबीएसई के अनुरूप लेंगे बोर्ड परीक्षाओं पर निर्णय

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दसवीं एवं बारहवीं कक्षाओं की शेष परीक्षाएं फिलहाल स्थगित रहेंगी। बाद में सीबीएसई द्वारा लिए जाने वाले निर्णय के अनुरूप फैसला किया जाएगा ताकि दोनों बोर्ड की परीक्षाओं में एकरूपता बनी रहे और प्रदेश के विद्यार्थियों का अहित न हो। इसी प्रकार उच्च एवं तकनीकी शिक्षा में भी परीक्षाओं का आयोजन स्थितियां सामान्य होने पर करवाया जा सकेगा।

ग्रीष्मावकाश में मिड–डे–मील का हो पारदर्शी वितरण

श्री गहलोत ने निर्देश दिए कि शिक्षा विभाग ग्रीष्मावकाश में बच्चों को मिड-डे-मील के लिए उचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण बच्चों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराना संभव नहीं है। ऐसे में अभिभावकों को सूखी राशन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

सभी भर्तियों में मेरिट एवं काउंसलिंग से होगी प्रथम नियुक्ति

मुख्यमंत्री ने लिपिक ग्रेड द्वितीय भर्ती परीक्षा-2018 के अभ्यर्थियों को जिला एवं विभागों का आवंटन पुन: नई प्रक्रिया से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभागों को मेरिट के आधार पर उनकी आवश्यकता के अनुरूप चयनित अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध कराएं। उसके बाद संबंधित विभाग मेरिट एवं काउंसलिंग के आधार पर उन्हें जिला आवंटित करें। उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि भविष्य में सभी भर्तियों में प्रथम नियुक्ति सभी विभागों द्वारा मेरिट एवं काउंसलिंग के आधार पर ही दी जाएं।

आरटीई की आय सीमा फिर से ढाई लाख होगी

श्री गहलोत ने कहा कि यूपीए सरकार के समय ''शिक्षा का अधिकार अधिनियम'' लाकर गरीब वर्ग के बच्चों को निजी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने का ऐतिहासिक कदम उठाया गया था। विगत कुछ वर्षों में इस कानून की भावना के अनुरूप जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को इसका लाभ नहीं मिल पाया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस कानून की पारदर्शिता के साथ पालना सुनिश्चित करवाई जाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आरटीई के जरिए बच्चों को बड़े नामी निजी स्कूलों में भी पढ़ने का अवसर मिलें। इसके लिए अभिभावकों की आय सीमा को एक लाख से बढ़ाकर ढाई लाख रुपए किया गया है।

अनुपयोगी स्कूल भवनों का हो उपयोग

मुख्यमंत्री ने कहा कि गत सरकार के समय एकीकरण के नाम पर बड़ी संख्या में स्कूल बंद कर दिए गए थे। ऐसे विद्यालयों के अनुपयोगी पड़े भवनों का उपयोग विद्यालयों को पुन: खोलने के साथ-साथ जरूरत होने पर पंचायत, उपकेन्द्र तथा सामुदायिक केन्द्रों के रूप में भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिन महाविद्यालयों के भवनों का निर्माण नहीं हुआ है उनके लिए भी योजना बनाकर दें ताकि राज्य सरकार विभिन्न माध्यमों से इनके भवनों का निर्माण करवाने पर कार्यवाही कर सकें।

बैठक में शिक्षा राज्यमंत्री श्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं का उच्च अध्ययन एवं कैरियर को लेकर अपना महत्त्व है। ऐसे में विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखकर ही इस संबंध में निर्णय लिया जाना उचित होगा। उन्होंने कहा कि विभाग में सीनियर सैकंडरी स्कूल के प्रिंसिपल पद पर पदोन्नति के लिए नियमों में संशोधन कर इसे तर्कसंगत बनाया जा रहा है। साथ ही वरिष्ठ अध्यापक के चयनितों को जल्द नियुक्ति देने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि गरीब परिवारों के बच्चों को आरटीई के तहत पारदर्शी तरीके से प्रवेश दिलाना सुनिश्चित किया जाएगा।

उच्च शिक्षा राज्यमंत्री श्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की एक समिति की रिपोर्ट के आधार पर परीक्षाओं को लेकर उचित निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 15 अप्रैल से 31 मई तक महाविद्यालयों में ग्रीष्मावकाश घोषित किया गया है ताकि नया सत्र एक जून से प्रारंभ किया जा सके।

उन्होंने बताया कि उच्च शिक्षा में करीब 3 लाख से अधिक विद्यार्थियों को ई-कंटेंट के आधार पर शिक्षा से जोड़ा गया है। लेक्चरर्स ने वर्क फ्रॉम होम में रहते हुए यू-ट्यूब, वॉट्सएप आदि माध्यमों से ई-कंटेंट उपलब्ध कराया है।

तकनीकी शिक्षा राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने बताया कि पॉलीटेक्निक कॉलेजों के सिलेबस को आधुनिक शिक्षा के अनुरूप बदला गया है जिससे इनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों को प्लेसमेंट प्राप्त करने में आसानी होगी। तकनीकी शिक्षा सचिव शुचि शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के अनुसार उच्च शिक्षा में आनन्दम कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इससे विद्यार्थियों में सामुदायिक सेवा की भावना विकसित होगी और वे प्रोफेशनलिज्म के साथ-साथ समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझ सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने की 'इंदिरा प्रियदर्शिनी बेबी किट' वितरण कार्यक्रम की शुरुआत

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजकीय चिकित्सालयों में जन्म लेने वाली नवजात बालिकाओं को निःशुल्क दिये जाने वाले 'इंदिरा प्रियदर्शिनी बेबी किट' वितरण कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री निवास से की। श्री गहलोत ने जनाना हॉस्पिटल, जयपुर से आई दो प्रसुताओं सोनम एवं मीनाक्षी की नवजात बालिकाओं को पिंक कलर के किट सौंपे।

इस अवसर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा, राज्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) डॉ. सुभाष गर्ग, अतिरिक्त मुख्य सचिव (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) श्री रोहित कुमार सिंह, एमडी (नेशनल हैल्थ मिशन) श्री नरेश कुमार ठकराल एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

जयपुर जिले के राजकीय चिकित्सा संस्थानों में जन्म लेने वाली बालिकाओं को सोमवार से पिंक कलर का बेबी किट मिलना शुरू हो जायेगा। अन्य जिलों में अगले कुछ दिनों में किट वितरण कार्यक्रम शुरू कर दिया जायेगा। उल्लेखनीय है कि बच्चे के जन्म लेते ही उसे पुराने कपड़ों में लपेटने से होने वाले इंफेक्शन के खतरे को रोकने और नवजात को हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए वर्ष 2019-20 के राज्य बजट में इसकी घोषणा मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने की थी। शिशु मृत्युदर में कमी लाने के उद्देश्य से नवजात बालकों को भी जुलाई, 2020 से नीले रंग का किट वितरित किया जायेगा। योजना के तहत प्रतिवर्ष राजकीय चिकित्सा संस्थानों में जन्म लेने वाले करीब 11 लाख से अधिक नवजात बालक-बालिकाओं को इंदिरा प्रियदर्शिनी बेबी किट दिये जायेंगे। इस पर प्रतिवर्ष करीब दस करोड़ रुपये खर्च होंगे।

राजस्थान के प्रवासियों को महाराष्ट्र से लेकर जयपुर पहुंचीं दो ट्रेन

लॉकडाउन के कारण महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों में फंसे करीब 2400 प्रवासी राजस्थानियों को लेकर दो ट्रेनें जयपुर रेलवे जंक्शन पहुंचीं। यात्रियों के यहां पहुंचने से पहले ही जिला प्रशासन द्वारा यात्रियों को ट्रेनों से उतरने के बाद समुचित स्क्रीनिंग, भोजन प्रदान कर गंतव्य के लिए आरएसआरटीसी की बसों में बिठाने की पूरी व्यवस्था कर ली थी। जयपुर के जिला कलक्टर डॉ. जोगाराम के अनुसार एक दिन पहले ही सूचना मिली थी कि दो ट्रेनें प्रदेश के करीब 2400 यात्रियों को लेकर यहां पहुंच रही हैं। रेलवे अधिकारियों से समन्वय कर जिला प्रशासन द्वारा इन यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग एवं सभी मेडिकल प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इनके गंतव्य के लिए रेलवे स्टेशन से ही बसों में बिठाने की व्यवस्था कर ली गई थी। पूरे स्टेशन के प्लेटफार्म पर यात्रियों के उतरने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग के लिए चार लाइनें बनाई गईं। उतरते ही उनको दिए गए टोकन के अनुसार सम्बन्धित लाइन पर पहुंचाया गया। यहां उनकी आधा दर्जन टीमों द्वारा स्क्रीनिंग की गई एवं उनको फूड पैकेट्स प्रदान किए गए।

स्टेशन पर पूरी व्यवस्था को सुनिश्चित करने में जिला प्रशासन, पुलिस, रेलवे, नगर निगम, मेडिकल, रोडवेज समेत कई विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी लगे हुए थे और यात्रियों का भी पूरा सहयोग रहा जिससे सभी यात्री समुचित स्क्रीनिंग के बाद बसों में अपने गंतव्यों पर रवाना हो गए।

यहां से सभी बसें सिन्धी कैम्प स्थित रोडवेज मुख्यालय पहुंचीं जहां जिला प्रशासन एवं रोडवेज के अधिकारियों ने सभी बसों में मौजूद यात्रियों की सूची का मिलान कर गंतव्य तक उनके पहुंचने के इंतजामों को सुनिश्चित किया एवं बसों को सम्बन्धित जिलों को रवाना किया।

उल्लेखनीय है कि सुबह 8:30 बजे पहुंची पहली ट्रेन में 1207 यात्री थे जो अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, चूरू, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झुंझुनू, जोधपुर, कोटा, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमन्द, सीकर, सिरोही, उदयपुर जिलों के थे। इनमें जयपुर के 13 यात्री शामिल थे।

इसी प्रकार दूसरी ट्रेन 1194 लोगों को लेकर आई जिसमें बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चूरू, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़,

जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झुंझुनूं, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, पाली, राजसमन्द, सीकर, सिरोही, उदयपुर के यात्री सवार थे। इस ट्रेन में जयपुर के 278 यात्री सवार थे।

वीडियो कॉंफ्रेंसिंग कर क्वारेंटाइन किए जाने बाबत दिए निर्देश

दोनों ट्रेनों में पहुंचे जयपुर जिले के 291 लोगों को आवश्यकतानुसार होम या संस्थागत क्वारेंटाइन किए जाने के सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में दो दिन पहले ही विस्तृत निर्देश जारी किए जा चुके हैं। अन्य जिलों के यात्रियों के बारे में भी सम्बन्धित जिलों के कलक्टर्स को जानकारी दे दी गई है।

यात्रियों ने किया तालियां बजाकर घर लौटने की खुशी का इजहार

लॉकडाउन के कारण लम्बे समय तक फंसे रहने के बाद अपने घर लौटने की खुशी यात्रियों की आंखों में नजर आ रही थी। कई यात्रियों ने इस खुशी को तालियां बजाकर अभिव्यक्त किया। यात्रियों में छोटे बच्चों से लेकर कई बुजुर्ग भी शामिल थे। बसों में बैठते हुए भी कई यात्री विक्ट्री साइन बना रहे थे। ●

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने किया जयपुर का दौरा

प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए प्रयासों पर जताया संतोष

कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दल ने जयपुर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (जयपुर प्रथम) डॉ. नरोत्तम शर्मा ने बताया कि मंत्रालय दल के सदस्यों को सीएमएचओ की ओर से क्षेत्र में की गई कार्यवाही से अवगत करवाया गया।

डॉ. शर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने सीएमएचओ (जयपुर प्रथम) के कार्यालय पहुंचकर गतिविधियों की ब्रीफिंग लेने के बाद शहर के कन्टेनमेंट जोन रामगंज क्षेत्र के सुभाष चौक एवं आसपास के क्षेत्र का दौरा कर सर्वे, स्क्रीनिंग व सैम्पलिंग की प्रक्रिया एवं कर्फ्यू की स्थिति का निरीक्षण किया। टीम ने की गई तैयारियों एवं कार्यप्रणाली पर संतोष व्यक्त किया। इस टीम में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से निदेशक (आपदा प्रबंधन) डॉ. दास, डॉ. बनर्जी, डॉ. नवीन, डॉ.जयदीप शामिल थे। डीपीएम अखिलेश शर्मा सहित कई अधिकारी इस दौरे में साथ रहे। ●

दिल्ली की डाक

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की पहल पर नई दिल्ली के एम्स अस्पताल में पैर के कैंसर के इलाज के लिए आई अजमेर जिले के पुष्कर की बालिका, विशाखा की मदद की गई। मुख्यमंत्री से गायत्री परिवार के प्रतिनिधि मण्डल ने भेंट कर गायत्री शक्ति पीठ पर आने का आमंत्रण दिया। बीकानेर हाउस में कोरोना वायरस से बचाव पर विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया।

बीकानेर हाउस में कोरोना वायरस से बचाव और उपायों पर कार्यशाला

राष्ट्रीय राजधानी में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के प्रकोप से बचने के उपायों पर बीकानेर हाउस परिसर स्थित राजकीय चिकित्सालय के चिकित्सकों द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस आयोजन में दिल्ली स्थित राज्य सरकार के सभी कार्यालयों के प्रभारी अधिकारियों सहित सभी विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। कोरोना वायरस के बारे में जानकारी देते हुए चिकित्सालय की डॉ. सविता अग्रवाल ने बताया कि यह वायरस एक संक्रामक वायरस है जिसके लक्षण सर्दी-जुकाम की तरह ही हैं तथा यह एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे में फैलता है। प्रारंभिक तौर पर इसमें संक्रमित व्यक्ति को बुखार-खांसी छींक, नाक बहना सांस लेने में दिक्कत छाती में जकड़न, निमोनिया, गुर्दो की समस्या आती है। उन्होंने बताया कि संकमण के पश्चात् लक्षण को दिखाई देने में 7-14 दिन लगते हैं। डॉक्टर ने बताया कि इस वायरस के संक्रमण से बचने के लिए, खांसते या छींकते समय नाक मुंह को रूमाल से ढ़कें, हाथों को बार-बार साबुन व पानी से धोएं या एल्कोहल युक्त सेनिटाइजर का प्रयोग करें, भीड़-भाड़ वाली जगह जाने से बचें, हैंडल स्विच, फोन इत्यादि को साफ करते रहें, फ्लूग्रस्त व्यक्ति से 6 फुट की दूरी रखें, फ्लू के लक्षण होने पर घर में ही रहें, पानी व पोषक भोजन प्रचुर मात्रा में लें, फ्लू होने पर डॉक्टर को दिखाएं। फ्लू होने पर भरपूर आराम करें, फ्लू होने पर रोगी व उसकी देखभाल करने वाले स्वास्थ्यकर्मी, रिश्तेदार मास्क का प्रयोग करें।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर अधिकारियों ने कैंसर पीड़ित विशाखा को पहुंचाया पैतृक स्थान

नई दिल्ली के एम्स अस्पताल में पैर के कैंसर के इलाज के लिए आई अजमेर जिले के पुष्कर की बालिका, विशाखा को अस्पताल से अचानक छुट्टी देने के उपरांत उसके पैदल ही अपने पैतृक गांव के लिए निकलने की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने दिल्ली स्थित राज्य सरकार के अधिकारियों के माध्यम से तुरंत अजमेर भिजवाने की व्यवस्था करवाई। अस्पताल की बेरूखी का शिकार हुई विशाखा की इस घटना की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इसके लिए स्वयं संज्ञान लेते हुए इस संबंध में अजमेर एवं दिल्ली स्थित अधिकारियों को तुरंत कार्यवाही के निर्देश प्रदान किए।

दिल्ली स्थित राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त श्री धीरज श्रीवास्तव ने तुरंत विशाखा और उसके परिजनों से संपर्क स्थापित कर उनके रात्रि विश्राम एवं भोजन की व्यवस्था करवाई। इसके उपरांत दिल्ली पुलिस कमिश्नर और एम्स के डायरेक्टर से बात कर विशाखा के इलाज की मुकम्मल व्यवस्था भी सुनिश्चित की।

मुख्यमंत्री से मिला गायत्री परिवार का प्रतिनिधिमंडल

राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत से गायत्री परिवार के उदयपुर संभाग के प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली स्थित जोधपुर हाउस में मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में गायत्री परिवार के भूपेंद्र पंड्या, शिवराम कलाल, लक्ष्मणलाल निनामा, कुबेर शर्मा, पूंजी लाल मीणा और भारत भट्ट शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री श्री गहलोत को सागवाड़ा गायत्री शक्ति पीठ पर पधारने के लिए आमंत्रण दिया।

प्रस्तुति : शिवराम मीणा

कोरोना की जंग जीतकर

पढ़ा रहे सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ

पाली जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 162 पर आबाद ढ़ोला गांव के बाहर बने टोल बूथ पर 39 वर्षीय माधोसिंह को देखते हुए एक बार तो यह एहसास नहीं होता कि यह व्यक्ति कुछ दिनों पहले कोरोना सरीकी महामारी को हराकर आज अन्य लोगों के लिए प्रेरणास्रोत बना हुआ है। यह 39 वर्षीय व्यक्ति पाली जिले का पहला कोरोना संक्रमित है। कोरोना की जंग जीतने के बाद से यह व्यक्ति खुद की सेहत का ध्यान रखते हुए रोजाना टोल बूथ पर आने जाने वाले जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री, पानी की बोतल के साथ कोरोना से जागरूकता की सीख दे रहा है।

प्रशासनिक सोच और सूझबूझ के कारण माधोसिंह जिले के उन कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए एक मिसाल है जो कोरोना सरीकी महामारी से घबराकर अपने होश-हवास खो रहे हैं। माधोसिंह कहते हैं कि कोरोना को हराने के लिए घबराहट सबसे बड़ी बाधा है। इस बाधा को आत्मविश्वास के बल पर दूर कर कोरोना महामारी का मुकाबला किया जा सकता है। वे बताते हैं कि दुबई से मुम्बई लौटने के बाद मुम्बई एयरपोर्ट पर उनकी स्क्रीनिंग की गई थी। वे 19 मार्च को ढ़ोला गांव ट्रेन के माध्यम से पहुंचे थे। मुम्बई से ढ़ोला के सफर में उन्हें खुद के शरीर में बुखार महसूस हुआ। गांव पहुंचते ही उन्होंने रानी पीएचसी चिकित्सकों से परामर्श लिया। यहां से उन्हें जोधपुर जाने की सलाह दी गई थी लेकिन वे जांच के लिए पाली के राजकीय बांगड़ अस्पताल पहुंचे। यहां उनमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। जब उन्हें खुद के कोरोना संक्रमित होने का पता चला तो वे बिना घबराए चिकित्सकों के हर निर्देश का पालन करने लगे। माधोसिंह कहते हैं कि आज के समय में लोग इस बीमारी से घबराकर स्वस्फूर्त चिकित्सकों के पास जाने से डरते हैं जबकि इस बीमारी से जीत डर को पराजित करने से ही मिल सकती है।

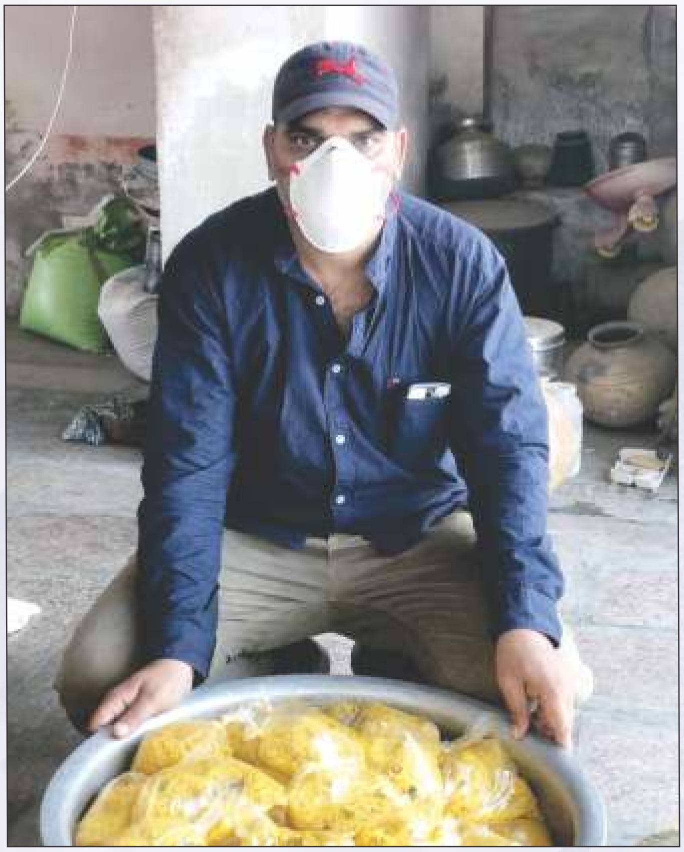

माधोसिंह बताते हैं कि कोरोना संक्रमण की पुष्टि के बाद जब उन्हें जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में उपचाररत किया गया था तब उन्होंने भजन सुनने तथा प्राणायाम व योग करने को रोजाना अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया था। अस्पताल में उपचार के दौरान चिकित्सकों व नर्सिंग कर्मियों की हौसला अफजाई तथा रोजाना परिजनों से फोन पर वीडियो कॉलिंग के दौरान मिलने वाले संबल के कारण उन्होंने कोरोना जैसी महामारी को पराजित कर दिया। पाली जिले का पहला कोरोना संक्रमित होने के बावजूद उन्होंने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। इसी का नतीजा निकला कि वे 14 दिन पूरा उपचार लेकर स्वस्थ होकर घर लौटे। उन्होंने कोरोना संक्रमण से लड़ाई के दौरान प्रशासन एवं चिकित्सा विभाग द्वारा दिए गए सहयोग को सराहनीय बताया।

ढ़ोला गांव के सरपंच मेघा परमार व माधोसिंह के भाई महेन्द्रसिंह बताते हैं कि कोरोना की महामारी से जंग जीतने के बाद अब माधोसिंह पूरे गांव के लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाते हैं। इसके अलावा वे ग्रामीणों को साफ-सफाई, सेनेटाइजेशन तथा एक दूसरे से दूरी बनाकर रखने की सलाह भी देते हैं। यहां ये जानने योग्य है कि ढ़ोला गांव निवासी माधोसिंह रेडिमेड गारमेंट्स के व्यवसायी हैं। कारोबार के लिहाज से वे दुबई गए थे जहां से कोरोना का संक्रमण उनके साथ लौटा। ●

–सुनील दत्त त्रिवेदी

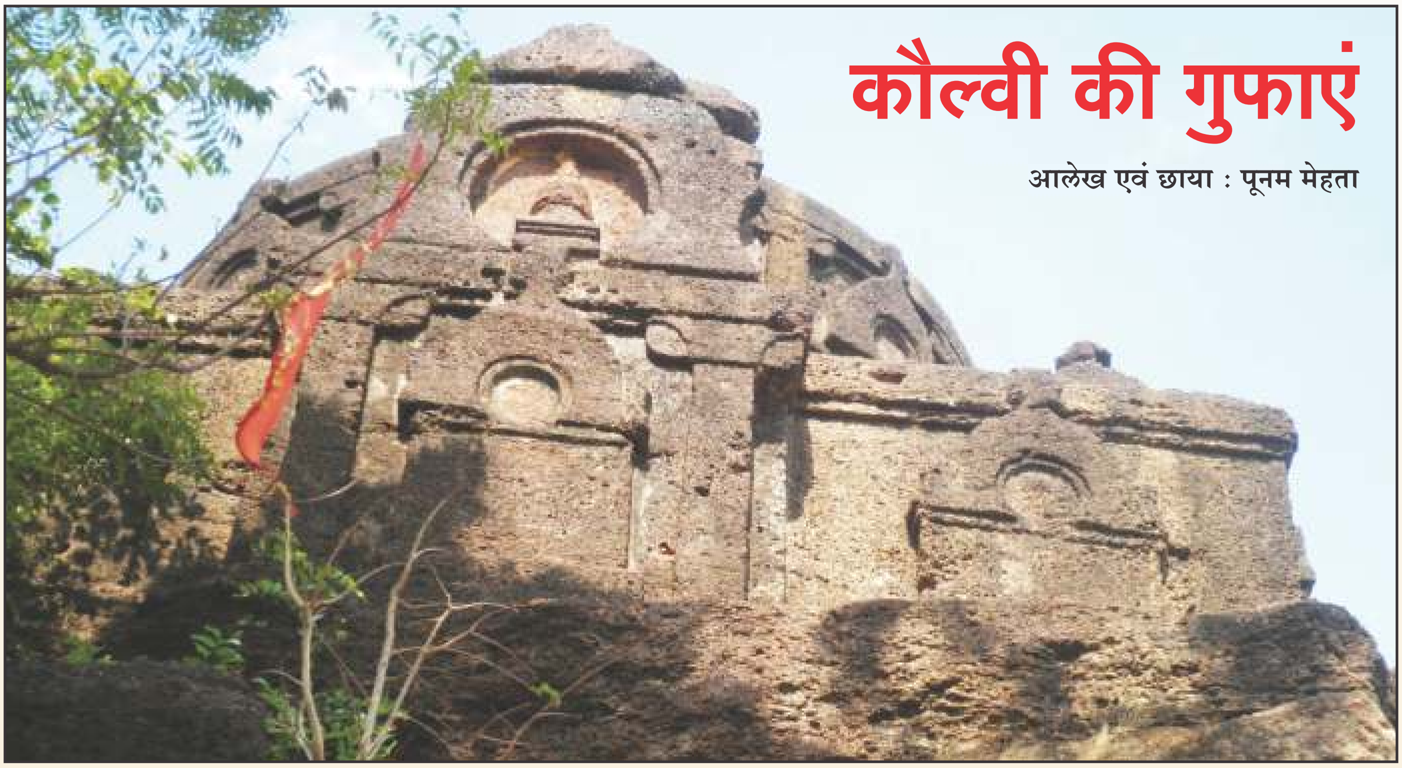

कौल्वी की गुफाएं

आलेख एवं छाया : पूनम मेहता

कोटा से झालावाड़ जाते राष्ट्रीय राजमार्ग बावन पर बनी नई सड़क पर गाड़ी मानो फिसलती हुई जाती है। सड़क के दोनों ओर हरियाली। दरा घाटी में अप्रैल से जून तक पलाश के पेड़ लाल रंग के पत्तों से ढक जाते हैं। प्रतीत होता है जंगल में आग लग गई हो। लाल मुंह के बंदर भी मुकुन्दरा रिजर्व के रास्ते पर बहुतायत से मिलते हैं।

अप्रैल-मई में बरौनियों से लदे आम, निम्बोली से आच्छन्न नीम की खुशबू से समस्त वायुमण्डल महक जाता है। ट्रेन से यदि आप डग जाना चाहें तो चौमहला नज़दीकी स्टेशन है। सड़क मार्ग से यात्रा करना चाह रहे हैं तो आप पहले कोटा से भवानीमण्डी जाएं तत्पश्चात् डग। डग तहसील भवानीमण्डी से डेढ़ घंटे की दूरी पर है।

कोटा से डग, पांच टोल नाकों पर रुकने के अलावा आप कहीं ठहरते नहीं है। छोटे-छोटे पहाड़, खेत जिनमें धनियां, संतरे के पेड़, अफीम की पौध, आप देख सकते हैं। मार्ग में रेवा नदी और कण्ठाल नदी जैसी छोटी-छोटी नदियाँ आती हैं जिन पर पुल बने हुए हैं।

डग की ओर बढ़ते हुए सड़क के एक मोड़ पर अचानक हरे रंग के कुछ साइनबोर्ड उभरते हैं। विनायका बौद्ध गुफाएँ डग तहसील से कुछ पहले हैं। सड़क के दाहिने हाथ पर 'कौल्वी गुफाएँ' लिखा है सड़क के उस किनारे, कच्चा रास्ता गुफाओं की ओर जाता है। काले पत्थरों से बना यह रास्ता आठवीं शताब्दी लिए चलता है। कौल्वी की गुफाएँ झालावाड़ की डग तहसील की शान हैं। पहाड़ी के ऊपर यह गुफाएँ निर्मित हैं। पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा गार्डरूम नीचे बनाया गया है। पहाड़ी पर चढ़ने के लिए रेलिंग लगायी गयी है। पहाड़ी पर से दूर- दूर तक का नजारा दिखाई देता है। पक्का रास्ता तो यहाँ के लिए निर्मित कर दिया गया है पर कोई गार्ड यहाँ दिखाई नहीं देता। पर्यटक यदा-कदा यहाँ पदार्पण करते हैं। रेवड़ चराने वालों से ही यहाँ का सन्नाटा टूटता है।

अकेला मनुष्य गुफाओं में आने की कल्पना भी नहीं कर सकता क्योंकि बस्ती से बहुत दूर अलग-थलग यह इतिहास की ऐसी थाती है जिस पर ज्यादा प्रकाश अभी नहीं डाला गया है और इतिहासविद् या पुरातत्त्व में रुचि रखने वाले अथवा पर्यटक ही इस ओर रुख करते हैं। नाला कियासरा की लाल मिट्टी के तट पर स्थित पहाड़ी पर बनी हैं पचास गुफाएँ जिनमें से सैंतालीस ही दिखती हैं। यह माना जाता है कि ये गुफाएँ बौद्ध भिक्षुओं के लिए निवास स्थान थीं, जो 5 वीं और 8 वीं शताब्दी के बीच शांति की तलाश में यहां आए थे। गुफाओं में जानवर न घुसें इसलिए पुरातत्त्व विभाग द्वारा जालीदार दरवाजे लगवाए गए हैं। कौल्वी में पत्थरों से तराशे बौद्ध चैत्य

और विहार का समूह है, जिसमें दो मंजिला कमरे (विहार), पूजा स्थल (चैत्य) हैं। फर्श से छत तक के स्तूप बने हैं। कौल्वी गुफाओं में बुद्ध की कई मूर्तियाँ ध्यान और खड़ी अवस्था में हैं। इस स्थल में स्तूप और चैत्य भी हैं जो वास्तुकला का प्रदर्शन करते हैं और इस क्षेत्र में हीनयान संप्रदाय के प्रभुत्व को दर्शाता है। छेद वाले पत्थर से निर्मित यहाँ के स्तूप और विहार गोलाकार हैं। विभिन्न मुद्राओं और अवतारों में बुद्ध को दर्शाने वाली चट्टानों से कई छोटे स्तूपों को उकेरा गया है। बोद्धिसत्व की 15 फीट ऊँची सबसे बड़ी प्रतिमा है। यहाँ एक गुफा में एक गुंबददार छत के साथ उनके अतीत के निशान हैं और दूसरी में पत्थर के खंभे हैं। पहाड़ का पत्थर छिद्रित है और कोमल भी। ऊपर चढ़ते वक्त एक गुफा जो चट्टान से ढक गई है वह रहस्यमयी सी प्रतीत होती है। गुफाओं को देखते हुए हैरानी होती है कि संपूर्ण पहाड़ को तराश के कैसे रहने और आराधना करने का स्थान बनाया होगा।

प्राचीन दिखने वाले भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण के साइनबोर्ड में यहाँ एक स्तूप की मौजूदगी का उल्लेख है लेकिन इसमें से बहुत कम बचा है। कौल्वी में गुफाएं खाली नहीं हैं। बुद्ध की कई छवियां आसपास हैं।

यहाँ आकर के अजीब सी शांति मन में महसूस होती है। गुफाएँ मन में विश्वास जगाती हैं। आत्मबोध के लिए निश्चित ही बुद्ध साधुओं के पास इससे अधिक अच्छा स्थान नहीं रहा होगा। पहाड़ के पत्थर को तराशकर उकेरी गयी प्रतिमाएँ भले ही धूल धूसरित हो गई हों, इतिहास का अप्रतिम प्रमाण अब भी हैं।

गुफाएँ देखते वक्त ठंडी हवा आपको छूती हुई निकलती है तो लगता है उस सदी का मंजर जीवंत हो गया हो। आत्मध्यान, आत्म-अनुशासन और श्रद्धा की प्रतीक यह गुफाएँ जिस तटस्थता से आज भी खड़ी हैं अचम्भित कर देने वाला है।

कौल्वी की गुफाओं से कुछ किलोमीटर दूर स्थित है कियासरा का शिव मंदिर। इसे सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पहाड़ी की ऊँचाई पर बना यह शिवलिंग प्रतिवर्ष बढ़ रहा है। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि कभी वे झुक के पूजा अर्चना किया करते थे आज बैठकर करते हैं। पास ही कियासरा नाला बहता है। थोड़ी ही दूर पर हनुमान जी का मंदिर है जो पर्वत पर उनकी आकृति उकेर के बनाया गया है। आस्था और विश्वास के इस स्थल पर अक्सर भण्डारों का आयोजन होता रहता है।

डग की यात्रा आपको आत्मबोध कराती है। प्रकृति के समीप ले जाती है और शुद्ध हवा के साथ-साथ अपनी संस्कृति व विरासत को जानने का मौका देती है। ●

सहजना - पैसों का पेड़

आलेख एवं छाया : डॉ. देवदत्त शर्मा

मोरिंगा यानी सहजना और मनीप्लांट यानी पैसों का पेड़। सुनने में पैसों का पेड़ सहजना अपने आप में अनूठा और विस्मयकारी लगता है किन्तु जयपुर जिले के बस्सी कस्बे से चार किलोमीटर दूर दूदली गांव के एक शिक्षित युवक धर्मराज शर्मा ने इसे न केवल सच कर दिखाया है बल्कि वह अन्य बेरोजगार युवकों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बना हुआ है।

दूदली गांव में 5 सितम्बर, 1981 को जन्मे धर्मराज शर्मा ने अपनी प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण कर बी.एससी. की और जीविकोपार्जन के लिए सीमेंट कम्पनी में काम करना शुरू कर दिया। उन्हें सीमेन्ट कम्पनी की तरफ से दक्षिण अफ्रीका जाने का अवसर मिला। दक्षिण अफ्रीका में मोरिंगा का उत्पादन बहुतायत से होता है। उस फेस्टीवल को देखकर धर्मराज की आंखें खुल गईं। मोरिंगा की न जाने कितनी-कितनी किस्में और उससे बने कितने-कितने उत्पाद। उन्हें देखकर वह चमत्कृत हो उठा और उसके मन में तत्क्षण ही एक विचार कौंधा कि क्यों न मोरिंगा की खेती की जाए। नई दिशा और नई क्रांति की उमंग से अभिभूत होकर वह एक बार फिर अपने खर्चे से दक्षिण अफ्रीका गया और मोरिंगा के सम्बन्ध में गहन एवं विस्तृत जानकारी प्राप्त कर अपने गांव में अपनी कल्पनाओं को मूर्त रूप देने का संकल्प लिया।

धुन के धनी धर्मराज ने मोरिंगा की खेती करने, उत्पादन और उसके विपणन की कार्ययोजना तैयार की। सबसे पहले उसने कालाडेरा के पास डीडवाना तथा अपनी बहिनों के खेतों में सहजने के पेड़ लगवाये। अंत में उसने अपने खेत की ढाई बीघा में सहजने के पेड़ लगवाये। इस प्रकार उसने कुल पच्चीस हजार सहजने के पेड़ लगाये।

सहजना मोरिंगेसी कुल का पेड़ है तथा लगभग पूरे भारत में पाया जाता है। मध्यम आकार के इस पतझड़ी पेड़ के लिए रेतीली दोमट मिट्टी अधिक अनुकूल रहती है। इसके हल्के पीले-सफेद रंग के फूल गुच्छों में आते हैं तथा हरे रंग की धारीदार फली आती है जो डेढ़ से ढाई फीट तक लम्बी होती है। इसके फूल, पत्तियां, फलियां, छाल और गोंद अनेक प्रकार की बीमारियों की चिकित्सा में काम आते हैं।

इसकी पत्तियों, फूलों और गोंद से बने पाउडर में संतरे से सात गुना विटामिन-सी तथा गाजर से दोगुना विटामिन-ए होता है। दूध से सत्रह गुना अधिक कैल्सियम और केले से पंद्रह गुना अधिक पोटेशियम मिलता है। इसमें पालक से पच्चीस गुना अधिक आयरन, दही से नौ गुना अधिक प्रोटीन तथा काले चने से आठ गुना अधिक मैग्नीशियम होता है। इसमें बानवें प्रकार के एंटी-ऑक्सीडेन्ट और इनफ्लामेंट पाये जाते हैं। इसी प्रकार इसमें छियालीस प्रकार के एक्टिव एसिड पाये जाते हैं।

इसकी पत्तियों, फूलों और फलियों की सब्जी बनती है। इसके पत्तों

का जूस तथा फूलों की खीर भी बनती है। फूलों की पकौड़ी तथा फलियों का सूप बनता है। इसके लगातार सेवन से जोड़ों का दर्द, पुराना सिर दर्द समाप्त हो जाता है तथा स्त्रियों में खून की कमी दूर हो जाती है।

पहले वर्ष प्रति पेड़ दस किलो तथा दूसरे वर्ष से करीब बीस किलो फलियां मिल जाती हैं जो बाजार में दस रुपये से लेकर पचास रुपये प्रति किलो आसानी से बिक जाती हैं। इसी प्रकार इसके सूखे पत्ते (छाया में सुखाये हुए) साठ रुपये से लेकर एक सौ बीस रुपये प्रति किलो तक बिक जाते हैं। इस प्रकार एक बीघा जमीन में कम से कम पचास हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक की आमदनी प्रतिवर्ष आसानी से ली जा सकती है।

इसमें सिंचाई के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती। एक बार लगाने के बाद सात वर्ष तक अच्छा फल देता है। इस प्रकार वे साल भर इस पेड़ से पैसा कमाते रहते हैं और उसे पैसों का पेड़ के नाम से सार्थक करते हैं।

धर्मराज शर्मा खेती में रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग के सख्त विरोधी तथा जैविक खेती के प्रबल पक्षधर हैं। वे जैविक खाद का प्रयोग करते हैं तथा पेड़-पौधों की पत्तियों से तैयार किये गये कीटनाशक दवा का छिड़काव करते हैं। वे जैविक खेती से गेहूं, दाल, चावल, मसाले, फल तथा सब्जियां उगाते हैं और उसका विपणन करते हैं। वे अपने जैविक उत्पादों की गुणवत्ता की गारंटी देते हैं तथा अपने क्षेत्र में जैविक खेती के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं। इतना ही नहीं उन्होंने आटे की गुणवत्ता कायम रखने के लिए जोधपुर से पत्थर की हाथ चक्की मंगवाकर लोगों को दिलाई हैं। वे जैविक पशु आहार और सूखी सब्जियां तैयार करने की योजना पर भी कार्य कर रहे हैं।

प्रवासी राजस्थानियों से संवाद

माटी से बढ़े जुड़ाव

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राजस्थान सरकार का संकल्प और प्रयास है कि दुनिया के अलग-अलग देशों में रह रहे प्रवासी राजस्थानियों का अपनी माटी के साथ जुड़ाव बना रहे। इस उद्देश्य के लिए 20 वर्ष पहले राजस्थान फाउण्डेशन का गठन किया गया था और सरकार इसके माध्यम से प्रवासियों के साथ बॉन्डिंग को मजबूत बना रही है।

श्री गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रवासी राजस्थानियों के साथ संवाद के दौरान कहा कि विदेश में रहने वालों का अपने प्रांत के साथ अपनापन बढ़ाने में राजस्थानी भाषा का बड़ा योगदान है। राज्य सरकार राजस्थानी भाषा के विकास और उसको मान्यता दिलाने के लिए कृतसंकल्प है। मुख्यमंत्री ने प्रवासियों को विश्वास दिलाया कि राजस्थान में रहने वाले उनके परिजनों को महामारी में किसी तरह की परेशानी होती है तो वे राज्य सरकार को जिस भी स्तर पर सूचित करेंगे, उनकी तुरंत मदद की जाएगी। उन्होंने कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा किये गये प्रयासों की जानकारी देते हुए कहा कि भारत में अन्य देशों के मुकाबले तुलनात्मक रूप से बेहतर काम हुआ है। इसी कारण देश में संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है। देश के अन्य राज्यों के मुकाबले राजस्थान में समय रहते कई उपाय किये गये, जिसके चलते यहां संक्रमण की दर कम तथा रिकवरी प्रतिशत अधिक है। दुनिया के 50 देशों में 90 से अधिक जगहों पर रह रहे प्रवासी राजस्थानियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री से संवाद किया।

मुख्यमंत्री ने प्रवासियों से हुए संवाद में राजस्थानी भाषा में धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा, 'महिलाओं रै कारण राजस्थानी कायम रैयी है। राजस्थानी री मान्यता रे वास्ते सबसूं पैला इण सरकार रै टेम ही विधानसभा में प्रस्ताव पास करिज्यौ। उम्मीद करां, केन्द्र सरकार इणनै 8वीं अनुसूची में जल्दी भेळसी।'

उन्होंने राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के लिए किये जा रहे प्रयासों की सराहना की और इस लड़ाई में राज्य सरकार के माध्यम से प्रदेशवासियों की मदद की पेशकश भी की। कॉन्फ्रेंस के दौरान कई प्रवासी उद्यमियों ने कोरोना संकट एवं लॉकडाउन के बाद प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए भी महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये। उन्होंने युवाओं के लिए कौशल विकास, राजस्थानी संस्कृति और खान-पान की विदेशों में ब्रान्डिंग एवं पैकेजिंग, नये उद्यमियों को तकनीकी दक्षता उपलब्ध कराने में मदद के प्रस्ताव दिये। साथ ही विभिन्न देशों में गठित प्रवासी राजस्थानियों के संगठनों एवं औद्योगिक फोरम आदि के माध्यम से मुख्यमंत्री, मंत्रियों तथा राज्य सरकार के अन्य प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को अपने यहां आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि विश्व के बदले हुए आर्थिक हालात में विभिन्न देशों के निवेशकों के साथ बैठक कर राजस्थान में निवेश के लिए प्रस्ताव दिये जा सकते हैं।

उद्योग मंत्री श्री परसादी लाल मीणा ने प्रवासियों द्वारा दिये गये सुझाव पर राज्य सरकार की ओर से सकारात्मक सोच के साथ विचार करने का आश्वासन दिया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कोरोना से निपटने के लिए राजस्थान द्वारा किए गए प्रयासों की जानकारी दी। कॉन्फ्रेंस के अन्त में राजस्थान फाउण्डेशन के आयुक्त श्री धीरज श्रीवास्तव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस का संचालन किया। इस दौरान मुख्य सचिव श्री डी.बी. गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग) श्री सुबोध अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) श्री रोहित कुमार सिंह, जनसम्पर्क आयुक्त श्री महेन्द्र सोनी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

Postal Regd. No. Jaipur City/413/2020-22
Registered with Registrar of Newspapers of India under R. No. 56175/1991

धरोहर

ऊषा रानी हूजा की कलाकृति 'डॉक्टर, माँ और बच्चा'

सवाई मानसिंह अस्पताल देश के प्रमुख सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों में से एक है। जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह, द्वितीय के नाम पर इसके भवन का निर्माण 1934 में शुरू हुआ और बाद में आवश्यकतानुसार निरतर इसमें विस्तार होता रहा। सवाई मानसिंह अस्पताल प्रांगण में स्थापित 'डॉक्टर, माँ और बच्चा' सुप्रसिद्ध कलाकार ऊषा रानी हूजा द्वारा सिरजी सुंदर कलाकृति है। चिकित्सक-मरीज के मानवीय संबंधों की संवेदनशीलता का विरल सौंदर्य सहेजे यह कलाकृति भारतीय कला का अप्रतिम उदाहरण है।

18 मई, 1923 को जन्मी ऊषा रानी हूजा राजस्थान ही नहीं देश की प्रमुख शिल्पी थी। गत्यात्मक प्रवाह, भाव संवेदनाओं की अनूठी व्यंजना और अनगढ़ सौंदर्य की उनकी शिल्प सर्जना देश-विदेश की कलादीर्घाओं के साथ ही अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली, एयरपोर्ट सर्किल, कोटा, जावर माइन्स, उदयपुर के साथ ही वाशिंगटन, स्वीडन, फिजी आदि देशों में भी प्रदर्शित है। धातु और विभिन्न अन्य माध्यमों में सिरजी उनकी कलाकृतियां सांगीतिक आस्वाद कराती जीवनगत सौंदर्य का एक तरह से गान है। शिल्प सृजन के साथ वह कविताएं भी लिखती थी। उनका अंग्रेजी काव्य संग्रह 'सौंग एण्ड स्कल्पचर' भी प्रकाशित है। ऊषा रानी हूजा को राजस्थान श्री, राजस्थान ललित कला अकादमी फैलोशिप, मेवाड़ फाउण्डेशन आदि सम्मान भी निरंतर मिलते रहे हैं।

आलेख एवं छाया चित्र : अजय सोलोमन

प्रकाशक व मुद्रक - सूचना एवं जनसम्पर्क आयुक्त, महेन्द्र सोनी द्वारा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के लिए, शासन सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) से प्रकाशित
सम्पादक- डॉ. राजेश कुमार व्यास • मैसर्स पॉपुलर प्रिन्टर्स, मोती डूंगरी रोड, जयपुर से मुद्रित, 'राजस्थान सुजस'-पृष्ठ संख्या 60, मूल्य 20 रुपये/ 60,000 प्रतियां